खण्ड-07 सत्र-04 (भाग-3) अंक-46

बृहस्पतिवार 17 अगस्त, 2023 / 26 श्रावण, 1945 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-04 में अंक 45 से अंक 47 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-4 (भाग-3) बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023/26 श्रावण, 1945 (शक) अंक-46

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	4–46
3.	याचिका समिति का चौथा अंतरिम प्रतिवेदन एवं उस पर चर्चा	47–135
4.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)	136–195

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 (भाग-3) बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023/26 श्रावण, 1945 (शक) अंक-46

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.10 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1 श्री अजेश यादव

2 श्री अखिलेशपति त्रिपाठी

3 श्रीमती ए. धनवंती चंदीला ए.

4. श्री अजय दत्त

5. श्री अमानतुल्ला खान

6. श्री अब्दुल रहमान

7. श्रीमती बंदना कुमारी

8. सुश्री भावना गौड़

9. श्री बी एस जून

10. श्री धर्मपाल लाकड़ा

11. श्री दिनेश मोहनिया

12. श्री दुर्गेश कुमार

13. श्री हाजी युनूस

14. श्री जय भगवान

15. श्री जरनैल सिंह

16. श्री करतार सिंह तंवर

17. श्री कुलदीप कुमार

18. श्री मुकेश अहलावत

19. श्री मदन लाल

20. श्री नरेश यादव

21. श्री पवन शर्मा
22. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
23. श्री प्रलाद सिंह साहनी
24. श्री प्रवीण कुमार
25. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
26. श्री प्रकाश जारवाल
27. श्री रघुविंदर शौकीन
28. श्री राजेश गुप्ता
29. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
30. श्री रोहित कुमार
31. श्री शरद कुमार चौहान
32. श्री संजीव झा
33. श्री सोमदत्त
34. श्री शिवचरण गोयल
35. श्री सोमनाथ भारती
36. श्री सही राम
37. श्री एस के बग्गा
38. श्री विनय मिश्रा
39. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
40. श्री अभय वर्मा
41. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
42. श्री अजय कुमार महावर
43. श्री जितेंद्र महाजन
44. श्री महेंद्र गोयल
45. श्री महेन्द्र यादव
46. श्री मोहन सिंह बिष्ट
47. श्री ओमप्रकाश शर्मा
48. श्री ऋतुराज गोविंद
49. श्री राजेन्द्रपाल गौतम
50. श्री राजेश ऋषि
51. श्री सुरेंद्र कुमार
52. श्री विजेंद्र गुप्ता
53. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 (भाग-3) बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023/26 श्रावण, 1945 (शक) अंक-46

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.10 बजे समवेत हुआ ।

माननीया उपाध्यक्ष (श्रीमती राखी बिरला) पीठासीन हुईं ।

माननीया अध्यक्षः 280, श्री जरनैल सिंह जी।

श्री बी एस जूनः अध्यक्ष जी बस एक मिनट।

माननीया अध्यक्षः मैं आपको समय दूंगी, बैठिए। मैं समय दूंगी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैडम जी, ये एलओबी रिवाईज्ड है। कल 11 बज कर 21 मिनट पर अपलोड हुई है हाउस शुरू होने के बाद और आज अभी तक आई नहीं है अगर कोई रिवाईज्ड है तो, तो हमारा ये कहना है कि अगर रिवाईज्ड एलओबी इतना लेट मैम्बर्स को मिलेगी तो हम तैयारी कब करेंगे फिर।

माननीया अध्यक्षः ठीक है, मैं इस पर ध्यान देती हूं। यहां पर जो है बात करती हूं सैक्रेट्री महोदय से। बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, इसमें मतलब अध्यक्ष महोदया ये..

माननीया अध्यक्षः आपका विषय आ गया। मैंने संज्ञान ले लिया। अब आप ये सोचें कि मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी कर दूं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः आप.. मतलब हाउस शुरू होने के बाद डिस्कशन पर वो लगाते हो आप आईटम।

माननीया अध्यक्षः आपने एक बात नोटिस में ला दी। सदन पटल पर रख दी है तो उस पर विचार तो किया ही जायेगा ना। ये थोडे ना है आपने कोई सवाल कर दिया मैं तुरन्त जवाब दे दूं। जरनैल सिंह जी।..मना नहीं किया जवाब देने के लिए। मैंने मना नहीं किया हैजवाब देने के लिए। मैंने बोला है मैं संज्ञान लूंगी। जरनैल सिंह जी। (अनुपस्थित)। संजीव झा।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चूंकि मेरी जो विधान सभा है वो अन-ऑथोराईज्ड कालोनी से बसा हुआ विधान सभा है। 90 परसेंट जो कालोनियां हैं वो अन-ऑथोराईज्ड हैं चूंकि वो एग्रीकल्चर लैंड पर बसा हुआ कालोनी है। अब अचानक डीडीए इन सभी कालोनियों में जो लोग मकान बना रहे हैं उस पर नोटिस दिये जा रहा है, उसको तोड़ा

जा रहा है। विडम्बना ये है कि अभी डीडीए ने रजिस्ट्री भी अलाऊ कर दी। लोग अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करा लेते हैं। रजिस्ट्री के बावजूद बहुत सारी जगह पर डीडीए डिमोलिशन कर रहा है। अभी हमारे यहां केशव नगर एक कालोनी है। केशव नगर कालोनी में डीडीए ने डिमोलिशन का ड्राईव चलाया और 2013, 2014, 2015 में जो मकान बनें, चूंकि जब डीडीए रजिस्ट्री कर रही थी तब उन्होंने कहा कि 2015 से पहले जितनी भी जगह पर अन–ऑथोराईज्ड कालोनी बस गई है वो वैद्य कालोनी हैं और उसी के बेसिज पर वो रजिस्ट्री अलाऊ भी कर रहे हैं। जो conveyance deed जिसको कहते हैं वो दे रहे हैं। लेकिन conveyance deed होने के बावजूद डिमोलिशन ड्राईव किया गया। हमारे यहां एक व्यक्ति आर्मी में था, कारगिल वार लड़ा था। वो रिटायर्ड हो करके आया। अपने गावं में जमीन बेचकर के आया। यहां जमीन खरीदा और मकान बनाया और उसके मकान को डिमोलिश कर दिया गया। अब ऐसे लोग जो इतनी अपनी hard earned money जो हमेशा देश की सेवा करते रहे वो अपना मकान भी नहीं बचा सकता। जहां रह रहा है वो सुरक्षित नहीं है तो फिर ऐसे में क्या किया जाये समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से हमारी रेवेन्यू मिनिस्टर को भी और आपके माध्यम से डीडीए के ऑफिसर्स को भी मैं आगाह करता हूं। मैं ये मानता हूं कि नई अन–ऑथोराईज्ड कालोनी नहीं बसनी चाहिएं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। लेकिन नई जब कालोनी बसती है, उसको रोका नहीं जाता और जो पुरानी बसी

हुई है उसको तोड़ा जाता है। तो सबको साफ समझ में आता है कि नई कालोनी कैसे बस रही है और पुरानी कॉलोनी क्यूं तोड़ी जा रही है। तो मसला तो लीगल-इलिगल का नहीं है, मसला फिर उसमें करप्शन का भी है। तो आपके माध्यम से मैं एलजी साहब को भी ये निवेदन करता हूं कि वो, ये तो उनके अधीन विषय है, उनका सब्जैक्ट है। कई बार वो अपने सब्जैक्ट को छोड करके दूसरे सब्जैक्ट की बात करते हैं, अपने सब्जैक्ट पर बात नहीं करते और मैने ये बात एलजी साहब को मिल करके बताई थी। चूंकि आज तो बहुत डेवलप हो गया है। टैक्नोलोजी एआई का समय आ गया है। हम कहते हैं जितने भी वैकेंट लैंड है, आप ड्रोन से उसका मैप ले लीजिए उसको रेड जोन बना दीजिए ताकि कन्स्ट्रक्शन ना हो। चूंकि जब कन्स्ट्रक्शन होता है, शुरू में तो गरीब लोग मकान ले लेते हैं और फिर गरीब का घर उजड़ता है। तो इस तरह से गरीबी किसी के लिए अभिशाप ना हो, हम सरकार या जो भी ऑथोरिटी जिसके पास ये शक्ति है वो अपनी शक्ति का दुरूपयोग ना करें, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद डीडीए कोई एक प्रक्रिया बनाये जिससे नई कालोनी ना बसे, लेकिन जो लोग बसे बसाये हैं, 2015, 2010, 2005 में जिन लोगों ने मकान बना लिया उनके साथ इस तरह का बर्ताव ना किया जाये। ये ही मैं निवेदन कर रहा हूं।

माननीया अध्यक्षः जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः थैंक्यू, स्पीकर मैडम। अध्यक्षा महोदया, दिल्ली के प्राईवेट स्कूल्स में ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, जिसमें ईडब्ल्यूएस से सम्बन्धित परिवार के बच्चों को दाखिला दिया जाता है ड्रॉ होता है और मेरे को इस बात की खुशी है कि पिछले आठ दस साल में जो पहले एडमिशन नहीं हो पाते थे ईडब्ल्यूएस के बच्चों के अब वो हो रहे हैं पर अभी भी उसमें कुछ गुंजाईश बची है। लगातार इन पिछले कुछ दिनों से हमारे दफ्तरों में बहुत सारे पेरेंटस आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा ईडब्ल्यूएस में नतीजा आने के बाद भी, ड्रॉ में नाम आने के बाद भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इसके सम्बन्धा में डीडीई को लिखित शिकायत देने के बाद भी कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं हुई तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री कोई ऐसा प्रोविजन करें जिससे जितने भी ईडब्ल्यूएस के नतीजे निकाले गए हैं, इन्श्योर किया जाए कि उन सबके एडमिशन हो जाए और जो नहीं हुए उनको immediately कोई अल्टरनेट स्कूल दिया जाए ताकि समय ना निकले। किया क्या जाता है प्राइवेट स्कूलों द्वारा, कुछ प्राईवेट स्कूलों द्वारा कि जानबूझ कर बच्चों को डिले किया जाता है। तीन बच्चे जनरल के आयेंगे तो एक बच्चा ईडब्ल्यूएस का लेंगे। ऐसा कर करके कई बारी वो परिवार जिनका नाम ड्रॉ में आया होता है वो मजबूरी में किसी दूसरे स्कूल में जाकर एडमिशन ले लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी वो सीट वैकेंट रह जाती है। तो एजूकेशन डिपार्टमेंट कोई पुख्ता इस चीज का अरेंजमेंट करें जिससे इन सभी बच्चों के एडमिशन हो जाएं। थैंक्यू स्पीकर मैडम।

माननीया अध्यक्षः राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष महोदया जी आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान दिल्ली में चल रहे कोचिंग इन्सटीच्यूट, ओयो होटल्स, पीजी चल रहे है उनका और प्राईवेट होस्पिट्ल्स, मैं इनकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं क्योंकि इन सभी में से मैक्सिमम में कोई भी फायर क्लेरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। अधिकतम के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन एमसीडी इनको धड़ाधड़ नोटिस भेज रही है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा मुखर्जी नगर के अंदर दुर्घटना हुईं एक-एक कमरे में पांच-पांच सौ बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है। फिर आग लगने पर कैसे भगदड़ मचती है। बड़ी मुश्किल से लोगों की जानें बची। ऐसे ही एक जनकपुरी में हुआ था ए-। ब्लॉक के अंदर एक बहुत बड़ा पीजी खुला हुआ था। उसके अंदर आग लगी और बच्चियों को खिड़कियों से कूदकर, फस्ट फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी जान बचानी पड़ी। समझ में नहीं आता कि एमसीडी इनको लाईसेंस कैसे दे देती है। अभी हाल ही में एमसीडी ने सब कोचिंग इन्सटीच्यूट्स को नोटिस जारी किये हैं। मेरे जनकपुरी में बहुत कोचिंग इन्सटीच्यूट हैं और एक-एक रूम के अंदर पांच-पांच सौ, सात सौ बच्चे इक्कट्ठे पढ़ते हैं। एक तो ऐसा इन्सटीच्यूट अभी बन रहा है और अभी कच्ची, बनती हुई बिल्डिंग के अंदर भी पढ़ाई चल रही है। एमसीडी उसको रोक नहीं रही। इसकी हमने शिकायत भी की उनको। एमसीडी ने अभी नोटिस

जारी किये। नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांग रहे है। हमें ये पूछना चाहिए कि आप जवाब क्यों मांग रहे हो, आप ने कैसे इनको लाईसेंस दे दिये चलाने के लिए, आपने इसके अंदर क्यों नहीं देखा कि फायर का क्लरेंस है कि नहीं है? लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये नोटिस के बाद अपने इनके आदमी जाते हैं, उनके साथ सैटेलमेंट कर रहे हैं, नहीं तो उनको सीलिंग की धामकी दे रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूं कि हमारे जो होस्पिट्ल्स हैं। हमने कई हॉस्पिट्ल्स ऐसे देखें जो चल रहे हैं, जिसके अंदर चलने का रास्ता नहीं है, उसमें stature भी लेकर जाते हैं। उसके अंदर स्थिति ऐसी है और फायर का सर्टिफिकेट नाम की तो चीज ही नहीं है। गली–गली के अंदर इन्सटीच्यूट खुले हुए हैं। गली–गली के अंदर हॉस्पिट्ल्स खुले हुए हैं। अब फायर का जब क्लरेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो ये खुल कैसे गए? एमसीडी के भ्रष्टाचार के कारण ही ये खुल गए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप एक ऐसी कमेटी बनाये जो इनकी जानकारी ले कि ये कैसे इन्होंने नोटिस जारी किये। नोटिस जारी करने का कारण क्या रहा और अगर इन्होंने नोटिस जारी किये है तो इन्होंने पहले इनको लाईसेंस कैसे जारी कर दिये बिना फायर क्लियरेंस के। ये एक मोटा भ्रष्टाचार होना शुरू हो गया है। ओयो होटल्स की तो सब हमारे विधायक जानते हैं कि वो होटल्स क्यों खुले हुए हैं। वहां पर गलत काम होते हैं लेकिन उनको रोका नहीं जाता। और उनके पास भी कोई फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। वो भी धड़ल्ले से चल

रहे हैं। पीजी धड़ल्ले से चल रहे हैं। और तो और पीजी के अंदर कॉमर्शियल यूजेज हो रहे हैं और साथ ही ना तो वो कॉमर्शियल का बिल देते हैं, ना कॉमर्शियल पानी का बिल देते हैं। इस तरीके से हमारा जो धनोर्जन होना है वो भी नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे ये ही प्रार्थना करूंगा कि आप एक कमेटी बनाये जो कमेटी इस भ्रष्टाचार के ऊपर कंट्रोल करे और देखें कि लाइसेंस, जो नोटिस दिये गए उसमें कितना भ्रष्टाचार करके ये लोग उनको रोक रहे हैं और किन-किनको इन्होंने सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा और किन-किनको मिले हैं। क्योंकि फायर सर्विसेज के पास इतना infrastructure नहीं है कि वो जा-जाकर सबको दे। मैने कई बार फायर वालों को लिखकर भेजा तो उन्होंने मेरे को तीन लिस्ट दी। अभी मेरे यहां भी एक माता चाननदेवी होस्पिटल है, उसमें जनरल वार्ड में आग लग गईं तो हम भी भागे-भागे पहुंचे लेकिन उनका फायर का सिस्टम इतना बढ़िया लगा हुआ था और डाक्टर्स ने पूरी मेहनत के साथ सबको सेफ बचा लिया बच्चों को। और इनके पास सर्टिफिकेट वी था। फायर वाले आये, उन्होंने उन पर फाईन भी किया, सब कुछ किया लेकिन अगर इस तरीके से हमारे सभी प्राईवेट होस्पिटल्स के अंदर क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो उसके अनुसार काम करते हैं तो इससे हमारी जानमाल की हानि बचेगी और मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं कमेटी बनाकर इसकी जांच करायें और जनता को न्याय दिलवायें। जय हिन्द।

माननीया अध्यक्षः अजय महावर जी।

श्री अजय कुमार महावरः धन्यवाद, आदरणीय अध्यक्षा महोदया जी। मैं आपके माध्यम से फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट जो जल बोर्ड के अन्तर्गत आता है, जल मंत्री जी महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी घोंडा विधान सभा में दो गांव हैं, गढ़ी मेन्दू गांव और उस्मानपुर गांव जो फ्लड जोन में आता है। यदा-कदा वहां बाढ़ भी आती है और इस बार भी वहां बाढ़ पूरी तरह से आईं लेकिन वहां हजारों जिन्दगियां, हजारों मकान बने हुए है। 2013 के बाद से जो जिंदगी की मूलभूत आवश्यकता होती है बिजली और पानी दोनों का कनैक्शन वहां दस वर्षो से नहीं दिया जा रहा है, बंद कर दिया गया है। कहा गया है कि वो 'ओ' जोन इलाका आता है। 'ओ' जोन के कारण वहां पर हम बिजली और पानी नहीं दे सकते। लेकिन हजारों जिंदगियां जो वहां रह रही हैं, जहां एक तरफ मानवीय संवेदनायें ये हैं कि हम एक छोटी सी चींटी की भी जिंदगी की परवाह करते हैं। तो वहां रह रहे हजारों लोगों की परवाह हम क्यों नहीं कर पा रहे, मूल भूत सुविधाएं हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए वहां बिजली और पानी दोनों उनको मिलना चाहिए। सरकार को मेरा एक सुझाव है कि हमारा एक करतार नगर का पुस्ता है और पुस्ता के साथ ही ये सटे हुए दोनों गावं हैं और बहुत दूर कम से कम दो किलोमीटर जा करके यमुना जी हैं। लेकिन यमुना खादर कहलाने के कारण ही वहां पर और कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो करावल नगर की जो पुस्ता है वो करतार नगर की पुस्ता के साथ खजूरी चौक से आगे जाती

है। सोनिया विहार का पुस्ता बनाया गया था जिसके बारे में कल आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी भी जिक्र कर रहे थे एक मीटर ऊपर करने का तो सोनिया विहार के पुस्ते की तर्ज पर यदि हम वजीराबाद से शास्त्री पार्क रोड तक एक पुस्ता का निर्माण कर दें, मार्जिनल बांध का निर्माण कर दें तो ये दोनों गांवों की जिंदगियां बच जायेगीं, उनको मूलभूत सुविधाएं मिल जायेगी और यमुना जी और इन गांवों के बीच में फोरेस्ट का इलाका भी है जहां अनेक जीव जन्तु भी रहते हैं। नील गाय हैं, हिरण हैं और भी कई प्रकार के वहां पर छः छः फुट के बाड़े बनाये हुए गए हैं तो उन जीवों की भी रक्षा हो पायेगी। तो इसलिए एक मैं मंत्री जी से आज करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि एक नये पुस्ते का निर्माण जो लगभग साढे तीन से चार किलोमीटर का ये पूरा है वो उसके बीच में किया जाए जिससे लोगों को राहत मिले, गांव भी बचे, पशु भी बचे और लोगों की जिन्दगियों को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधा मिल जाए।

जब तक ये बांध ना बने तब तक कम से कम बिजली और पानी दो मूलभूत सुविधा जरूर दी जाये जिससे हज़ारों लोगों को इससे लाभ मिल सके उनकी जिंदगियों को आराम मिल सके, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः मुकेश अहलावत जी।

श्री मुकेश अहलावतः अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष

महोदया, मेरी विधानसभा में एक पुल बन रहा है और उस पुल को बनते हुये 12 साल हो गये और 12 साल में आप सोच सकते हो जो पुल बन रहा है तो वहां पर दुकानदारों की क्या हालत हो रही होगी और वहां पर जो आने-जाने का रास्ता है वो भी सारा ठप्प हो गया है और वहां पर जितने लोग रहते थे वो भी लोगों ने अपने-अपने घर भी बदल लिये हैं क्योंकि वो पुल ही नहीं बन पा रहा है। अब उस पुल के कारण क्या दिक्कत है कि वो पुलएमसीडी वाले और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर बना रही हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है और यहां के फाइनांस मिनिस्टर से भी और हमारे जो एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश भाई से भी प्रार्थना है कि दोनों एक बार ज्वांइट मीटिंग रख लें, जो भी इश्यू है उसको क्लीयर करके उस पुल को निर्माण कराया जाये क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत है और उसको फंड रिलीज़ करवाया जाये। वहां पर क्या-क्या दिक्कत है, जो कानून की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करवाई जाये, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविंदः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। मैं एक ऐसी कॉन्सिटीट्वेंसी को रिप्रेसेन्ट करता हूं अध्यक्ष महोदय जहां पर लगभग 8 लाख की आबादी है और हैल्थ सर्विसिज़ लगभग ज़ीरो है जिसको देखते हुये हम लोगों ने बहुत मेहनत करके डीडीए से ज़मीन लिया हॉस्पिटल के लिये और हॉस्टिपल का एलॉट्मेंट होता है 10 फरवरी, 2021 को और उस

वक्त कोविड का जो फ्र्स्ट फेज़ है वो खत्म हुआ था और जो डेल्टा है जो सैकेंड फेज़ है वो लगभग मार्च-अप्रैल में शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को ज़मीन का पजैशन होता है और 28 जुलाई, 2021 को जो कि कंसीडर ये किया जाता है कि बहुत फास्ट प्रोसेस था और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मंत्री सत्येन्द्र जैन जी का जिन्होंने इसको इतना स्पीड्ली करवाया, टेंडर पब्लिश हो जाता है 28 जूलाई, 2021 को जबकि पोजैशन हुआ है 6 अप्रैल, 2021 में, कुछ ही महीनों के अंदर में इसका टेंडर तक हो जाता है सारी प्रक्रिया करने के बाद और उसके बाद 11 अगस्त को बिड की ओपनिंग होती है और काम शुरू हो जाता है सितम्बर 2021 में और आप यकीन नहीं करेंगे, 2021 सितम्बर में काम शुरू होता है जबकि किराड़ी एक ऐसी कॉन्सिटीट्वेंसी है जहां हॉस्पिटल की सबसे ज्यादा जरूरत है। 8 लाख की आबादी हमारी खुद की और आस-पास में भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारे सारे लोग संजय गांधी जाते हैं और संजय गांधी दिल्ली का सबसे खराब अस्पताल केवल इसलिये है क्योंकि वहां पर उसकी कैपेसिटी से 50 गुना ज्यादा मरीज आते हैं। सरकारी हॉस्पिटल किसको चाहिये? गरीब आदमी को चाहिये। गरीब आदमी कहां रहता है? झुग्गी-झोंपड़ी में और अनॉथराइज़ कॉलोनी में रहता है सफल्तानपुरी, मंगोलपुरी, किराड़ी, बवाना की झुग्गियों में रहता है। लेकिन हैल्थ सर्विसिज़ के नाम पर संजय गांधी की हालत तो खराब ही है लेकिन हमारे हॉस्पिटल को लेकर के ये बहाना बनाया गया कि नीचे water table बहुत ऊपर

है। तो सरकार ये निर्णय करती है कि उसके अंदर में हम pile formation से बिल्डिंग बनायेंगे। उस निर्णय को हुये भी दो साल हो गये, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का पूरा डैलिगेशन जाता है नौटंकी करने के लिये जिसमें कुछ सांसद भी थे, खूब नोटंकी होती है, खूब ड्रामेबाजी होती है। मैं हैल्थ सेक्रेटरी से मिलता हूं, मैं हर किसी से मिलता हूं लेकिन केवल तारीख मिलता है, केवल आश्वासन मिलता है लेकिन काम आज तक शुरू नहीं हुआ है। उस काम को अवार्ड हुये भी कम से कम ढाई साल हो चुका है। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रॉब्लम है क्या, ऐसी क्या परेशानी है किराड़ी के अंदर हॉस्पिटल बनाने के लिये? हमारे गरीब प्रवासी लोग क्यों धक्के खायेंगे कहीं पर? हमारे आस–पास कोई हैल्थ सर्विस नहीं है और गर्वमेंट हॉस्पिटल की जरूरत गरीब लोगों को होती है। तो मैं इस सदन के माध्यम से हैल्थ मिनिस्टर जी का भी ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं और सरकार का भी ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि पेशेन्स की हद होती है। हमें हॉस्पिटल की जरूरत है और किराड़ी में हॉस्पिटल बनना चाहिये और यही मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं और मैं कर भी क्या सकता हूं, धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः आदरणीय अध्यक्षा महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की सरकार को वरिष्ठ नागरिकों की अत्यंत विकट स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। नई वृद्धा पेंशन के लिये आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया है। वे

वरिष्ठ नागरिक सरकार को अपनी व्यथा सुनाने के लिये जिसमें अधिक नंबर महिला वरिष्ठ नागरिकों का है ऐसे वरिष्ठ नागरिक दर-दर भटक रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार सामाजिक सुरक्षा का विस्तार ना करके बुजुर्गों के प्रति अपनी उदासीनता ही नहीं अपितु निर्दयता दिखा रही है। दिल्ली सरकार के 75 हज़ार करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का दावा करने वाले बजट में भी वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन के लिये इस वर्ष एक भी नई पेंशन के लिये एक कौड़ी भी नही रखी गई है। वरिष्ठ नागरिकों को नई पेंशन के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। वृद्धावस्था पेंशन के तहत लाभार्थीयों की मृत्यु के कारण भी जो रिक्ततायें हैं उन पर भी लगभग वो रिक्तियां डेढ़ लाख के करीब हैं अंदाजें से ही, 25 परसेंट के करीब क्योंकि 2018 के बाद एक भी नई पेंशन नहीं लगी है। आप 2018 के बाद पेंशन नहीं लगा रहे हैं, उसी दौरान एमसीडी की पेंशन बंद हुई थी कोर्ट के आदेश थे और वो जो लोग एमसीडी से पेंशन लेते थे उनको दिल्ली सरकार से पेंशन लेने का नये सिरे से फार्म भरने का मौका ही नहीं मिला। आप सोचिये उनकी क्या स्थिति होगी। कितने लोगों की दवाई है, कितने लोगों की रोज़ी-रोटी, मान लीजिये एक परिवार में दो बुजुर्ग लोग घर में हैं तो उस पैसे से ही वो अपनी जरूरतें पूरी कर लेते थे लेकिन वो वैकेंसिज़ को सरकार क्यों नहीं भर रही है ये बात बिल्कुल गले नहीं उतर रही है कि जिसका पैसा भी बजट में प्रोविज़न होता है और वो खाली रिक्तियां जो हैं वो भरी जा सकती हैं। मुझे लगता है कि कम से कम एक-एक

एसेंबली में एक-एक हज़ार से ज्यादा नई पेंशन आ सकती हैं बिना नई पेंशन शुरू करे ही। सरकार इसमें पूरी तरह से ये नज़रअंदाज कर रही है, कम से कम वरिष्ठ नागरिकों के लिये सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार को पेंशन के पात्र वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिये एक पेंशन हैल्प डैस्क का गठन करना चाहिये। अभी क्या कहते हैं मैडम जी वो कि वो डिस्ट्रिक में है। अब एक डिस्ट्रिक में कई सारी एसेंबली लगती हैं, अब एक बुजुर्ग वहां तक रिक्शा करके जायेगा या कैसे भी जायेगा, सुबह से शाम हो जायेगी उस हैल्प डैस्क से उसको प्रोपर इन्फोंमेशन भी नहीं मिलेगी और वो तंग अलग होगा, उसकी जान अलग खतरे में पड़ेगी क्योंकि कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 90 साल के लोग भी हैं, तो ये हैल्प डैस्क हर विधानसभा में, मैं समझता हूं कि विधायक कार्यालय में होना चाहिये। पेंशन से संबंधित कोई भी जानकारी है, किसी की. कितने लोगों की पेंशन रूक जाती है, कई-कई महीने पेंशन नहीं आती है। अब वो आधार कार्ड को लिंक करना है, आधार कार्ड से बैंक में वो देना है पता ही नहीं है लोगों को लेकिन वो परेशान होते रहते हैं। सरकार को ये सोचना चाहिये कि महीनों की पेंशन अचानक बंद हो जाने से ना कितने बुजुर्गों की रोटी, दवाई कपड़े और रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के भी टोटे हो जाते हैं। ऐसे मुद्दे को सरकार द्वारा शीघ्र हल किया जाना चाहिये। अब 75 हज़ार करोड़ के बजट में..

माननीया अध्यक्षः अब हो गया लगभग।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, एक मिनट बस। 75 हज़ार करोड़ के बजट में आप ये देखिये कि बुजुर्ग सबसे ज्यादा पूरी तरह से सरकार उनके प्रति उदासीन है। xxx[1]

माननीया अध्यक्षः ये देखो ये कोई तरीका नहीं है आपने ये लिखकर नहीं दिया है प्लीज़ आप बैठिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः नहीं एक मिनट, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिलेगी।

माननीया अध्यक्षः बैठिये आप, समय खराब ना करें प्लीज़ बैठ जायें।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मेरा इतना ही कहना है।

माननीया अध्यक्षः गुप्ता जी समय खराब ना करें आपने जो लिखकर दिया था वो आपने बोल लिया ना।

श्री विजेंद्र गुप्ताः नहीं, मेरा इतना ही कहना है अध्यक्ष महोदय कि आप बाकी सारे काम ..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः एक सैकेंड आप लोगों का बोलना बहुत जरूरी हो जाता है।

---

[1]चिन्हित अंश अध्यक्षा महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

श्री विजेंद्र गुप्ताः xxx[1]

माननीया अध्यक्षः बैठिये, एक तो इनके ये सारे शब्द निकालें बैठिये आप।

श्री विजेंद्र गुप्ताः xxx[1] क्यों निकालना।

माननीया अध्यक्षः जितना आपने लिखकर दिया।

श्री विजेंद्र गुप्ताः क्यों निकालना जी, क्या मैंने गलत बोल दिया।

माननीया अध्यक्षः एक सैकेंड,

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः गलत इसमें क्या है।

माननीया अध्यक्षः इसमें गलत ये है कि 280 के रूल के मुताबिक...

श्री विजेंद्र गुप्ताः तो मैं कम्पेरिज़न बता रहा हूं ना की सरकार के पास पैसा तो है पर बुजुर्गों को नहीं देंगे।

माननीया अध्यक्षः जो आपने लिखकर दिया है, जो आपने लिखकर दिया है मैंने उसे टोका एक बार भी, मैंने टोका क्या? कुलदीप जी।

---

[1]चिन्हित अंश अध्यक्षा महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैंने इतना ही तो, इतना ही तो मैंने कहा है की सरकार के पास पैसा तो है xxx[1] बुजुर्गों को पेंशन देने के लिये पैसा नहीं है।

माननीया अध्यक्षः बैठिये, आप बैठ जाईये, बैठिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः जितना समय दिया जाता है उसमें बात रखिये आप अपनी फालतु इधर-उधर की बातें ना करा करो आप। अब्दुल रहमान जी।

श्री अब्दुल रहमानः अध्यक्षा महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे 280 पर एक अहम् मुद्दे को उठाने का मौका दिया। मेरी विधानसभा में ब्रह्मपुरी रोड़ पर एक गाँधी हरिजन के नाम से स्कूल था मैडम। वो एडिड स्कूल था और अब से लगभग ढाई तीन साल पहले गर्वमेंट ने उसे अपने अंडर ले लिया। मैडम उसकी बिल्डिंग जर्जर हालत में थी तो गर्वमेंट ने उसके बच्चों को शिफ्ट किया पीली बिल्डिंग सीलमपुर जो वहां से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। ढाई साल से बच्चे उस दूसरे स्कूल की बिल्डिंग में छोटी सी जगह में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। 26 करोड़ रुपये की लागत से उस स्कूल की बिल्डिंग के 100 कमरे बनाये जाने थे। 84 कमरों में क्लासरूम और 16 कमरों में ऑफिसिज़ के यूज़ के लिये तो मैडम ढाई साल पहले उसका काम शुरू होने

[1]चिन्हित अंश अध्यक्षा महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

वाला था लेकिन 35-36 पेड़ों को स्थानांतरित किया जाना था उसके आहाते से, वो स्थानांतरित नहीं हो सके इसके कारण वो काम आज तक शुरू नहीं हो सका। उसके बाद में वो टेंडर लैप्स हुआ वो ठेकेदार चला गया छोड़कर, रिटेंडर हुआ उसका। उसको भी एक साल से ज्यादा हो गया लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हो सका और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। अभिभावक हर रोज़ मेरे ऑफिस में आते हैं और 800 मीटर दूर चलकर बच्चे-बच्चियों को जाना पड़ता है तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मैडम कि आप इसमें थोड़ा सा दखलअंदाजी करें अपनी और इस स्कूल की बिल्डिंग को जल्द से जल्द बनवायें ताकि उन बच्चों को राहत मिल सके और बच्चे अच्छे से अपने ही स्कूल में आकर के पढ़ाई कर सकें, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्माः धन्यवाद अध्यक्षा महोदय, 280 के तहत मुझे बोलने का मौका मिला है। आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मैडम लक्ष्मी नगर, विधानसभा में लगभग 15-20 वर्षों से बहुत सारे रोड़ों का निर्माण नहीं हुआ और पिछले तीन सालों में आईजीएल गैस पाइप लाइन लगभग 65 परसेंट घरों में पहुंचाने के कारण रोड़ों को तोड़कर ही इन्टरनल पाइप डाले गये। इस दौरान जल बोर्ड के माध्यम से पानी का पाइप लाइन और सीवर लाइन भी बदलने का काम जोरों से

चला। तीन बार रोड़ कटिंग होने के कारण रोड़ों की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गईं मैंने शहरी विकास मंत्रालय में 2020 में 20 रोड़ों के लिये, 2022 में चार रोड़ों के लिये और 2023 में 6 रोड़ों के लिये। इसी तरह से मुख्यमंत्री Local Body Development में 6 अन्य रोड़ों के लिये फाइलें मैंने जमा कराईं। कुल 33 स्कीम बनाकर मैंने शहरी विकास मंत्रालय में जमा कराया लेकिन आज तक एक रुपया भी इश्यू नहीं हुआ। मंत्रालय से पता करने पर जानकारी आया कि मेरे बाद की फाइलें बहुत सारे एमएलए जो कि आम आदमी पार्टी से हैं उनकी फाइलें पास भी हो गईं, उनके रोड़ के निर्माण भी शुरू हो गये जबकि लक्ष्मी नगर विधानसभा 70 विधानसभाओं में से एक विधानसभा है। दिल्ली सरकार के विकास कार्यों में एक बटा 70वां हिस्सा लक्ष्मी नगर का भी बनता है लेकिन बार-बार पत्र लिखने, बार-बार मंत्री जी से बात करने इवन कि मैंने व्यक्तिगत भी मुलाकात की। उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर दे दीजिये, प्रायोरिटी लिस्ट भी मैंने बनाकर दे दिया लेकिन अभी तक मेरी सभी फाइलें सभी डिपार्टमेंट से पास होकर मंत्री जी के कक्ष में पढ़ा हुआ है। मंत्री जी ना कोई उसका उपयुक्त उत्तर दे रहे हैं जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सदन में आकर कहा था कि लक्ष्मी नगर ही नहीं 70 के 70 विधानसभाओं में रोड़ों के निर्माण तेज़ गति से किये जायेंगे लेकिन ये भेदभावपूर्ण व्यवहार लक्ष्मी नगर विधानसभा के साथ क्यों है? जो लक्ष्मी नगर जनता का हक बनता है वो सरकार को देना चाहिये। मैडम आपके माध्यम से जो फाइलें

मंत्री जी के कक्ष में पड़ा है कोई एक आर्डर कर दें कि हां, नहीं देना, हम जनता को बता देंगे। हम रोज़ जनता को ये कहते रहते हैं कि अरे भाई फाइल मंत्री जी के पास पड़ी हुई है, फाइल मुख्यमंत्री जी के पास पड़ी हुई है और कई आरडब्ल्यूए और एनजीओ चिट्ठी लिख-लिखकर पता लगवाते हैं कि क्या विधायक ने रोड़ बनाने का प्रस्ताव दिया है या नहीं। तो एक बार क्लीयर हो जाएगा कि हम कोई पैसा नहीं देंगे, तो हम भी नीचे अपने जनता को बता देंगे और नहीं, देना है तो दें ताकि डेवलपमेंट तो हो क्योंकि बहुत बुरी स्थिति लक्ष्मी नगर के रोड़ों की है। अगर थोड़ा भी मर्सी हो, थोड़ा भी अगर दिल्ली की जनता के बारे में ठीक सोचते हैं तो रोडों के पैसे आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि क्लीयर हों ताकि हम लक्ष्मी नगर के लोगों की सेवा कर सकें और मैडम पिछले दो मंत्रियों ने भी ऐसे ही फाइलें रोक कर रखी थी। तो मुझे इस बात का बहुत दुख है कि माननीय मंत्री जी से लगातार मिलने के बाद, पत्र लिखने के बाद भी लक्ष्मी नगर विधान सभा के एक रोड के लिए एक रुपया नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत दुःख का विषय है। आपके माध्यम से चाहता हूं कि एक बार इसपर संज्ञान लिया जाए।

माननीया अध्यक्षः श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्रपाल गौतमः धन्यवाद, अध्यक्षा महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय उपसभापति महोदय जी, आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि कल से हम देख रहे हैं कि बेहद खुबसूरती से

आप सदन चला रही हैं और हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है। कहीं कोई शोर शराबा नहीं और बहुत प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ आप सदन चला रही हैं।

माननीया अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्रपाल गौतमः इसी तरह शांति से सदन चले और सब लोग अपनी समस्याएं भी रखें और दिल्ली के लोगों का भला करें। इसी के लिए शायद इस विधान सभा का गठन हुआ है। माननीय अध्यक्षा जी मैं आपका ध्यान और पूरे सदन का और सरकार का ध्यान अपनी विधान सभा में स्थित दो अस्पतालों की दुर्दशा की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरी विधान सभा में टोटल पांच हॉस्पिटल हैं, जिसमें स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, एमसीडी द्वारा चलाया जाता है। ईहबास, जीटीबी हॉस्पिटल, दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल ये चार हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के द्वारा चलाये जाते हैं।

ईहबास और जीटीबी हॉस्पिटल, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इर्हबास में देश के कोने कोने से मरीज ईलाज के लिए आते हैं। जीटीबी के अंदर हरियाणा से राजस्थान से और लगभग आधा यूपी लोग ईलाज के लिए आते हैं। सबका ईलाज हो रहा है। दोनों हॉस्पिटल अच्छे से चल रहे हैं।

लेकिन, मुझे इस बात का बेहद दुख है दो हॉस्पिटल, दिल्ली स्टेट कैंसर इन्स्टिट्यूट और राजीव गांधी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल,

ये दोनों हॉस्पिटल गर्वनिंग बॉडी के द्वारा चलाए जाते हैं और गवर्निंग बॉडी के चैयरमेन हमारे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं और इससे ज्यादा शर्मनाक और दुख की बात कोई हो नहीं सकती। सैकड़ो करोड़ की लागत से ये दोनों हॉस्पिटल बने और इसमें दिल्ली स्टेट कैंसर इन्स्टिट्यूट में जब पहले मैं विजिट करता था जब नया नया विधायक बना था तो मुझे हॉस्पिटल की विजिट करते हुए गर्व महसूस होता था कि न केवल भारत के सभी राज्यों से बल्कि विदेशों से भी कैंसर का ईलाज कराने लोग वहां आते थे, ईलाज करा रहे थे, हम उनसे मिलते थे। लेकिन, आज बेहद शर्मनाक बात ये है कि हमारी अफसरशाही की अकर्मण्यता की वजह से, लापरवाही की वजह से जो करोड़ों रुपए की मशीनें दिल्ली स्टेट कैंसर इन्स्टिट्यूट में लगी है और राजीव गांधी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में लगी हैं, वो मशीनें बंद हो गयी हैं, काम नहीं कर रही है। वहां कोई टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं । मैंने जब वहां विजिट किया, जानने की कोशिश की कि कौन से कारण हैं कि ये करोड़ो की मशीनें जो कैंसर जैसे गंभीर रोग का ईलाज कराने में उपयोगी है, जो हार्ट की बीमारी का या गैस्ट्रो की बीमारी का ईलाज कराने में बेहद उपयोगी हैं, जिसका टेस्ट बाहर कराने के लिए कभी 15-15, 20-20 हजार, 10-10 हजार रुपया खर्च करना पड़ता है, वो मशीनें करोड़ों की लागत से खरीदी गयी, लेकिन चूंकि पहली बात तो दोनों ही अस्पतालों के अंदर लंबे समय से स्थायी तौर पर कोई मेडिकल डायरेक्टर उपलब्धा नहीं हुआ। एक

मेडिकल डायरेक्टर लगाया जाता है। उसी को चाचा नेहरू का एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है, उसी से चार्ज दे दिया जाता है राजीव गांधी सुपर स्पेशिलिटी का, उसी को दे दिया जाता है दिल्ली कैंसर का। अब एक डायरेक्टर तीनों हॉस्पिटल को मैनेज नहीं कर पा रहा। वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। मतलब लगभग पूरा प्रशासनिक ढांचा धवस्त हो गया और उसका एक और नुकसान एक वजह से और हुआ कि जो अकाउंट ऑफिसर होता है, राजीव गांधी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में लंबे समय से कोई अकाउंट आफिसर ही नहीं हैं।

दिल्ली स्टेट कैंसर इन्स्टिट्यूट के अकाउंट आफिसर पर एडिशनल चार्ज है। अकाउंट आफिसर यहां के बिल को पूरी फाइल को चैक करके क्लीयर नहीं कर रहा, फिर बिल जमा नहीं हो रहे जिसकी वजह से पिछले लगभग दो साल के बिल क्लीयर नहीं हुए और बिल क्लीयर न होने की वजह से जिन मशीनों का एनुअल मेंटेनेंस होना चाहिए, वो एनुअल मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। कंपनियों ने मेंटेनेंस करने से इंकार कर दिया और धीरे धीरे वो मशीनें जंग खा गयी और करोड़ो रुपये जनता के बर्बाद हो गए। केवल मशीनें बर्बाद हो जाती तो वो एक बात थी, नई खरीदी जा सकती थी, लेकिन नुकसान ये हुआ कि हॉस्पिटल में ईलाज के लिए जो टेस्ट हुआ करते थे, वो टेस्ट नहीं हो पा रहे। मरीजों की संख्या घटती जा रही है। आज वो कैंसर इंस्टिट्यूट लगभग बंद होने के कगार पर है। राजीव गांधी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल बंद होने के कगार

पर है। माननीया अध्यक्षा महोदय, मैं चाहता हूं, सदन से निवेदन करता हूं इसका रिकॉर्ड मंगवाया जाए पिछले तीन-चार सालों में कितने डाक्टर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट से, कितने डाक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल से नौकरी छोड़कर चले गए। वहां डाक्टर आते हैं, नए बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल है। ईलाज करेंगे, लोगों की मदद करेंगे और खुद भी अपने आप को अपडेट करेंगे, लेकिन न तो उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी है। चूंकि सारा भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पर होती है, कांट्रेक्चुवल है और वहां उनकी नौकरी की कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई सेफगार्ड हो, कोई सेफ्टी हो। जब चाहे निकाल दो और ऊपर से उनको महीनों महीनों से तनख्वाह न मिले और जो ईलाज के लिए जो उपकरण चाहिए, वो उपकरण नहीं मिल पा रहे। उपकरण खत्म हैं और उपकरण इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं चूंकि वहां कोई अकाउंट ऑफिसर नहीं हैं, जो पिछले बिल क्लीयर हों तो फिर अगले बिल लगें। दो दो साल से बिल क्लीयर नहीं हो रहे। डाक्टर नहीं हैं, दवाईयां नहीं आ पा रही हैं, उपकरण नहीं हैं, मशीनें जंग खा गयी हैं, पूरा हॉस्पिटल बंद होने के कगार पर है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय काबिल नहीं है। लेकिन अगर वो चैयरमेन हैं तो उन दुर्दशा की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्षेत्रीय विधायक लेगा क्या? जब मेडिकल डायरेक्टर नहीं हैं तो दोष किसको दें? अगर गवर्निंग बॉडी दोनों अस्पतालों को चलाती है तो गवर्निंग बॉडी के चैयर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। या तो वो कुछ

सुझाव दें कि कैसे अस्पताल सुधारें, कैसे जॉब सिक्योरिटिज हो, कैसे पिछले बिल क्लीयर हों, कैसे उनको मेडिकल डायरेक्टर सबको इंडिपेंडेंट दिये जाए, कैसे अलग अलग इंडिपेंडेट अकाउंट ऑफिसर दिये जाए, वरना मैं यकीन के साथ कह सकता हूं और बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, चूंकि ये पीड़ा केवल मेरी सीमापुरी विधान सभा की नहीं है, बेशक अस्पताल मेरी विधान सभा में हैं, लेकिन यहां जो मरीज आते हैं, वो पूरे देश के कोने कोने से आते हैं और उसकी वजह से दर्द हमें होता है। जब हम वहां जाते हैं मरीज भी हमसे कहते हैं जी कुछ नहीं हो रहा है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही है और जब हम अफसरों से मिलते हैं, डाक्टरों से मिलते हैं। डाक्टर भी आकर रोने लगते हैं। मेडिकल डायरेक्टर है नहीं, किससे मिले, किससे समाधान करें। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन के माध्यम ये लिखित में जाना चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी महोदय, आप गवर्निंग बॉडी के चैयरमेन होने के नाते अपनी तरफ से सुझाव दें कि कैसे इस अस्पताल का रख रखाव ठीक हो, कैसे मशीनों का मेंटेनेंस ठीक हो, कैसे डाक्टरों की स्थायी तौर पर भर्ती हो, कैसे ये हॉस्पिटल पूरी अपनी ऊर्जा के साथ काम करें। अभी तो जो काबिलियत है उसकी उससे भी, वो काबिलियत से भी नीचे जाकर काम कर रहे हैं। अंडरयूटिलाइज हो रही हैं मशीनें। अंडरयूटिलाईज हो रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग हैं तो इसका समाधान होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया अध्यक्षा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया, जय हिन्द, जय भीम, जय भारत।

माननीया अध्यक्षः बंदना कुमारी जी। 11वें नंबर पर हैं। अनिल कुमार, आप तैयार नहीं हैं।

माननीया अध्यक्षः मैं भिजवाती हूं।

श्रीमती बंदना कुमारीः थैंक्यू मैडम, आपने मुझे.... मैडम हमारे यहां..

माननीया अध्यक्षः एक मिनट, आज लगभग 35 सदस्यों के लगे हैं 280 में, मेरा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले, जिनके पास भी उनका प्रश्न नहीं हैं, जिनकी टेबल पर भी, तो एक बार सेक्रेटरी साहब उनको भिजवा दें आप। जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः मैम आज जो मुद्दा, कल का इंर्पोटेंट था मेरा, तो कल वाला बोल दूं।

माननीया अध्यक्षः हां, बोलिये जो भी बोलना चाहें।

श्रीमती बंदना कुमारीः एक हमारे यहां शालीमार बाग में एक रोटरी बनी थी पीडब्ल्युडी की विभाग के द्वारा रोटरी का काम होना था, जो लगभग 2007 में, 2007 में उसकी सेंक्शन हो चुकी थी और अंडरपास भी बनना शुरू हो गया था। अंडरपास बन चुका था। एक रोटरी का काम इसलिए रूका हुआ था, जो वहां पर कुछ झुग्गियां थी लगभग 70 से 80 के करीब में झुग्गियां थी, जिसकी वजह से वो रोटरी का काम, गोल चक्कर का काम रूक गया था और उस गोल चक्कर के लिए 2009 में अंडरपास का काम

कंप्लीट हो चुका और वो झुग्गियों को शिफ्ट करने की वजह से वो रूक गया। फिर 2013-14 में जब हम आए। हमने जब ये फाइल खोली तो 2015 से लगातार डे बाय डे उस फाइल को मैं देख रही हूं। डे बाय डे चीफ सेक्रेटरी से लेकर, सेक्रेटरी से लेकर पीडब्ल्युडी के हर विभाग के साथियों से मैं लगातार मिल रही हूं। अब उस फाइल की स्थिति ये है लगभग 2017 में, 2017 में मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी के साथ सबके सहयोग से, विभाग के अधिकारियों के सहयोग से वो जे जे कलस्टर जो 80-90 के करीब मकान थे, वो मकान शिफ्ट कर दिए गए वहां से। 2017 से लगातार हर डिपार्टमेंट में जा जाकर वहां पर गोल चक्कर जो हमारी दो हॉस्पिटल है उस एरिया में, एक मैक्स हॉस्पिटल है, एक फोर्टिज हॉस्पिटल है और साथ में वहीं कॉर्नर पर दो बड़े स्कूल हैं और वो चौक ऐसे पैक होता है, जो ढाई-ढाई घंटे वो चौक पर जाम रहता है। लगातार हमने पुलिस से, ट्रैफिक से, सभी जगह से एनओसी होने के बाद ये फाइल पास हो हुई

अब फाइल की स्थिति ये है जो हमारे मंत्रालय से भी फाइल पास हो चुकी और ये फाइल लगभग 9 से 10 पीडब्ल्युडी सेक्रेटरी देख चुके हैं, चैक कर चुके हैं। सेंक्शन आने वाले दिन ही पता नहीं क्या होता है, उसी दिन सबकी ट्रांस्फर हो जाती है, जब उनको साईन करना होता है, पता चलता है मेरी तो ट्रांस्फर हो गयी। आज पता चलता है क्योंकि आज साईन होने वाली है तो आज ही ट्रांस्फर हो गयी। फिर उस फाइल पर दूसरे सेक्रेटरी आते

हैं, वो डे वन से फिर शुरू करते हैं। सारी चैकिंग होती है, फिर चैकिग होती है, फिर चैकिंग होती है, फिर क्लीयर होने वाले दिन उनकी ट्रांस्फर हो जाती है। ऐसे कम से कम सात से आठ सेक्रेटरी उस फाइल को देख चुके हैं। आज भी हालात यही है जो कि हमारी मंत्रालय से क्लीयर हो गयी लेकिन सेक्रेटरी साहब के टेबल पर फाइल रखी हुई है और छः महीने हो गये।

अभी हमारे पीडब्ल्युडी सेक्रेटरी Anbarasu जी हैं, उनके पास भी मैं लगातार तीन बार, चार बार जा चुकी हूं और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूं। सर सारी ओब्जर्वेशन हो गयी तो इसको क्लीयर कर दीजिए और क्योंकि वहां पर ऐसी स्थिति होती है तीन चार बार तो मैं खुद गाड़ी से उतर कर और सारे ट्रैफिक को खुलवाती हूं और वहां पर क्लीयर करवाती हूं, जो उस जगह को जाम से मुक्ति से मिले।..

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट कीजिए।

श्रीमती बंदना कुमारीः लेकिन आज तक उस फाइल पर क्या स्टेटस है, क्यों रोक कर रखा गया है, उसकी क्लियरेंस हमारे पास नहीं हैं और आज तक मैं भी नहीं समझ पायी जो उस फाइल में प्रोब्लम क्या है। अगर प्रोब्लम है तो भी बताएं, वहां किस प्रोब्लम से उसको रख रहे हैं। अभी बोला जाता है अगले मंडे तक हो जाएगा। अगला मंडे कब आएगा, वो भी क्लीयर नहीं है। मैंने कहा चूंकि एक बार सभी अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, एक टेबल

पर बुलाके डिस्कसन कर लिजिए कि इसको क्या करना है, कहां पर कौन सी प्रोब्लम आ रही है। तो मैं अध्यक्षा जी, आपके माध्यम से चाहती हूं, ये सदन के माध्यम से चाहती हूं, जो उस फाइल में क्या प्रोब्लम है, वो पीडब्ल्युडी की रोटरी, जिससे पूरा शालीमार बाग ही नहीं, आजादपुर वाले एरिया सभी को फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत।

माननीया अध्यक्षः अनिल कुमार बाजपेयी जी। पहले ही 35 लोग हैं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः पहले ही 35 लोग हैं, अगर समय रहा तो सबको पता है। मैं समय किसी का रोकती नहीं हूं। एप्रिसियेट करने के लिए धन्यवाद, लेकिन समय सीमा भी तो है। सदन रूल से चलेगा। अनिल बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 280 नियम के अंतर्गत बोलने का मौका दिया। आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान गांधी नगर विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जब से गांधी नगर बना है लगभग 1960 और 1961 के आस पास तब से वहां पर कोई भी फायर स्टेशन नहीं हैं। गांधी नगर में एशिया की रेडीमेड गारमेंट्स की सबसे बड़ी

मार्केट है। पूरे देश से ही नहीं, विदेश से भी लोग व्यापार करने के लिए गांधी नगर में आते हैं।

गीता कॉलोनी गांधी नगर के बाद में बसा और गीता कॉलोनी में फायर स्टेशन है, लेकिन गांधी नगर के अंदर फायर स्टेशन नहीं हैं जबकि गीता कॉलोनी में जो फायर स्टेशन है उसके बगल में गांधी नगर फायर स्टेशन बनने की जगह पड़ी हुई है लेकिन आज तक गांधीनगर फायर स्टेशन नहीं बना है। विगत कई वर्षों में कई बार गांधी नगर में आग लगने की घटनायें हो चुकी हैं। कम से कम 3 से 6 लोगों की डेथ आग लगने के कारण हुई जिसमें 13 साल का एक नौजवान बच्चा भी था, वो भी मारा गया। अभी रिसेन्टली 9 अगस्त, 2023 को गांधी नगर थाने के पास बहुत बड़ा टिम्बर व्यापारी, टिम्बर मर्चेंट था एक वहां पर सरदार जी उनकी दुकान पर 3:45 मिनट पर आग लग गईं 21 से अधिक गाड़ियां आईं और दो दिन डेढ़ दिन आग बुझाने में वहां पर लगा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पर फायर स्टेशन होना चाहिए। अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक चीफ फायर ऑफिसर श्री अतुल गर्ग जी से कई बार इसके बारे में मीटिंग हो चुकी है और वहां के सारे रेसीडेंट वेलफेयर एसोसिएसन, मार्केट एसोसिएसन सबने मिलकर बात की है। किसी तरीके से हम लोगों ने फाइल वहां से मूव करा दी है। आज वो फाइल माननीय कैलाश गहलौत जी के पास पड़ी हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी का कई बार हम लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया

होता है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये नहीं कि मैं भाजपा का विधायक हूँ, कभी उनकी पार्टी का भी मैं विधायक था। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गांधी नगर में फायर स्टेशन खुलना चाहिए। ये कोई मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, ये गांधी नगर की आम जनता की मांग है। मैं आपका व्यक्तिगत रूप से आभारी रहूंगा कि इस मामले को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के गांधी नगर में नया फायर स्टेशन खुलना चाहिए ये मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत-बहुत आभार।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद। राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद उपाध्यक्षा जी, मेरी विधान सभा के अंदर खासतौर के वजीरपुर जे.जे. कॉलोनी के अंदर ऐसी बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है, बाकायदा खम्भों पे लगी हुई है जिन्हें टीपीडीडीएल ठीक करने से मना कर देता है। उनका ये कहना होता है कि ये बैडस्विच की लाइटें हैं जिनको किन्हीं नेताओं ने, काउंसलर्स ने चुनाव के समय पे लगा दिया और अब वो ठीक नहीं हो सकती क्योंकि उसके ऊपर ट्रांफार्मर लगे हुए हैं या कुछ लाइन्स जा रही हैं। चलिए मान लिया हमने उनको कहा कि इन्हें आप नहीं ठीक कर सकते तो इनको ठीक करने का तरीका क्या है। ट्रांफार्मर को शिफ्ट किया जाए, खम्भे को शिफ्ट किया जाए, क्या किया जाए। मैं इस वक्त में आदरणीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसका एक विकल्प निकाला और मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत हमको ऐसी

लाइट्स दीं जो हमने कैमरे की तरह जैसे कैमरे लगाए थे वैसे ही उन लाइट्स को घरों के ऊपर लगाया, उन्हीं लोगों को उसी से सब्सिडी दी और बहुत जगह रोशनी हो गयी। लेकिन उसके बावजूद ऐसे बहुत–से चौराहे हैं जहां पर हमको जो पास में रहने वाले हैं उनका कनैक्शन नहीं मिल पाता। हमें उन खम्भों पे ही लाइट लगानी पड़ेगी। ना कोई नया खम्भा लगाने की जगह है। ऐसे में मैंने टीपीडीडीएल से कई बार मीटिंग्स करीं और उनको कहा कि भई आप बताइये ये कैसे ठीक होंगी, तो उन्होंने कहा के जी हम इन्हें ठीक कर सकते हैं लेकिन इसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है आप एमएलए फंड ले लीजिए, तो कहते हैं नहीं एमएलए फंड नहीं चाहिए इसमें। इसमें सरकार से पैसा आना चाहिए। ठीक है सरकार से पैसा ले लीजिए। तो उसका प्रपोजल बना के दे दीजिए। वो भी बनाके देने को राजी नहीं है। समझ नहीं आता, कल भी आपने एक बात सुनी होगी सदन में कि विधायक कह रहा है पैसा दे दो, मंत्री जी कहते हैं दे दो, मुख्यमंत्री चाहते हैं दे दो, जनता चाहती है लाइट लग जाए। डीसीडब्लु कहता है किसी महिला के साथ में गलत काम ना हो जाए अंधोरे के रहते। सारी दुनिया सब कुछ समझती है तो प्रोब्लम कहां पर है? सीधे–सीधे बतायें, प्रपोजल बनायें एक निश्चित अवधी के अंदर बनाये। दिवाली आने वाली है दिवाली से पहले वहां पर रोशनियां हो जायें। जो थोड़ा बहुत भी खतरा कहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो लाइटें हम लगाते हैं, नहीं तो वो नीचे रह जाती हैं। जो ऊंचे खम्भों पे लाइट

लगती है बहुत एरिया कवर करती है। उसको चोरी करना, खराब करना आसान नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि टीपीडीडीएल के पास एक पत्र जाए या उनको बुलाया जाए और उनको ये सख्त हिदायत दी जाए कि जिससे भी पैसा उनको लेना है वो दिल्ली सरकार से लेना चाहती है तो दिल्ली सरकार के लिए प्रपोजल बनाये, अगर विधायक से लेना चाहती है तो विधायक से प्रपोजल बनाये क्योंकि एमसीडी के तहत वो लाइटें आती हैं तो एमसीडी से लेना चाहती है तो एमसीडी को बनाये। उसके लिए भी विधायक पैसे दे सकता है। वो पैसे लें और लाइट को ठीक करें क्योंकि वहां रहने वाली माताओं के लिए, बहनों के लिए वो लाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चूंकि खुद एक महिला हैं मुझे उम्मीद है कि आज ही एक लेटर आप बड़ा सख्त-सा टीपीडीडीएल को लिखेंगी। आपने बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापतिः सुरेन्द्र कुमार जी।

श्री सुरेंद्र कुमारः आदरणीय उपाधयक्ष जी आपने 280 में बोलने का समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय जल मंत्री और सदन का ध्यान गोकलपुर विधान सभा क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जहां पर पानी की गम्भीर समस्या है। मेरी विधान सभा में 25 ऐसी कॉलोनी हैं जहां तीसरे दिन पानी मिलता है और 15 ऐसी कॉलोनियां हैं केवल आधा घंटा पानी आता है, बाकियो में 20 परसेंट पानी ही मिलता है। पहले भी मैं कई बार इस समस्या को सदन में उठा चुका हूँ

लेकिन इस पर कोई भी अभी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं इस संदर्भ में पहले भी आदरणीय मंत्री जी से मिला हूँ। उपाधयक्ष से भी मिला हूँ लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनता का ये मौलिक अधिकार है और मेरे क्षेत्र के लोगों पानी के अधिकार से वंचित है। भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मेरे क्षेत्र में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी क्षेत्र में पानी की त्राहि–त्राहि मची हुई है। माननीय उपाधयक्ष जी, मैं मंत्री जी के संज्ञान में जलबोर्ड की सीवर लाइन जो कई सौ साल पुराने मेरे क्षेत्र में गांव हैं जोहरीपुर, मंडोली गांव और आपका सुबोली जहां तक सीवर लाइन नहीं डली है और ऐसी कुछ अनॉथराइज कॉलोनियां जिसमें करीब 17 कॉलोनी हैं जिनका 17 करोड़ रूपए के सीवर कनैक्शन के लिए स्कीम जा चुकी है लेकिन अभी तक बजट नहीं मिला है। क्योंकि सीवर कनैक्शन हो जायेंगे तो हम वहां पे रोड बनाने का कार्य भी शुरू किया जा सकता है। आदरणीय उपाध्यक्षा जी मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरा क्षेत्र 90 परसेंट अनॉथरोइज है। वहां एक भी पास कॉलोनी नहीं है, स्लम कॉलोनी है, झुग्गी हैं। तो आपसे निवदेन है उस क्षेत्र को देखते हुए, पक्षपात ना करते हुए क्योंकि आस–पास की कॉलोनियों में वहां जहां मैं रहता हूँ ज्योतिनगर में वहां 4 बार पानी आता है और मेरे क्षेत्र को एक बार भी पानी नहीं मिलता है। ये पक्षपात देखते हुए दिल्ली सरकार से निवेदन करना चाहता

हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आस-पास की कॉलोनियों को देखते हुए मेरे क्षेत्र में भी पानी दिया जाए, उनके साथ पक्षपात ना किया जाए क्योंकि वो भी दिल्ली की जनता है, दिल्ली की सरकार को वोट देती है। हम सबको सरकार बनाने का वो सहयोग देने का काम करती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः नरेश यादव जी। अपना विषय शोर्ट में रखें ताकि औरों का भी नंबर आ जाए।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्षा जी जो आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया। अध्यक्षा जी, आज कल मेरे ऑफिस में बीएसईएस कनैक्शन लगाने की बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है और बीएसईएस के जो अधिकारी मेरे पास आते हैं और लोगों की जब समस्या सुनते हैं तो उनका ये कहना होता है कि जो बिल्डिंगें हैं वो एमसीडी जब कंन्सट्रैक्सन हो रही होती है तब वो बुक कर देती है। बुक करने के पश्चात में बीएसईएस और दिल्ली जल बोर्ड को एक लेटर इशु करती है कि इन बिल्डिंग्स पर जो एमसीडी द्वारा बुक्ड है उसपे कनैक्शन ना लगाया जाए। अध्यक्ष जी ये समस्या मुझे लगता है कि माननीय दूसरे जितने सदस्य हैं पूरी दिल्ली में, ये समस्या होगी और एमसीडी इसको बड़ी चालाकी से करती है। एमसीडी जिसको चाहे उस बिल्डिंग को बचा देती है और जिसको चाहे बुक कर देती है और इसमें अध्यक्षा जी बहुत जबरदस्त करप्शन भी है। एमसीडी में जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट

है, सबसे ज्यादा करप्शन वहीं होता है और सभी अधिकारी भी उसी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। 99 परसेंट सारी बिल्डिंगे ये लगभग बुक करते हैं, लेकिन इसमें कुछ जो नंबर होता है प्रोपर्टी का उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वो किन्हीं लोगों को बेनिफिट्स भी देते हैं और फिर उसके बाद में वो अपना पल्ला झाड़ते हुए बीएसईएस को लेटर लिख देते हैं कि इन बिल्डिंगों में किसी तरह का कोई कनैक्शन ना दिया जाए। बीएसईएस अधिकारी भी कनैक्शन देना चाहते हैं। लोग वहां रह रहे होते हैं उस बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग को बुक्ड दिखाया गया है, जिस बिल्डिंग को सील्ड दिखाया गया, लेकिन क्योंकि उनकी बाइंडिग होती है वो लेटर एमसीडी का, कोर्ट के भी कई आदेश हैं कि अगर कोई बिल्डिंग एमसीडी से बुक्ड है या सील्ड है तो उसपे कनैक्शन ना लगाया जाए। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय सीएम साहब से ये अनुरोध है कि जितनी भी बिल्डिंगें दिल्ली में बुक्ड हैं या सील्ड है वो जो बन चुकी है, जहां पर लोग रह रहे हैं उसको एमसीडी एक एमनेस्टी स्कीम लाके सबको रेगुलराईज कर दे और सबको वहां पर बिजली का कनैक्शन लगाने की और साथ में दिल्ली जलबोर्ड का कनैक्शन लगाने की अनुमति दी जाए और किसी भी तरह से एमसीडी कहीं भी जो बिल्डिंग बन रही है, उसमें इस तरह का करप्शन ना कर सके ऐसी व्यवस्था की जाए। साथ में अध्यक्षा जी जो लोग बिल ना भरने की वजह से कनैक्शन कट जाता है उनका 6 महीने के बाद कनैक्शन नहीं लगता और वो जब दुबारा अप्लाई

करते हैं तो उनको भी ये कहा जाता है कि आपकी बिल्डिंग पिछले 10 साल, 15 साल पहले बुक थी। उनके भी कनैक्शन नहीं लगाये जाते। जबकि सारी कार्रवाई पूरी करके, सारे डोकोमेंट्स लेके वो कनैक्शन लगाया गया था। तो इसकी भी व्यवस्था की जाए कि अगर किसी का कनैक्शन एक बार लगा है और वो बिल दोबारा भर देता है तो वो कनैक्शंस भी लग जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्षा जी जो आपने मुझे ये समस्या उठाने का मौका दिया।

माननीया अध्यक्षः करतार सिंह तंवर जी।

श्री करतार सिंह तंवरः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। आपने मुझे 280 के तहत बोलने का अवसर दिया। अध्यक्षा जी मैं आपका ध्यान छतरपुर विधान सभा में लगातार ट्रैफिक जाम की बढ़ती हुई समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूँ। छतरपुर विधान सभा में 100 ुटा रोड और एसएसएन मार्ग पर हर रोज कई-कई घंटे का जाम लगा रहता है। ये दोनों ही रोड पीडब्लुडी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। डीएलएफ फार्म छतरपुर से कुतुब मेट्रो तक एक एलिवेटिड रोड बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। एलिवेटिड रोड बनने से ही इस क्षेत्र को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकती है। अध्यक्षा जी छतरपुर विधान सभा में बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं। बहुत बड़ा जैसे एक छतरपुर मंदिर है, राधास्वामी सत्संग व्यास है, गुरू जी का आश्रम है, हंसलोक आश्रम है, राजविद्या केन्द्र है। ये सभी धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए संस्थान हैं और बहुत सारे बैंक्वेट भी हैं जहां पर शादी-विवाह के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं और मेरे ख्याल से

पूरी दिल्ली से ही लोग छतरपुर विधान सभा में आते हैं। तो ट्रैफिक का जो वहां पर लोड है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और हमेशा अब सबसे बड़ी जो ट्रैफिक जाम की समस्या है मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में आज छतरपुर में सबसे ज्यादा है। तो मेरा आपसे निवेदन कि डीएलएफ छतरपुर फार्म के सामने से और कुतुब मेट्रो तक जल्द से जल्द एक एलिवेटिड रोड बनाया जा सके, ताकि क्षेत्र को इस समस्या से छुटकारा मिले। एक अध्यक्षा जी यहां पर एक टैम्प्रेरी इसी रोड के बीच में नन्दा हॉस्पिटल के सामने एक टैम्प्रेरी कूड़ा घर भी है जिसकी वजह से भी जाम बहुत ज्यादा लगता है, क्योकि कूड़ा फैलकर रोड पे आ जाता है और वहां पर गाय आ जाती हैं जिससे रोज वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कूड़ेदान को भी जल्द से जल्द हटाया जाए और इस रोड को पूरे को 100 फुटा रोड और एसएसएन मार्ग को एलिवेटिड बनाया जाए बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान मोती नगर विधान सभा और दिल्ली में हो रही झुग्गियों, कलस्टर में भेदभाव की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरी मोती नगर विधान सभा में डेढ़ लाख से ज्यादा लोग कलस्टर में रहते हैं। यहां पर बड़े–बड़े कलस्टर हैं। कीर्तिनगर है, रामा रोड है, जखीरा है, अमर पार्क है। और यहां पर औद्योगिक संस्थान काफी हैं और यहां पर करीब–करीब

डेढ़ लाख लोग कलस्टर में रहते हैं और जब भी चुनाव आते हैं तो इनको सपने दिखाए जाते हैं 'जहां झुग्गी वहीं मकान'। 2014 में प्रधानमंत्री जी का चुनाव हुआ। 2017 में एमसीडी का, 2019 में प्रधानमंत्री का फिर चुनाव हुआ। 2020 में दिल्ली राज्य का चुनाव हुआ और 2022, अभी एमसीडी का चुनाव हुआ। तो हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े-बड़े होर्डिंग लगाती है, प्रधानमंत्री जी की फोटो लगती है उसके ऊपर और बड़े-बड़े वादे किये जाते हैं कि 'जहां झुग्गी वहीं मकान' और हर चुनाव में स्मार्ट कार्ड बांटे जाते हैं, ये आपको एक कार्ड दे रहे हैं अब आपको मकान जरूर मिलेगा। अब वहां की जनता भोली-भाली है, पढ़ी-लिखी नहीं है और वो उनके बहकावे में आ जाती है। और पिछले 12 साल से इस चुनाव पर छला जा रहा है और कई लोगों ने इस छल में पैसे भी जमा करा रखे हैं झुग्गियों में, 80-85 हजार रुपये डीडीए में जमा भी करा रखे हैं परंतु आज तक कोई भी उनको मकान मिला नहीं है। और मेरे क्षेत्र में झुग्गीवासी आते हैं, गुहार लगाते हैं, परंतु जब मैंने, जुलाई 2022 में हमने एक केंद्रीय मंत्री का एक वक्तव्य, एक ट्विट देखा, जिसमें लिखा था नरेला के अंदर 2400 फ्लैट बांग्लादेशियों को आबंटित कर दिये गये हैं, उनको बिजली भी फ्री, उनको पानी भी फ्री। अध्यक्ष जी, जब केंद्र सरकार के द्वारा बांग्लादेशियों को फ्लैट मुफ्त में बांटे जा रहे हैं जबकि ये हमारे दिल्लीवासी झुग्गियों के, क्लस्टर के पैसे देने के बावजूद भी फ्लैट नहीं मिल रहे, ये किस तरह का देश प्रेम है? तो मेरी जो क्लस्टर

में डेढ लाख लोग रहते हैं वो हाथ जोड़कर विनती करते हैं.. हैं जी।

...व्यवधान...

श्री शिव चरण गोयलः ऐसा है, लेकिन जो ट्विट तो आया था आपने पढ़ा होगा।..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः गुप्ता जी।

...व्यवधान...

श्री शिव चरण गोयलः मैं जो कह रहा हूं, आपको जो..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः विजेंद्र गुप्ता जी,

...व्यवधान...

श्री शिव चरण गोयलः आप ये जो ट्विट..

माननीया अध्यक्षः विजेंद्र गुप्ता जी, आप यहां चेयर को एड्रेस कर लें। वहां से सदन थोड़े ही न चल रहा है। करें कंटिन्यू।

...व्यवधान...

श्री शिव चरण गोयलः तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है भाजपाइयों से, प्रधानमंत्री जी से, जो ये वादे करते हैं बड़े-बड़े, कम

से कम भी उनको मकान दिये जाएं और जिन्होंने पैसे जमा करा रखे हैं 10-10, 12-12 साल से उनको कम से कम भी, लेकिन अब वो तो चुनाव आने वाला है 8 महीने बाद, अब कम से कम भी बड़े-बड़े होर्डिंग न लगाये, लगाये तो कम से कम मकान उनको जरूर देंगे। शुक्रिया। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद जी। भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदया, मैं आज आपके माध्यम से एक बड़ा संवेदनशील एक मुद्दा है मेरी विधान सभा का, 280 के माध्यम से उसे उठाने जा रही हूं। इसके साथ-साथ में इस तरह के 2 मुद्दे मैं 280 में पहले भी उठा चुकी हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा पालम के साधा नगर वार्ड में जे.बी.एम. पब्लिक स्कूल के सामने लगभग आज से कुछ समय पहले 15 बीघा जमीन जो ग्राम सभा की थी उसको दिल्ली सरकार ने ग्राम सभा की लैंड्स को डीडीए को हैंडओवर कर दिया देखरेख करने के लिए। इनका खसरा नंबर 612, 613 और 614 है। लगभग साढ़े चार-पांच बीघा जमीन के ऊपर लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया, चार मंजिला मकान बन गये हैं, कुछ मकान बनकर के तैयार हो गये हैं, इसी विषय में मैं 280 में अपनी बात रखना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, नियम के तहत यह ग्राम सभा की जमीन देखरेख की दृष्टि से डीडीए को हैंडओवर कर दी गईं मेरे से पूर्व विधायक, जो एम.पी. भी रहें वेस्ट दिल्ली से, उन्होंने इस जमीन को बचाने के लिए, डीडीए की इस जमीन पर चार दीवारी करवा दी ताकि इस जमीन

को वो सेफ कर सकें। हालात बदले अध्यक्ष महोदय, कुछ समय बाद क्षेत्र के ही कुछ दबंग लोगों ने इस चार दीवारी को जगह-जगह से तोड़कर इस जमीन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसमें बीजेपी महिला पार्षद के पति और जो पूर्व पार्षद रहें बीजेपी से उनका शामिल होना बताया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति ये है कि एक टुकड़े पर चार मंजिल का मकान बन चुका और वो बिक चुका, एक और बिल्डिंग चार मंजिल की बनकर के तैयार है, बिकने की हालत में खड़ी है। अध्यक्ष महोदय, एक लंबे चौड़े टुकड़े पर कबाड़ी वाले बहुत अधिक तादाद में वहां पर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की वर्तमान महिला पार्षद के पति द्वारा रोडा, बदरपुर, रेता, टैक्टर-ट्राली वहां खड़ा करके उस पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एरिये में रहने वाला कोई साधारण सा आदमी या बिल्डर जब अपनी बिल्डिंग को बनाता है तो उस पर ये दबाव डाला जाता है कि बिल्डिंग मैटेरियल का सामान तुम वहीं से लोगे जो अनऑथराइज्ड तरीके से कब्जा करके जहां पर उन्होंने वो सारा सामान डाला हुआ है। और अगर हमसे सामान नहीं खरीदोगे तो पालम विधान सभा में कोई भी बिल्डिंग बनना अपने आप में मुश्किल है। कहने का तात्पर्य यह है अध्यक्ष महोदय 15 बीघा जमीन जिसे डीडीए को हैंडओवर किया था, आज उस पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं इस विषय पर दिल्ली सरकार के एसडीएम महोदय से बात की,

उन्होंने भी डीएम महोदय से बात की और इस समस्या का हल निकालने के लिए डीडीए के अधिकारियों द्वारा डीएम और एसडीएम के साथ में एक मीटिंग रखी गई लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन के माध्यम से और हमारे दिलीप भाई बैठे हैं जो डीडीए के मेम्बर हैं, उनके भी संज्ञान में ये लाना चाहूंगी। मेरा इस सदन के माध्यम से यह निवेदन है कि इस जमीन को तुरंत आदेश के साथ खाली करवाया जाए तथा इस जमीन पर मानवता के नाते कोई हॉस्पिटल, पार्किंग और स्कूल का निर्माण करवाया जाए। धन्यवाद महोदया आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। शुक्रिया।

माननीया अध्यक्षः आज 280 में कुल 18 सदस्यों ने भाग लिया। अब श्री राजेश गुप्ता जी, श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के संबंध में याचिका समिति का चौथा अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मुझे भी आपसे ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं है। सदन जो है कानून और जो है मर्यादा से चलेगा।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्षा जी, मेरा एक निवेदन था, मेरा एक निवेदन था आपसे कि बड़ी अच्छी कार्यवाही चल रही है सदन की और बहुत सारे लोगों के लोकल विषय लिये जा रहे हैं

तो मेरा निवेदन है कि सदन को एक दिन के लिए और आगे बढ़ाया जाए, ये मेरा निवेदन है आपसे।

माननीया अध्यक्षः माननीय सदस्य, कुलदीप जी का प्रस्ताव सदन के समक्ष है,

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें,

जो इसके विरोधा में हैं वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जी, हाँ पक्ष जीता,

तो सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए मतलब कल 18 तारीख के लिए बढ़ाई जाती है। धन्यवाद। जी राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद उपाध्यक्षा जी आपने जिस रिपोर्ट को पेश करने के लिए आदेश दिया है, बहुत ही गंभीर स्थिति जो दिल्ली को बार-बार फेस करनी पड़ रही है, सामना करना पड़ रहा है और सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद जिस तरीके से हम लोगों को अपने काम कराने में, जनता के काम कराने में तकलीफ आ रही है। मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम लोग किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आये हैं। हम में से ज्यादातर लोग, कोई सॉफ्टवेयर में काम करता था, कोई इंडिया से बाहर रहता था, किसी का बिजनेस था, कोई आर्टिस्ट था, बस मन में एक सपना था कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाये, अपनी

दिल्ली के लिए कुछ कर पाये, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाये। हम सोचते थे क्यूं ऐसा होता है कि जिन नेताओं को जनता चुनकर भेजती है वो जनता में जाना क्यूं नहीं चाहते? क्यूं लोग एक दूसरे के काम रोकते हैं? क्या उन्हें डर नहीं लगता? क्या उन्हें शर्म नहीं आती? क्या उन्हें हाय का डर नहीं लगता? तो मन में आया कि उस आंदोलन में चलते है जिस आंदोलन से सबकी एक उम्मीद जगी कि शायद एक ऐसा विकल्प पैदा हो देश की राजनीति में जो देश में कुछ बदलाव कर पाये। दिल्ली की जनता ने उस आंदोलन के मुखिया को सराहा और पहली बार में ही 28 सीटें दी। कुछ कमी रह गई तो अगली बार 2015 में एकतरफा, 50 हजार, 60 हजार, 70-70 हजार वोट से विधान सभा की सीटें जीतकर दे दी, जो लोक सभा के चुनाव में अंतर होता है उससे ज्यादा अंतर कई जगह विधान सभा की सीटों पर रहा। जो-जो वादे करे थे उनको धार्मर्गंथ की तरह हमने अपने मैनिफेस्टो को मानते हुए पूरा करा। बजट की दिल्ली में कोई कमी नहीं रही क्योंकि ईमानदार सरकार थी। जनता ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब टैक्स दिया और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने उस टैक्स को उन्हीं को वापस दिया, कभी फ्री बिजली के तौर पर, कभी फ्री पानी के तौर पर, कभी मोहल्ला क्लिनिक के तौर पर, फ्री हॉस्पिटल के तौर पर, कैमरे के तौर पर, वाईफाई के तौर पर, महिलाओं को मुफ्त यात्राओं के तौर पर, फिर बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रओं के तौर पर, बहुत अच्छा चल रहा है। और इसीलिए 2020 में फिर सरकार चुनकर

आई और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में तो कम से कम, पूरे इंडिया में तो कम से कम कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जो दावे से ये कह सकें कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दे देना, ये किसी की भी हिम्मत नहीं होती। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दावे से ये कहा कि अगर मैंने काम किया है, मेरी सरकार ने काम किया है, मेरे विधायकों ने काम किया है तो वोट देना, नहीं तो मत देना। और दिल्ली की जनता ने फिर 62 सीटें दी।

फिर एक चुनाव आया निगम का, अब जब सर्वे आये निकलकर तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने जब वो सर्वे देखा तो देखा तो यार इस बार तो लग रहा है दिल्ली सरकार से भी खराब हालत हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत धूल बच जाती है कभी-कभी झाड़ू लगने पर वो भी नहीं बचेगी। एकतरफा हार, तो चुनाव ही रद्द करा दिये। एक साल चुनाव को रोककर रखा। फिर परिसीमन ऐसा करा कि कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि एक सीट ये जीते, दो हम जीते। सारे तिकड़म बनाये, उस सब के बावजूद निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आ गईं और जो एक साल के भीतर हुआ उसकी पृष्ठभूमि में इस रिपोर्ट को मैं पेश करना चाहता था। जो एक साल का डिले करा उसमें परिसीमन तो आपको मालूम है हुआ, आपको मालूम है वार्ड कैसे बांटे गये। लेकिन कैसे-कैसे कामों को रोककर जनता को परेशान किया गया ताकि लोग निगम में इनको ले आये, उसकी पृष्ठभूमि इस रिपोर्ट के अंदर है। मैं कुछ पुरानी चीजों को बताये देता हूं क्योंकि ये रिपोर्ट आज जो मैं पेश

कर रहा हूं उसमें पुरानी पृष्ठभूमि है, in its sitting held on 19 January 2023 the House adopted three interim reports presented by the Committee on Petitions. The first interim report dealt with the issues and irregularities in the functioning of OPD counters in the Delhi Govt. hospitals. The reports were presented to the House on 18 January 2023 and adopted in the sitting held on 19th January 2023. The second interim report dealt with the issues relating to the sabotage and irregularities in the disbursal of the Old Age pension. The third interim report dealt with the issues relating to the attempts to sabotage the functioning of Mohhala clinics. The second and the third interim reports were presented and adopted by the House on 19th January 2023. Recommendations of the Committee on these three issues have been annexed to this report. The committee had recommended that the Chief Secretary, Delhi should submit the action taken report in the recommendations within 30 days of the adoption of the reports. In a separate recommendation, it was also requested that Hon'ble Presidentof the ministry of Home Affairs, Govt.of India should take appropriate action against the chief secretary and the Hon'ble Lt. Governor of Delhi. However, the Chief Secretary and the Secretaries of the departments concerned in complete disregard to the recommendations of the committee and in defiance to the decision of the House, failed to submit the Action Taken Report.As

there were no satisfactory reply to the reminders sent by the assembly secretariat, the committee decided to seek the comments from these officers and asked them to attend the sitting of the committee which was scheduled for 14th of August 2023. In the meantime, Sh. Saurabh Bhardwaj, the hon'ble Minister of Health forwarded to the hon'ble Speaker a file containing the draft action taken reports on the interim reports of the committee. From the perusal of the file copy of which was made available to the committee by the Speakers office, it was found that the departments of Health, Finance and Social Welfare had submitted that the draft ATRs of the Chief Secretary, the ATRs were consolidated and submitted by the General Administrative Department.

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः वो एक बार रिपोर्ट पेश कर लें आप..

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): रिपोर्ट की कापी नहीं दी गई है हमें और उस पर चर्चा हो रही है विधानसभा के अंदर..

श्री राजेश गुप्ताः अभी चर्चा शुरू कहां हुई है सर।

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ताः अभी, पहले थोड़ी दे देंगे आपको, पहले थोड़ी दे देंगे। अरे यार कमाल हो गया।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मैं बात पूरी सुन लूं।

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ताः पहले इनको दे दो।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आपके प्वाईंट आफ आर्डर से पहले, अच्छा बैठ जाइए आपका विषय आ गया। विषय आ गया ना।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बिधूड़ी साहब विषय आ गया अब मैं बोल लूं।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): ....विधान सभा रूल्स के मुताबिक नहीं चलाई जा रही है और दिल्ली से.

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अच्छा बैठिए। अच्छा बैठ जाइए प्वाईंट आफ आर्डर आ गया।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः प्वाईंट आफ आर्डर आ गया बैठ जाएंगे। बैठ जाएं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अच्छा तो बैठिए तो।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): हमारे पास कापी नहीं है। नहीं आप इसके उपर रूलिंग दे ना।

माननीया अध्यक्षः तो बैठेगें तभी तो रूलिंग मिलेगी।

-..व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः सबको एक साथ खड़े होना है। बोल रहे हैं ना आपके नेता। माहौल खराब करना है बस। एक बार पढ़ लें, रिपोर्ट टेबल हो जाए आपके पास हो जाएगी।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): नहीं आपके सैक्रेट्रिएट को इस बात की चिंता करनी चाहिए..

.व्यवधान.

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): ये हमारे अधिकारों का हनन है यदि हम सही बात आपके नोटिस में ला रहे हैं तो आप हमें संरक्षण देने का कार्य आपका है। इसलिए हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि हमारी कोई मंशा ये हो कि हम

हाउस की कार्यवाही को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कापी हमें देनी ही पड़ेगी।

माननीया अध्यक्षः हो गया, बोल लिया आपने।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): जी।

माननीया अध्यक्षः ऐसा कौन सा विषय है जो आप संज्ञान में लाए चेयर के और उस पर मैंने जो है रूलिंग ना दी हो। तो ऐसे निराधार आरोप आप ना लगाएं। पहली बात..

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): आरोप नहीं है।

माननीया अध्यक्षः मेरे को बात कंपलीट तो करने दीजिए यहां वन टू वन कम्नयूकेशन नहीं हो रहा आपने कुछ बोला है मैं उसका जवाब दे रही हूं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप बैठिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): नहीं, आपका ये कहा जाना कि हम आरोप लगा रहे हैं।

माननीया अध्यक्षः मेरा आपसे निवेदन है पहले आप बैठ जाइए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। रूल्स के मुताबिक विधानसभा को चलाया जाए।

माननीया अध्यक्ष: मैं आपके आग्रह पर ही कुछ बात कह रही हूं। आपके आग्रह पर ही कोई जवाब दे रही हूं। मैं पहली बात तो मैं पूर्ण रूप से इस बात को साफ कर दूं विधानसभा पूरे रूल एंड रेगूलेशनस के हिसाब से ही चल रही है, पहली बात। दूसरी बात जैसे रिपोर्ट टेबल होगी सभी माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष के पास रिपोर्ट पहुंच जाएगी। सभी को चर्चा लेने का इसमें जो है मौका मिलेगा। आपकी तरफ से नाम भी नहीं आए थे हर चर्चा में, मैं पहले से आपको बोलती हूं कि नाम दे दीजिए और अभी भी सैक्रेट्री साहब को आपके पास भेजा गया है कि आप नाम दे दीजिए चर्चा के लिए। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, खत्म अब, बस। अब आप इसे बढ़ाये ना। बिधूड़ी जी बिल्कुल ना बढ़ाए, देखिए, नहीं, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: आपको मिल रही है कापी बैठिए तो, बैठिए आप। रिपोर्ट टेबल करें। कापी मिल रही है। बैठ जाइए।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: आप इतने सम्मानित सदस्य हैं, इतने सीनियर सदस्य हैं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः राजेश जी। रिपोर्ट टेबल करें और उसके बाद सभी सदस्यों को रिपोर्ट मिलेगी। अब इस पर एक भी शब्द आगे नहीं, कार्यवाही आराम से चलने दीजिए। आप लोगों को बोलना भी होता है, फिर समय भी खराब करना होता है।

श्री राजेश गुप्ताः The ATRs were consolidated and submitted by the General Administration Department. The note was marked up to the level of the Chief Secretary only. The Chief Secretary on 28th May 2023 observed that the approval of the 'Government' should be taken before submitting the ATRs to the Assembly. Later, when the proposals were again submitted to the Chief Secretary, the proposals were marked to the Ministers concerned, the Chief Minister and finally up to the level of the Hon'ble Lieutenant Governor. ये जो सारी चीज हुई जो पहले भी हुआ है कि तीन चीजों के उपर पेटीशन चली जिसमें जो पहली थी वो हॉस्पिटल्स के अंदर जो स्टाफ रखा जाता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का उनको इन्होंने बिना सोचे समझे हटा दिया, एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जहां पर कम्प्यूटर लगे होते थे और कुछ पढ़े लिखे बच्चे होते थे जो ये देखते थे कि कौन आ रहा है वहां पर, कौन से डिपार्टमेंट में भेजना है, उसका क्या नाम है, क्या उम्र है इन्होंने ने उनको एकदम से हटा दिया, बिना सोचे समझे हटा दिया। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई अब ये गौर देने वाली बात है कि पैसे की

कोई कमी नहीं थी लेकिन समय कौन सा था, जब इन्होंने चुनाव को डिले करा। सबको हटा दिया। अब अस्पतालों के पास में कोई चारा नहीं बचा, उन्होंने किसी ने गार्ड को बिठा दिया, किसी ने एनओ को बिठा दिया, किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया। अब जो पर्ची लिख रहा है उसे नाम लिखना नहीं आता। जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में भीड को देख के एम को एफ लिख दिया। मेल को फीमेल लिख दिया। ए 56 है जल्दबाजी में 26 चली गई, जाना है हड्डी के डॉक्टर पे और भेज दिया महिलाओं के डॉक्टर पे, अफरा तफरी, क्यूं? क्योंकि कहते हैं कि इनको कोई इसके अंदर AR स्टडी करनी थी। कमेटी ने रिकमंडेशंस दी अपनी और चीफ सैक्रेट्री साहब को कहा कि आप तीस दिनके अंदर इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट दीजिए और एक और रिकमंडेशन दी कि भारत के राष्ट्रपति होम मिनिस्ट्री के होम अफेयर्स में गवर्नमेंट जो अब इंडिया का है वो भी इसके उपर संज्ञान ले। अब आप देखिए कि चीफ सैक्रेट्री साहब इस का क्या जवाब देते हैं 08-06-2023 को It is observed that the Hon'ble Committee on Petitions of the Legislative Assembly of Delhi has undertaken investigations in day-to-day administrative matters of Government of NCT of Delhi which is prohibited in terms of first proviso to section ये कहते हैं ये रोज का काम है कमेटी को इसके अंदर अधिकार ही नहीं है कि वो किसी को बुलाए। 14 तारीख को जब ये मीटिंग हुई और चीफ सैक्रेट्री साहब से मैंने बार बार पूछा कि चीफ सैक्रेट्री साहब आपने इसमें लिखा है ये रोज का काम है डे-टू-डे, क्या ये आपको रोज का काम लगता है,

क्या दिल्ली में ऐसा रोज होता है? बार बार मेरे पूछने के बावजूद वो उसका जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा जी मैंने एक रिपोर्ट दे दी है अब मंत्री जी की मर्जी है इसे मानें ना मानें। तो मैंने उनसे पूछा कोई तो आधार होगा जो आपने लिखा है। तो उन्होंने कहा हमारे किसी साथी ने भी कहा कि ये ओपिनियन हो सकता है क्योंकि क्लीयर नहीं है कि डे-टू-डे में क्या क्या आता है, तो ये सबजैक्टिव हो सकता है लेकिन दिल्ली के चीफ सैक्रेट्री कुछ लिख रहे हैं वो सबजैक्टिव कैसे हो सकता है, वो ओपिनियन भी नहीं हो सकता। उसका कोई ना कोई बेस होना चाहिए। उन्होंने इतनी बड़ी लाईन लिखी है, उन्होंने हमारे अधिकारों पे, पेटीशन कमेटी के अधिकारों पर सवाल उठाया है, ऐसे ही थोड़े लिख देंगे, लेकिन बार बार पूछने के बाद भी चीफ सैक्रेट्री साहब कहते रहे कि मैं आपको इसका लिखित में जवाब दे दूंगा जबकि वो सामने बैठे थे, हम सामने बैठे थे, अधिकारी सामने बैठे थे। समिति के सदस्य वहीं बैठे थे, जवाब तभी दिया जा सकता था लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लिखित में जवाब दूंगा, अभी जवाब नहीं दे पाएंगे। खैर, उनके साथ में उसी वक्त फाइनेंस सैक्रेट्री साहब बैठे थे और ड्यूसिब की सीइओ मैडम बैठी थीं, जब मैंने फाइनेंस सैक्रेट्री साहब से ये बात पूछी कि फाइनेंस सैक्रेट्री साहब आप दिल्ली के नंबर टू हैं, मालिक हैं दिल्ली के, तो आपकी नजर में ऐसा कितनी बार हुआ कि मौहल्ला कलीनिक में काम करने वाले लोगों को एकदम से हटा दिया जाए या सॉरी हॉस्पिटल के अंदर जो काम कर रहे थे डेटा एंट्री ऑपरेटर उनको हटा दिया जाए।..

श्री विजेंद्र गुप्ताः रिपोर्ट की कापी तो दे दो।

माननीया अध्यक्षः आप बाहर थे इसपे बात हो गई है। अभी जैसे ही ये रिपोर्ट पेश होगी, जैसे ही पटल पर आ जाएगी, आपको कापी मिल जाएगी।

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ताः अरे विजेंद्र जी रिपोर्ट बाद में ही तो मिलेगी पहले कैसे दे दें। पहले पेश तो होने दो, पेश तो होने दो।

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ताः मैं कर रहा हूं ना पेश। कर रहा हूं पांच मिनट रूको।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आपके सुधार के..

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ताः वो अभी किसी के पास नहीं है भाई

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप जिस विषय पर मुझसे बात कर चुके, पहले एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जिस विषय पर आप मुझसे बात कर चुके हैं उसकी मैंने रूलिंग आपको दे दी। विजेंद्र गुप्ता जी उस वक्त बाहर थे या तो आप उन्हें कन्वींस कर दीजिए मैं

तो आपको कर चुकी हूं। मैं सदन को भी कनवींस कर चुकी हूं। अब कोई बाहर होगा आकर फिर बात करेगा, वो तरीका नहीं है। आप एक बार पटल पर पेश कर दीजिए।

श्री राजेश गुप्ताः पहले पेश कर दूं।

माननीया अध्यक्षः प्रस्तुत कर दीजिए रिपोर्ट एक बार।

श्री राजेश गुप्ताः एकदम से पढ़ लेंगे, स्कैन थोड़ी कर लेंगे।

माननीया अध्यक्षः कर दीजिए न।

श्री राजेश गुप्ताः इनको तो इंग्लिश में ही देना।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः हो रही है ना बात वहां। मतलब या तो बिधूड़ी जी, बिधूड़ी जी फिर आप ना बोलें, ये सब बोल लेंगे।

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ताः बिधूड़ी जी हम आपकी बात मान रहे हैं। आप अपने पूर्व गवर्नर साहब की एक बात मान लो बस। अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत ना करने के संबंध में याचिका समिति का चौथा अंतरिम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूँ।[2]

---

[1]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–23195 पर उपलब्ध।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: माननीया अध्यक्षा महोदया मैं श्री राजेश गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत याचिका समिति की चतुर्थ प्रतिवेदन का मैं समर्थन करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको टेबल पर प्रस्तुत करने की अनुमति दें।

माननीया अध्यक्ष: धन्यवाद जी। सबसे पहले इधर, इधर दीजिए सबसे पहले। सबसे पहले इधर दीजिए। अब आप शुरू कीजिए।

श्री राजेश गुप्ता: अब इनके पढने तक का इंतजार करना पड़ेगा।

माननीया अध्यक्ष: बस चाहिए डिस्टर्ब करने के लिए मुद्दा।

श्री राजेश गुप्ता: तो बिधूड़ी जी पढ़ूं आगे। आपका आदेश हो तो।.. इसमें फाइनेंस सैक्रेट्री साहब से जब मैंने पूछा के उस समिति में जो मैम्बर्स हैं तीन बार के विधायक या दो बार के हैं, हॉस्पिटल्स को देखते आए हैं, हमारी विधानसभाओं में अस्पताल है। मैं पार्लियामेंट सैक्रेट्री, हॉस्पिटल भी रह चुका हूं। मैंने अपने दस साल, नौ साल के जो मेरा विधायक होने का तजुर्बा है, कभी ऐसा नहीं देखा कि एकदम से किसी को ऐसे हटा दिया जाए। तो उनसे पूछा क्या ये डे-टू-डे है। उन्होंने कहा नहीं ये डे-टू-डे नहीं है। ये रोज नहीं होता। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तो चीफ सैक्रेट्री साहब ने क्यूं लिखाये डे-टू-डे है? ऐसे ही, यही बात ड्यूसिब की जो सीइओ मैडम है उनसे पूछा गया जो सोशल वेलफेयर को भी हैड करती हैं के जो पेंशंस रूकी चार महीने की

पेंशन, उस टाइम रूकी तो क्या ऐसा बार बार होता है जिस वजह से वो रूकीं, रूकने की कई वजह हो सकती हैं। थोड़ी बहुत रूक जाती हैं किसी वजह से लेकिन इतने बड़े ऐमाउंट में पूरी दिल्ली की पेंशंस बंद हो जाएं तो क्या ऐसा बार बार होता है? तो उनका भी जवाब था ऐसा बार बार नहीं होता। तो फिर चीफ सैक्रेट्री साहब ने क्यूं लिखा कि पेटीशन कमेटी को अधिकार नहीं है कि वो समिति बुलाए क्योंकि ये डे–टू–डे का मैटर है। दिल्ली में चार महीने पेंशन नहीं आती, दिल्ली के अस्पतालों में अफरा तफरी हो जाती है। दिल्ली के मौहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिलती और इसको ये कह दिया जाए कि डे–टू–डे है नहीं ये rarest of the rare है, ये डे–टू–डे नहीं है। ये लिखने के बाद में आगे ये लिखते हैं and also dragged the name of hon'ble LG in the subject of these interim reports without any evidence हमने तो नाम लिया नहीं लिया, उन्होंने जरूर इसमें लिखा हुआ है These actions are not in terms of the provisions of proviso to section 33(1) of the GNCTD Act, 1991 and also unconstitutional as allegations in the title of the interim reports have been made against the Hon'ble Lt. Governor without any basis. अब आप देखिए कि पूछा क्या जा रहा है जवाब क्या आ रहा है। इस पे ये कोई चर्चा नहीं है कि किन अधिकारियों से गलती हुई या दोष है, उस पे बात नहीं हो रही बस ये है कि बुलाओ मत, कोई कमेटी मत बुलाओ Accordingly, it is proposed that the facts mentioned in para 17 &

18 above may be added suitably in draft ATRs to these reports. In addition to proposals at paras 16 and 19, it is proposed that since the matter involves violation of Proviso to section 33(1) of the GNCTD Act, 1991, therefore, these drat ATRs be placed before the Hon'ble Lt. Governor for prior opinion in terms of Proviso to Section 44 (2) of the GNCTD Act read with para 1 of the Order dated 28.04.2021 issued by the office of Hon'ble Lt. Governor किये जो कुछ भी है पहले परमीशन ले लो एलजी साहब से। दिल्ली के चुने हुए अधिकारी, दिल्ली के चुने हुए विधायक या समिति उनसे कुछ ना पूछे। ये भी गवर्नर साहब पूछेगें कि लगाएगा कौन, हटाएगा कौन, हटा दिया तो हटा क्यूं दिया ये भी वो पूछेगें। यानि के इस विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। जो लिखना था उन्होंने बिल्कुल खुद लिखा हुआ है इसके अंदर जिसके लिए वो कह रहे हैं कि मैं लिखित में जवाब दूंगा जो उन्होंने खुद साइन करे हुए हैं इसके अंदर as the matter in First Interim Report also involves engagement of manpower through outsourcing (which is a Services matter), therefore the file may also be submitted before the Hon'ble Lt. Governor on draft ATR on First Interim Report for approval pursuant to insertion of section 3 A in the GNCTD Act, 1991 on 19.05.2023 through the GNCTD (Amendment) Ordinance, 2023 अब ये सर्विसिज़ का मैटर भी है तो अब आप जो अस्पतालों के अंदर सात आठ, दस लड़के बैठे होते हैं, लड़कियां बैठी होती हैं वो outsourcing से

भी जो आप लोग लेते हैं वो भी सर्विसिज़ का मैटर है। सिर्फ बड़े अधिकारियों की बात नहीं हो रही, ये उन बच्चों की बात हो रही है जिनकी तनख्वाह 17 अटठारह बीस हजार जो semi-skilled में आते हैं उनको भी अगर रखना है तो गवर्नर साहब रखेंगे, साफ साफ खुद लिख के दिया हुआ है जिसके लिए उन्होंने ये मैं फिर कह रहा हूं कि जवाब नहीं दिए, उन्होंने कहा कि मैं लिखित में जवाब दूंगा The file was thereafter submitted to the Hon'ble Minister of Social Welfare. The Hon'ble Minister stated in his note dated 15.06.2023 that he was inclined to forward the draft Action Taken Report. The file was thereafter submitted to the Hon'ble Minister of Health. The Hon'ble Minister of Health in his note dated 18th August,2023 observed that as the Committee had recommended action against the Chief Secretary and other Officers '..the Chief Secretary has reasons to stall the Action Taken Report, therefore as an afterthought on 08.06.2023, tried to stall the report on the pretext of section 33 (1) of the GNCTD (Amendment) Act.' The Hon'ble Minister also pointed out that this action of the Chief Secretary was against the directions of the Hon'ble Speaker, who is the final authority in these matters.

The Committee agrees with the opinion of the Hon'ble Minister. On 06.03.2023, the Hon'ble Speaker had convened a meeting which was attended by the Hon'ble Chairpersons as well as the Chief

Secretary and other officers of the Government. In the meeting the Hon'ble Speaker conveyed his decision that अब देखिए ये स्पीकर साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाकर, चेयरपर्सनस को बुलाकर, बिल्कुल साफ हिदायत दी, विधान सभा के अंदर बुलाकर, की No officer should absent himself from the sittings of the Committee without the prior permission of the Hon'ble Chairperson. उसके बावजूद ये सुबह-सुबह चिट्ठी भेज देते हैं, किसी ना किसी बहाने के साथ में। कोई छुट्टी पे भाग जाता है, कोई कहता है मुझे वहां बुला लिया, कोई कहता है जी पहले ये रिपोर्ट दे दो। उस दिन सेम जिस दिन मीटिंग हो, 9 मैंबर समिति के वहां पहुंचते हैं, अपने काम धंधे छोड़ कर लेकिन officers का जो रवैया है वो ये है, All information sought by the Committee or the Assembly should be promptly furnished. In case the Department has any reservation in providing information/ documents, the matter should be brought to the notice of the concerned Minister who, in turn, will take it up with the Hon'ble Speaker. The Speaker's decision in this matter would be final और इसमें समिति ने ये भी किया कि एक बारी बताया गया कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई हुई है, हमें वहां जाना है, उसी वक्त मैंने ओनरेबल मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी को फोन लगाया, उनसे बात हुई और उन्होंने तभी कह दिया कि नहीं समिति की बैठक पहले जरूरी है, पहले वहां अफसरों को इन्होंने हिदायत दी कि पहले आप वहां जाएं। उसके बावजूद वो बहाना

देते हैं की हमको तो वहां बुला लिया। This decision of the Hon'ble Speaker was communicated to the Hon'ble Chief Minister and the Chief Secretary vide DO Letter dated 06.03.2023. In the enclosed note to the letter which had been shared with the Chief Secretary in the meeting the Hon'ble Speaker had made it clear that 'matters of ‘day-to-day administration' are not considered by the Committees. The phrase ‘day-to-day administration" has not been defined anywhere. In the absence of any definition, the Speaker is the final authority to interpret the same. कहीं नहीं लिखा की डे–टू–डे है क्या। तो स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे, चीफ सेक्रेटरी डिसाइड नहीं करेंगे। The inherent powers of the Speaker of the Delhi Assembly in this regard are similar to those exercised by the Lok Sabha Speaker. All the Committees function under the overall supervision of the Speaker. The Agenda of the proposed sitting is finalized with the approval of the Speaker and any challenge or defiance in this regard can tantamount to a breach of privilege or contempt.

The NCT (Amendment) act, 2021 also places a restriction on the Committees to not conduct any inquiries on administrative decisions. As mentioned earlier, till a decision of the Hon'ble Supreme Court in this matter, none of the Committees of the Delhi Assembly are conducting any ‘inquiry". हम कोई इन्कवायरी उसमें

नहीं कर रहे हैं, ना करते हैं। The Committees examine the issues before them and recommend certain action or measures. If the Government does not agree with these recommendations, they can express their reasons in their ATNs ` मेरी कोशिश थी, वो लोग एल जी गैलरी में आप आएं, शायद आ नहीं पाया अभी। 4 महीने उसकी सैलरी पूरी जीरो हो गई, उसका घर उसी चीज पर चलता है, वो हैंडीकैप बच्चा है। इनको पता भी नहीं है कि राजनीति में कैसे-कैसे गलत काम ये कर रहे हैं। उसमें एक आदमी था जिसकी औरत pregnant थी और वो रोने लगा घर पर आकर, की मेरी औरत भी मर जाएगी, बच्चा भी मर जाएगा। क्योंकि कमाने-खाने के तरीके नहीं है, इतने पढ़े-लिखे वो बच्चे हैं, थोड़ा बहुत कम्प्यूटर जानते हैं, तो ये भीख भी नहीं मांग सकते। क्या करें? इनको कोई मतलब नहीं है। इन्हें राजनीति करनी है। अब ये कह देंगे उनमें से भी कोई मेरा रिश्तेदार था, जैसे कल इन्होंने करा, संजीव जी के रिश्तेदार थे, बंदना जी के रिश्तेदार थे। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि विजेंद्र गुप्ता जी मेरे रिश्तेदार थे इसलिए पिछली बार इनको एलओपी बना दिया। मैं राजेश गुप्ता हूं, ये विजेंद्र गुप्ता हैं, तो आरोप लगा लो। बोल लें, इसमें क्या जाता है।.. नहीं गुप्ता-गुप्ता तो सेम ही मिल गया ना। अब बताओ इस तरीके की मनगढ़ंत बातें करना और अफसरों को ऐसे दबा के रखना कि सिंपल-सिंपल तीन चीजें हैं, तीनों समितियों में हमने ये बार-बार पूछा कि किसी की तो गलती रही होगी। अरे फांसी थोड़ी देनी है किसी को, ये तो

बता दो की किसकी गलती से मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर्स की सैलरी रूकी। जब आप पे पैसे थे, सरकार पर पैसे थे, मंत्री जी देना चाहते हैं, तो रूके कैसे। पैंशन रूकी, कितनी विधवा औरतें, कितनी परेशान हुई होंगी, वो ढ़ाई हजार रुपए कईयों का घर चलाते हैं। तुमने वो रोक दिया, अरे कोई तो जिम्मेवार होगा, बताने को तैयार नहीं चीफ सेक्रेटरी साहब। कौन उन बच्चों को जो नौकरी से हटाया, कौन जिम्मेवार है नाम बता दो, उसका नाम उसमें लिख दो, कोई तो जिम्मेवार होगा। कहते हैं एल जी साहब पर रिपोर्ट भेजो, सर्विसिज का मैटर है, डे–टू–डे की बात है, कोई तो जिम्मेवार होगा। सिर्फ उसएक चुनाव के लिए आपने कितने लोगों को तंग करा, हो सकता है कोई मर गया हो बेचारा, हो सकता है कोई बीमार हो गया हो उस दौरान। लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं। इसलिए ये समिति आपके सामने रिकमंडेशंस दे रही है। The Committee is of the opinion that the Chief Secretary, the Principal Secretary (Finance), the Secretary (Health) and the Secretary (Social Welfare) have willfully attempted to stall and delay the submission of the ATRs to the Assembly. Further, as is evident by the language in his note, the Chief Secretary has defied the directions of the Hon'ble Speaker and the decision of the House.

The Committee recommends that the matter of non submission of ATRs to the Assembly should be referred to the Committee of

Privileges for detailed examination and report so that the guilty officer(s) can be identified and punished as deemed fit.

ये आपके सामने रिकमंडेशन है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर विपक्ष के साथी भी बिल्कुल मानेंगे, जब यहां अधिकारी नहीं होते, ये भी जानते हैं ये गलत है, इनको भी तकलीफ होती है, ये भी सवाल रखते हैं और इनके इलाके के अंदर भी बुजुर्ग लोग थे, विधवा महिलाएं थी जिनको पेंशन नहीं मिली, इनके यहां भी हॉस्पिटल में लोग परेशान हुए हैं, इनके यहां भी मोहल्ला क्लीनिक में दिक्कतें आई हैं। मेरा मानना है कि जब वो अपनी बात रखेंगे तो वो भी ये चाहेंगे अगर किसी ने गलत किया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ये रिपोर्ट आपके सामने पेश करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद जी, अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्षा महोदया। मैं अपनी बात पूर्व अमेरिकी सीनेंटर लेट एडवर्ड कैनेडी के शब्दों से शुरू करूंगा, जिन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार है ना कि विशेषाधिकार। ये सब किसी भी देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित बुनियादी सेवाएं देने के लिए एक बुनियादी सिद्धांत है। स्वास्थ्य सेवाएं विशेष रूप से उन विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है जहां घनी आबादी होती है। औसतन नागरिक की

वेतन चिकित्सा की भारी लागत को सहने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए और नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सरकारों को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत हर भरसक प्रयास करना चाहिए और इसी प्रयास को पूरा करने के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हमेशा स्वास्थ्य को अपने priority पर रखा और उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक का मॉडल पूरे देश को एक प्राथमिक स्वास्थ्य मॉडल के रूप में स्थापित करके दिया। अध्यक्षा महोदया, यही नहीं भारतीय संविधान के अनुछेद–10 में ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है कि अपने सभी नागरिकों के लिए निशुल्क और सस्ती स्वास्थ्य की व्यवस्था की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करे। अध्यक्षा महोदया, भारतीय राज्य के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद स्वतंत्रता के बाद देश में केवल 17 प्रसेंट लोग ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य बीमा हुआ पड़ा है, बाकी 65 प्रसेंट से ज्यादा लोग अभी–भी अपने खुद के खर्च पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं का निर्वहन करते हैं। ऐसे में राज्यों की जिम्मेदारी बहुत महती हो जाती है और इसी जिम्मेदारी को हमारी सरकार ने बखूबी से समझा, लेकिन आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है अध्यक्षा महोदया कि जो स्वास्थ्य की नीति, कल्याणकारी नीति आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में चल रहा है उसको derail करने के लिए दिल्ली के तमाम अधिकारियों ने, दिल्ली के एल जी के इशारे पर उसको रोकने का काम करने का काम

किया है। अध्यक्षा महोदया, एक याची के रूप में श्री धर्मेन्द्र कुमार ने एक याचिका दी कि दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिकों में डॉक्टरों की सैलरी रोक दी गई है। मोहल्ला क्लीनिकों में दवाइयों की खरीद रूक गई है। दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिकों में जो खून की जांचें होती है निशुल्क वो रोक दी गई हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिकों में जो साफ-सफाई के लिए दैनिक दिनचर्या के लिए खर्चे आते थे उसको रोक दिया गया है। वाई-फाई के खर्चे रोक दिए गए हैं। छोटी-छोटी चीजें, बिजली के रिचार्ज के लिए कूपन को रोक दिया गया है और दिल्ली के जो स्वास्थ्य के मॉडल का नमूना पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था मोहल्ला क्लीनिक उसको ठप्प करने की कोशिश की गई है। ये एक याचिका आती है। अभी विपक्ष कल से बोल रहा है तमाम पेपरों में सुर्खियॉं पाने के लिए, आज मिला भी है उनको की जनता के मुद्दों को उठाने का मौका नहीं मिलता सदन में। अरे आप गम्भीर होते इतने तो ये मुद्दे धर्मेंद्र कुमार को नहीं उठाना पड़ता, इस मुद्दे को भाई गुलाब सिंह यादव जी को इसको रैर नहीं करना पड़ता पेटिशन कमेटी को। जो काम विपक्ष का था वो भी काम हमारे सत्तापक्ष के साथी कर रहे हैं, ये आपको शर्म आनी चाहिए विपक्ष के रूप में। आप जनता के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, आप अपनी राजनीतिक रोटियॉं सेकने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार को बदनाम करने के लिए केवल अपनी राजनीतिक रोटियॉं सेकते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के लोग देख रहे हैं और इसीलिए आप लोगों को हरा रहे

हैं, चुनाव–दर–चुनाव। दिल्ली में तीन बार हार गए, एमसीडी में सुपड़ा साफ हो गया, अब 2024 आ रहा है वहां भी साफ होने का डर है, इसीलिए थोड़ा हड़बड़ाहट ज्यादा है। हड़बड़ाहट ज्यादा है इसीलिए, इसीलिए और और बताना चाहता हूं कि ये जो रिपोर्ट हमने 19 जनवरी को प्रस्तुत किया था अगर उस रिपोर्ट को पढ़ लिए होते हमारे, कल बोल रहे थे महावर जी, अगर इस रिपोर्ट को पढ़ लिये होते तो उस रिपोर्ट में लिखा गया है, पहले पन्ने पर ही कि मैं अध्यक्ष के रूप में धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने सचिवालय के समस्त सदस्यों का जिन्होंने इसको रिपोर्ट को बनाने में सहयोग किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन फैलोज का खासकर के मनीष रंगनाथन को और सिद्धार्थ सिंह को जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाने में, जांच में बहुत सहयोग किया। अगर आप पढ़ लिए होते तो आप ये कल नहीं कहते कि फैलोज को जासूस के रूप में आपके यहां लगाया गया था। आप पढ़ने–लिखने वाले लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे थे।ये परम्परा है इन लोगों के यहां। इनके प्रधानमंत्री कम पढ़े–लिखे हैं, वो परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं कम पढ़–लिख करके। उसमें आपका दोष नहीं है, आप उस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिनये कह रहे थे कल किमुझे बताया जाए आज तक फैलोज ने क्या काम किया, मुझे नहीं पता। अरे पढ़ते–लिखते तो पता चल जाता कि इसी सदन में काम करने के नाते, इसी सदन ने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है और ये रिपोर्ट टेबल किया गया है। क्या काम कर रहे हैं वो

आपको पता चल जाता लेकिन मजबूर हैं आप, बदनाम करने के लिए कुछ तो बोलना ही है। और इस पर अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो एक मैं चाहता हूं कि एक शायरी के माध्यम से इनको शेयर के माध्यम से ये बता दें कि किस तरीके से ये जो है खाली बदनाम करने के लिए झूठ बोलते हैं, 'इतना भी आसान नहीं है, ये महावर जी के लिए खासकर के कहूंगा और बिधूड़ी जी बैठे हैं काफी जोश से बोलते हैं झूठ बड़ा सही तरीके से, इतना भी आसान नहीं है सबकुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना, अपने आपसे झूठ और दूसरों से सच बोलना, इतना आसान नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं सदन को गुमराह करने के लिए जनता को गुमराह करने के लिए। आज पूरा देश देख रहा है, आज पूरा सदन देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप हमेशा अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए रोहिंग्याओं का मैटर उठाते हैं। आप बताईये रोहिंग्या कहां से आए हैं? बंग्लादेश से आए है और वहां की सीमा दिल्ली की सीमा बंग्लादेश से सटी हुई नहीं है, आपकी केन्द्र सरकार के फेल्योर के नाते देश में रोहिंग्याओं का आगमन होता है। दिल्ली में पुलिस अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है उसको बाहर करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की, केन्द्र सरकार की थी, उसको बाहर नहीं करते आप। लैंड की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के पास है, एलजी के पास है। रोहिंग्या दिल्ली में बस जाते हैं उनको बाहर नहीं करते आप और कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने

रोहिंग्याओं को बसा दिया। झूठ बोलते हैं पूरे देश के सामने, शर्म नहीं आती आप लोगों को। उनको और नहीं वैधा तरीके से उनको अभी शिवचरण जी ने बताया आप लोग उनको फ्लैट आबंटित करने का काम करते हैं, बताईये और वो कहते हैं कि बसाने का काम रोहिंग्याओं को अपने करते हैं, उनको बुलाने का काम अपने करते हैं और इनका फेलियोर हो जाए तो कहा ये तो काम तो, गलती तो अरविंद केजरीवाल की है.. और सुन लीजिए आज से मैं भारतीय जनता पार्टी को भारतीय रोहिंग्या पार्टी कहता हूं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अजय महावर जी,

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः आप देशद्रोही पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी

....व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः अजय महावर जी,

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः देश में रोहिंग्याओं को घुसाकर के दिल्ली में बसाकर के दिल्ली और देश के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अजय महावर जी,

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः दिल्ली और देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए आप लोग देश को लड़ाने के लिए रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहे हैं देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अजय महावर जी बैठिए।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः आप सुन लीजिए रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहे हैं, देशद्रोही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः त्रिपाठी जी,

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः देशद्रोही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी.

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः त्रिपाठी जी, विषय पर रहें।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः जो अपने वोटबैंक की राजनीति के लिए रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने का काम करती है।

...व्यवधान.....

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः नहीं सुन पाओगे,

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः सही बात है, नहीं सुन पाओगे आप लोग, अभी भाग जाओगे, मुझे पता है आप भागने वाले हो, अभी भाग जाओगे।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अखिलेश त्रिपाठी जी।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अखिलेश त्रिपाठी जी।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः अरे हिम्मत है तो सुनो। हिम्मत है तो सुनो और जवाब देना कि रोहिंग्या जो दिल्ली में आकर बस गये लॉ एंड आर्डर की समस्या जब पैदा हुई वो किसकी जिम्मेदारी

है अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है या केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदी की सरकार की जिम्मेदारी है, बताओ।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अखिलेश त्रिपाठी जी,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अखिलेश त्रिपाठी जी, विषय पर रहिये।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः विषय पर आ रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः त्रिपाठी जी विषय, मैं बात कर रही हूं न।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः बहुत पीड़ा हो रही है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बात कर रही हूं न, प्लीज बैठिए।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः हां, तो बैठिए ना आप.

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप लोग भी बात करते करते-करते मुद्दे से भटकते हैं बैठ जाईये न।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः महावर जी, बैठिये।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः रोहिंग्याओं को बसाकर के देश को गुमराह करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई है यहां पर।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः त्रिपाठी जी विषय पर रहिये।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः अब आपका नकाब छुपने वाला नहीं है और एक नकाब और उठा रहा हूं आज आप लोगों का।

माननीया अध्यक्षः त्रिपाठी जी विषय पर रहिये। आप चेयर को संबोधित करें।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः बस एक मिनट।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः त्रिपाठी जी आप चेयर को संबोधित करें इधर-उधर बात न करें आप, किसी का नाम न लें, विषय पर रहिये।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः मैं मुद्दे पर आ रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बहुत हो गया ॠतुराज जी,

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः मुद्दे पर आ रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः ॠतुराज जी बहुत हो गया, हो गया शांत हो जाईये।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के कल्याणकारी कामों से..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अब ये आप क्या कर रहे हैं अजय महावर जी।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अजय महावर जी अभी क्या कर रहे हैं, तरीका है कोईं

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः शांत होईये मैंने रूलिंग दे दी न, त्रिपाठी जी।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाले आप बोल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाले यहां बोल रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः विषय पर।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः अध्यक्षा जी, वो चुप नहीं हो रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः विषय पर रहिये।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: मैं अध्यक्ष महोदया एक बात और है कि जब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, डोर-स्टैप डिलीवरी या सर्विसेज, महिलाओं को फ्री बस यात्रा की कल्याणकारी योजनाओं से जब भारतीय जनता पार्टी घबराती है तो आरोप लगाती है कि भई जो दिल्ली में मंदिर हैं उसके पुजारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैं आज खड़े होकर कह रहा हूं अपनी पार्टी की तरफ से बिलकुल मिलना चाहिए, उनको सबको तनख्वाह मिलनी चाहिए मंदिर के पुजारियों को लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से वक बोर्ड का एक्ट केन्द्र की सरकार ने बनाया था, मैं आज मांग करता हूं नरेन्द्र मोदी की सरकार से, नरेन्द्र मोदी से मांग करता हूं कि अगर वो जनकल्याण के लिए पुजारियों के हित में हैं तो केन्द्र से एक्ट बनाएं और एक्ट बनाने के बाद उसको दिल्ली की सरकार पहली सरकार होगी जो उसको लागू करेगी और सबको सैलरी देने का काम करेगी। आप लागू करिये, नौटंकी करते हैं दिखावे की और मैं चाहता हूं कि जब अभी विपक्ष के नेता खड़े हों तो ये जवाब जरूर दें कि कौन सा ऐसा राज्य है भाजपा शासित..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: आप उन्हें बोल लेने दीजिए न, क्या है हर बात पर.

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः जहां पर इन्होंने ब्राह्मण पुजारियों को, पंडितों को, संतों को तनख्वाह देने का काम किया है ये जरूर बताएंगे, ये जरूर बताएंगे..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाइये आप।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः ये जरूर बताएंगे। ये बताएंगे। और जाकर के हर मंदिर में बताएंगे कि किसी भी अपने प्रदेश में कहीं भी ब्राह्मण पुजारियों को संतों को..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मैं सब सुन, सुन लिया मैंने वो..

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः और कहीं भी ये लोग तनख्वाह देने का काम नहीं करते हैं और दिल्ली में मांग करने का काम..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः त्रिपाठी जी, आप अपने वक्तव्य को खत्म करें।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः उस पर ही आ रहा हूं। अध्यक्षा जी, बस उसी में आ गया।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः खत्म करें आप अपने वक्तव्य को।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः हां, मैं आ गया।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अपने वक्तव्य को खत्म करें।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः आ गया, आ गया।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप अपने वक्तव्य को खत्म करें त्रिपाठी जी।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः अध्यक्ष महोदया, मैं उस समय जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत किये गये थे अंतरिम प्रतिवेदन प्रथम, द्वितीय, तृतीय मैं समिति का अध्यक्ष था, अभी भी समिति के सदस्य के रूप में एक-एक समिति की कार्यवाहियों को मैंने देखा है बहुत

बारीकी से अध्यक्षा महोदया ये फेल विपक्ष, फेल विपक्ष का काम भी सत्ता पक्ष के लोग आंदोलन की भट्टी से निकले हुए लोग अरविंद केजरीवाल के सिपाही लोग कर रहे हैं मैं अपने सदस्य साथियों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा दिल्ली की जनता के सुख-दुख के मुद्दों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं संघर्ष करते हैं।..

माननीया अध्यक्षः चलिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः एक मिनट और अध्यक्ष महोदया एक दो मुद्दे और रह गये हैं।

माननीया अध्यक्षः विषय को छोड़ देते हैं इधर-उधर की बातों में आ जाते हैं आप।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः अध्यक्षा महोदया, जब समिति ने वित्त सचिव को..

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः जब अध्यक्षा महोदय जब ये..

माननीया अध्यक्षः बोलिये।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः जब हम वित्त सचिव को बुलाते हैं, स्वास्थ्य सचिव को बुलाते हैं वो दोनों लोग समिति में आते हैं 16 दिसंबर, 2022 को पहली बार समिति नोटिस जारी करती है, 20 तारीख को पहली मीटिंग रखी जाती है और मीटिंग में जब

पूछा जाता है कि क्या कारण है कि मोहल्ला क्लीनिक में लोगों का ईलाज करने वाले डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी गई है, क्या कारण है कि जो जरूरी जांचें हैं, खून की जांचें हैं, जो अरविंद केजरीवाल की सरकारी के द्वारा निशुल्क दी जाती हैं उसको क्यों रोक दिया गया है, दवाईयां क्यों नहीं मिल पा रही हैं, मोहल्ला क्लीनिकों में, रिचार्ज क्यों नहीं हो पा रहा है सफाई के लिए, जरूरी जो छोटे-मोटे खर्च हैं वो क्यों रोक दिये गये हैं, वाईफाई का और बिजली का रिचार्ज क्यों रोक दिया गया है, तो अध्यक्षा महोदया स्वास्थ्य विभाग के सचिव कहते हैं कि ये जो देरी हुई है वो वित्त विभाग की लापरवाही से हुई है क्योंकि वित्त विभाग ने जो आवश्यक अनुमति थी वो समय रहते नहीं दी है। जब वित्त सचिव से इसके बारे में पूछा गया कि भई आपकी लापरवाही के बारे में स्वास्थ्य सचिव ने ऑन ओथ कमेटी में गवाही दी है तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो गलती है वाकई में वो स्वास्थ्य विभाग के सचिव की तरफ से है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है क्योंकि उन्होंने अनुमति मांगने में लेट किया है और जब लेट किया है तो इसीलिए अनुमति लेट से दी गई है। जब समिति ने इन दोनों बातों की जांच शुरु की..

माननीया अध्यक्षः कंप्लीट कीजिए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः अध्यक्षा महोदया, तो जो घोर लापरवाही देखने में आई उसके बारे में समय कम है इसलिए मैं उसको स्किप करता हूं कि विभाग ने बार-बार रिक्वेस्ट किया

स्वास्थ्य सचिव से कि भई इस तरीके से समस्याएं आ रही हैं जून, जुलाई, अगस्त के महीने में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में तनख्वाह नहीं मिल पा रही है डॉक्टरों को, कुछ करिये लेकिन वित्त सचिव महोदय एलजी साहब के आदेशानुसार दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग को पंगु करने का काम कर रहे थे। अध्यक्षा महोदया, जब कहा गया कि इसकी जानकारी मुख्य-सचिव को दिया जाएगा तो वित्त सचिव ने जवाब दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा तो काम है वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करना और मैं वही कर रहा था। मेरे लिए जनता कभी प्राथमिकता में नहीं है। पूरी समिति इस बात को सुनकर के शॉक हुई थी कि एक अधि कारी के लिए वित्तीय नियम, वित्तीय अनुशासन जनता से सर्वोपरि हो गया। तब सवाल उठता है कि लोकतंत्र के मंदिर के प्रति जवाबदेही कम करने की कोशिश केन्द्र की सरकार एलजी को शासन देकर के करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्यों केन्द्र की सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली में अधिकारियों के माध्यम से घुसकर के दिल्ली की सरकार के कामों को रोकना चाहती है। आज जब मुख्य सचिव को बुलाया गया कि भई आपके अधिकारियों के बारे में ये घोर अनियमितता पाई गई है, इन सभी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से दिल्ली के लाखों गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाओं से महरूम रहना पड़ा। उनको कई लोगों को बीमारियां जो समय से जांच हो जाती तो रुक जाती, वो नहीं रुक पाई, आगे बढ़ गईं इस उदासीनता के कारण, इन पर कार्रवाई करिये। तो जो मुख्य सचिव महोदय थे..

माननीया अध्यक्षः आप कंप्लीट कीजिए बहुत देर हो गई है।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः जिनके कहने पर, समय देने पर उनको बुलाया गया कि भई आप किस समय आ सकते हैं, उन्होंने कहा, जी 6 बजे आ सकते हैं शाम को। समिति ने कहा ठीक है जी आप 6 बजे आ जाईये, वो 6 बजे आए उनके साथ बैठे, समिति ने विमर्ष किया और जब मुख्य सचिव को बताया कि भई ऐसी–ऐसी समस्याएं थी आपके यहां, तो उन्होंने कहा जी देखो जी हमें जानकारी नहीं थी इन बातों की कि दिल्ली में कुछ ऐसे स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी चल रही है। समिति ने यह भी बताया कि केवल मोहल्ला क्लीनिक ही नहीं बल्कि अस्पतालों में ओपीडी के काउंटर पर बैठने वाले जो मल्टी टास्किंग जो स्टाफ थे उसको भी हटा दिया गया है जिससे ओपीडी ठप्प हो गये हैं बड़े–बड़े अस्पतालों के। समिति ने उनको ये भी बताया कि भई बुजुर्गों के, विधवाओं के, विक्लांगों के आवश्यक जरूरतमंद लोगों की पेंशन रोक दी गई हैं, डीटीसी के कर्मचारियों की पेंशन रोक दी गई है। समिति ने ये भी बताया कि डीटीसी के मार्शलों की तनख्वाह रोक दी गई है। समिति ने उनको यह भी बताया कि वित्त विभाग के द्वारा जलबोर्ड के छोटे से छोटे काम को रोक दिया गया है आप इस पर कार्यवाही करिये। तो मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। तो माननीय सदस्य उस समय सौरभ भारद्वाज जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने पूछा उनसे कि आप ये बताईये कि क्या आप अखबार पढ़ते हैं? बोले सारे

अखबार नहीं पढ़ते कुछ अखबार पढ़ते हैं। समिति को गुमराह करने की कोशिश की मुख्य सचिव ने जबकि यह बेसिक रूल है कि कोई भी आईएएस अफसर होता है उसके ऑफिस में सुबह-सुबह सबसे पहले कोई भी जितने प्रमुख अखबार हैं उसकी मुख्य कटिंग उसके विभाग से संबंधित एक कटिंग के माध्यम से उसके टेबल पर रखा जाता है ताकी वो उसके विभाग में क्या चल रहा है उसको जानकारी हो जाए।..

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः और इस पढ़ने के बावजूद भी वो गुमराह करते रहे समिति को।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद, बहुत सारे वक्ता हैं इस विषय पर बहुत सारे वक्ता हैं।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः एक बात और, और उनसे पूछा गया जब समिति में की आप अगर गुमराह रहे तो आप बताईये कि आप अपने हैड आफ डिपार्टमेंट से कितने दिनों में एक बार में मिल लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि तीन-चार हफ्तों में एक बार मिल लेते हैं। तो समिति ने उनसे कहा की भई तीन-चार हफ्तों में मिल लेते हैं तो तीन महीने हो गये इन बातों को दोहराते हुए, तो आप अपने जो है सचिवों से तीन-चार बार तो मिल गये होंगे तो आपके वित्त विभाग के सचिव और स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने या समाज कल्याण विभाग के सचिव ने, जलबोर्ड के सीईओ ने

अगर आपको इस बात की सूचना नहीं दी तो यानि कि तथ्य को मुख्य सचिव से छिपाया है तो आप इसके लिए क्यों कार्रवाई नहीं करते, इस पर वो चुप्पी साधा लिये। इसका मतलब साफ था अध्यक्षा महोदया, कि मुख्य सचिव भी इन सब काम रोकने की कार्रवाई में शामिल थे और मुख्य सचिव किसके इशारे पर काम कर रहे थे, इस सदन के एक-एक सदस्य को पता चल गया है एलजी के इशारे पर दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक को, दिल्ली के जलबोर्ड को, दिल्ली के डीटीसी को, दिल्ली के पेंशनधारी लोगों के पेंशन को रोकने के लिए पूरा षड़यंत्र रचा गया अधिकारियों के द्वारा..

माननीया अध्यक्षः चलिये बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः और दिल्ली को ठप्प कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई पूरी तरीके से होनी चाहिए।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद, विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः एक मिनट मैं एक बात रखना चाहूंगा।

माननीया अध्यक्षः गुप्ता जी बैठ जाईये एक बार, हां जी।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः आप बैठ जाईये।

माननीया अध्यक्षः नहीं, अभी मैं आपको नहीं दे रही परमिशन। आपको परमिशन नहीं मिलरही है। अगर आप जबरदस्ती बोलेंगे आपका नाम आया, मैं आपको मौका नहीं दूंगी फिर।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्षा जी, यहां पर एक Forth interim report committee on Petitions इसके पहले पेज पर जब कमेटी की फार्मेशन हुई पिटिशन कमेटी की तो तभी नियम और कानून का उल्लंघन हो गया पहला, कमेटी के चेयरमैन हैं राजेश गुप्ता, मेंबर्स हैं, राजेश गुप्ता फ्राम आम आदमी पार्टी, अखिलेश पति त्रिपाठी, आम आदमी पार्टी श्री बी एस जून, आम आदमी पार्टी, श्री दिलीप कुमार पांडेय, आम आदमी पार्टी, श्री जयभगवान, आम आदमी पार्टी श्री करतार सिंह तंवर, आम आदमी पार्टी, श्री कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी, श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों, आम आदमी पार्टी, श्री सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी बीजेपी का रिप्रजेंटेशन जीरो।.. अध्यक्ष महोदया, अध्यक्षा जी मुझे आप समय तय कर दीजिये मैं चाहूंगा कि मुझे जितना समय आप दें मैं उतने समय में अपनी बात कर लूं।

माननीया अध्यक्षः आप 8 मिनट में बोलिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः और विपक्ष के जो सतारूढ़ दल है,

माननीया अध्यक्षः आप 8 मिनट में बोलिये एक बजकर 12 मिनट हो रहे हैं आप एक बीस तक बोलिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः ठीक है। और मैं आदरणीय अध्यक्षा महोदय मैं चाहूंगा कि सदस्य जो हैं मेरी बात को भी सुनें। हमने कमेटी के प्रतिवेदन पर पूरा सुना है।

माननीया अध्यक्षः सत्तापक्ष के साथियों से निवेदन है आप सबको बोलना है, सबका नाम आया हुआ है, समय खराब न करें बिल्कुल।

श्री विजेंद्र गुप्ताः और मंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है बहुत जल्दी घबरा जाते हैं मेरे खड़े होने पे तो ये भी जरा xxxx[3]

माननीया अध्यक्षः ये मंत्री जी से ऐसे बात करने का कौन सा तरीका है।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः नहीं नहीं मैं उनको मेरे मित्र है वो।

माननीया अध्यक्षः ये कोई तरीका है इनके ये शब्द निकालें।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिये आप लोग।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिये। अजय दत्त जी बैठिये। अजय दत्त जी बैठिये।

---

[3]चिन्हित अंश अध्यक्षा महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः विजेंद्र गुप्ता जी सदन की कोई मर्यादा होती है माननीय मंत्री जी के लिये आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें!

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं मंत्री जी के सम्मान में..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप बहुत सीनियर हैं,

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः मंत्री जी बहुत काबिल हैं और मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, उनको बुरा लगा, मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं। ठीक है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः प्रमिला जी, अजय दत्त जी, सही राम जी बैठें। दिलीप पाण्डेय जी इन्हें बिठाईये। इनको बिठाईये।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः अध्यक्षा महोदया,..

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः इन्हें बिठाईये। भई पहले आप अपने शब्द वापिस लीजिये।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं अपने शब्द वापस लेता हूं,

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः क्योंकि विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः कुलदीप जी बैठिये। अजय दत्त जी बैठ जाईये। सही राम जी, प्रमिला जी, त्रिपाठी जी..

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईगो का कोई इशु नहीं है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाईये। कोई बात नहीं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः हर बात पर सफाई नहीं देनी होती है। आठ मिनट हैं आपके पास 8 मिनट में आप अपने शब्दों का सही प्रयोग कर अपनी बातें रखिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः ठीक ठीक।

माननीया अध्यक्षः और आप अपने शब्द् वापस लीजिये जो मंत्री जी के लिए आपने बोले हैं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः वो तो मैंने बोल तो दिया और कितनी बार बोलूं। मैंने बोल दिया। बोल दिया है मैंने।

माननीया अध्यक्षः हां, ये तरीका नहीं है सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। चलिये शुरू कीजिये।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः ठीक है जी। अब 9 में से proportionate कम से कम एक मेंबर हर कमेटी में है, पीटिशन कमेटी में क्यों नहीं है।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः देखिये मैडम अगर फिर मैं ऐसे कैसे बोलूंगा आप बताईये। क्यों डरते है इतना।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः ये आपको कमेंट करने के लिये किसने बोला है आपका नंबर आयेगा जब फिर आप बोलेंगे कि हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, विपक्ष टीका टिप्पणी कर रहा है।

श्री विजेंद्र गुप्ताः कमेटी के फॉर्मेशन में ही फॉल्ट है और अनजस्टिफिकेशन है कि विपक्ष को इसमें जानबूझ कर नहीं रखा गया क्योंकि पीटिशन कमेटी को मनमर्जी करनी थी। दूसरा इसमें 3 रिपोर्ट आई हैं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मैंने क्या कहा है हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है उनको जो बोलना है वो बोल लें।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः 3 रिपोर्ट आई हैं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अगर वो रूल बुक पढ़कर आते तो ऐसे ऑब्जेक्शन करते नहीं।

...व्यवधान...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः इस पर आरोप नहीं लगा सकते आप।

श्री विजेंद्र गुप्ताः दूसरा 3 रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट की बात की गयी है OPD counters in Delhi Govt. hospitals, old age pension and Mohalla Clinic. मैंने ये रिकमेंडेशन पढ़ी है। पहले तो ये जो तीन बातें हैं इसकी जवाबदेही सरकार में बैठे हुए जैसे स्वास्थ्य मंत्री श्री

सौरभ भारद्वाज जी की है और पेंशन के इशु पर जवाबदेही मंत्री आनंद जी की है। अब देखिये रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं। रिकमेंडेशन बता दे रहा हूं सारी पढूंगा तो टाईम लग जायेगा The Committee recommends that the hospital should purchase computer system of their own istead of issuing tender for the same. अब कमेटी कहती है कि हॉस्पिटल कंप्यूटर अपने आप खरीद लेगा कोई टेंडर नहीं करेगा। ये अब मैं दूसरा एक विषय आपके सामने रख दूं पूरी बात कहने से पहले, लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं पहला है विधायिका Legislature. क्या है विधायिका। आप सभी को ये बता दें कि यह लोकतंत्र का पहला स्तंभ होता है Legislature इसका कार्य देश में कानून बनाये रखना होता है, कानून बनाना। हमारे इस भारत देश में विधायिका का चुनाव हर 5 वर्षों में किया जाता है इसके बाद यह कुछ नियम व कानूनों का निर्माण भी करते हैं। इनके द्वारा बनाये नियमों को शासक व प्रजा दोनों पर लागू होते हैं। यानि कि लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, नियम बनाना और एग्जीक्यूटिव जिसमें मंत्रीगण भी आते हैं, कैबिनेट आती है उसका काम है एग्जीक्यूट करवाना।अब ये मंत्री डायरेक्शन देगा, कैबिनेट देगी कि हाउस की कमेटी देगी। आगे पढ़ता हूं जी। ‘the Committee recommends अब देखिये कमेटी ने क्या रिकमेंड किया। 'The Committee recommends that the privilege proceedings be initiated against Mr. Amit Singla Secy. Health Deptt., Dr. AC Verma, Pr. Secy., Sh. Manoj Sharma, Dy. Secy. misleading the Committee, disrespectful

conduct and attempting to conceal information from the Committee.' अब इसके बाद क्या लिखते हैं कि प्रिविलिज की कार्रवाई होनी चाहिये इनके खिलाफ, कौन करेगा 'the Chief Secy. Govt. of NCT of Delhi should submit an Action Taken Report on the above mentioned recommendations by the Committee to the Legislative Assembly of Delhi within 30 working days of the adoption of this report. अब प्रिविलिज की कार्रवाई अगर करनी है मैडम तो आप हैं यहां सर्वेसर्वा आप इस हाउस को चेयर कर रही हैं। अगर इस कमेटी को ये रिकमेंड करना था तो आपके पास करना था, इस हाउस को करना था कि इनके खिलाफ प्रिविलिज.. अब आप चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांग रहे हैं कि इनके खिलाफ प्रिविलिज की प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं की गयी, आगे। क्योंकि मैं सारा..

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः एक मिनट आप बोलना न।

माननीया अध्यक्षः मंत्री जी.

श्री विजेंद्र गुप्ताः आप बोलना भैया मुझे मालूम था आपको दिक्कत होगी प्लीज।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः अब आईये दूसरा।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः एक सेकिंड, गुप्ता जी एक सेकिंड।

श्री विजेंद्र गुप्ताः जी। जी।

माननीया अध्यक्षः एक सेकिंड। हांजी मंत्री जी।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैडम, मैं अपनी बात कह लूं आपने मुझे 8 मिनट दिये हैं उनको फिर उसके बाद वो बोल लेंगे। उनको प्रॉब्लम क्या हो गयी है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आपको आपके 8 मिनट मिलेंगे ही, आपको आपके 8 मिनट मिलेंगे ही।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः चलिये मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोलिये बोलिये। मैं फिर बोल लूंगा।

माननीया अध्यक्षः हांजी मंत्री जी।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): मुझे ये लगता है कि..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः भई मंत्री जी बोल रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्षा महोदया, हाउस के अंदर रिपोर्ट की कापी सब मेंबर्स को दी गयी और ये हाउस की प्रापर्टी है। हाउस की रिपोर्ट को झूठे ढंग से हाउस के सामने पेश करना अपने आप में प्रिविलिज है और कैसे है मैं अभी बताता हूं देखिये। वो जो रिकमेंडेशन पढ़ रहे हैं उसके अंदर रिकमेंडेशन जो चीफ सेक्रेटरी को दी गयी है वो ये है. 'The Committee recommends the Chief Secy., that the Chief Secy. take strict action against the Secy. Health, Pr. Secy. Finance for willfully causing delay in processing the files regarding Data Entry Operators in OPD counters. Privilege का काम तो यहां की कमेटी करेगी मगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, जो विजिलेंस की इंक्वायरी है, जो उनके उपर कार्रवाई करनी है वो तो चीफ सेक्रेटरी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा क्योंकि पावर तो आपने सारी खुद रख रखी है। समस्या ही तो ये है आप कह रहे हैं मंत्री की जवाबदेही है। मंत्री की जवाबदेही तो इस हाउस के प्रति है मगर अफसरों की जवाबदेही तो मंत्री के प्रति है, वो छीन के आप बैठे हुए हो, तो आप ले लो एक्शन। आपके बस की नहीं है तो हमें पावर वापिस दे दो हम लेकर दिखायेंगे एक्शन।

...व्यवधान...

श्री ओ.पी. शर्माः आपके पल्ले कुछ नहीं है?

माननीया अध्यक्षः चलिये। गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ता: ये मैडम एक मिनट,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: ये ओ.पी. शर्मा जी, बोलना है तो इनका नाम दीजिये भई ओ.पी. शर्मा जी को अगर बोलना है तो। बिना नाम के या बिना यहां परमिशन के कोई नहीं बोलेगा।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता: अध्यक्षा जी ये जो मैं पढ़ रहा हूं, हां बोलो आप, अब वो अकेला अब आप बोलो। मत बोलने दो क्योंकि पोल खुल रही है न, पोल खुल रही है सरकार की, सरकार की पोल खुल रही है इसीलिये वो मंत्री जी उनको कह रहे हैं आप बोलो।

माननीया अध्यक्ष: अगर गुप्ता जी..

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता: मुझे अपनी बात कहने दीजिये न। आप प्रिविलिज की कमेटी की कार्रवाई चीफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं। प्वाईंट नंबर 5 मैं पढ़ रहा हूं और 6 में कह रहे हैं आप नंबर 1 टू 5 प्रिविलिज जो है चीफ सेक्रेटरी करें। ये देखिये आप पढ़ा है मैं, पढ़िये आप पेज नंबर 23। हां, पढ़ लिया। ठीक है आगे। आगे चलिये। आगे चलिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप शब्दों को तोड़ मरोड़ के और रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ के पेश न करें तथ्यों के साथ ऐसे..

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः अच्छा अब आगे चलिये। अरे आपकी दी रिपोर्ट पढ़ रहा हूं भैया। The Committee recommends.

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आपके पास 3 मिनट और है गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः 'The Committee recommended that strict departmental action should be taken against the concerned District Social Welfare Officer, Lajpat Nagar, Mr. Vikas Pandey who failed to perform his duties and did not adhere to mandated protocol.' अब एककोई ए बी सी कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उसकी कमेटी ने क्या जांच की है, क्या उसका बैक ग्राउंड है कुछ इसके बारे में कुछ नहीं पता। सो ऐसा लग रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट जो है पूरी अगर मैं पढ़ूगा बहुत टाईम लग जायेगा लेकिन हर जगह मैं कुछ ग्लेयरिंग पढ़ रहा हूं बस। 'Social Welfare Department, GNCTD shall ensure that regular sensitisation programs be made a key component of the training modules for officials involved in public dealing. अब आईये तीसरी पे। तीसरी तो माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता: तीसरी में कमेटी प्रेजीडेंट आफ इंडिया को रिकमेंड कर रही है, उनको डायरेक्ट कर रही है The Committee humbly request—

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: ये सत्ता पक्ष के साथी शांति बनाये रखें। अजेश यादव जी।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता: सुनिये The Committee humbly -

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: मुझे पता है किसको कितने मिनट हो गये हैं आप शांति रखें।

श्री विजेंद्र गुप्ता: 'The Committee humbly requests the Hon'ble President of India and Ministry of Home Affairs, Govt. of India to take cognisance of this report of the Committee on Petition and take appropriate action against the Chief Secretary and the Hon'ble Lieutenant Governor.' अब कमेटी प्रेजीडेंट आफ इंडिया को रिकमेंड कर रही है और कह रही है कि चूंकि उन्होंने पीटिशन कमेटी के कहने पे एक्शन नहीं लिया चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ और एलजी के अगेंस्ट तो इसलिये हम जो है अब आगे देखिये

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः अब इस सारे उस में बड़े साफ और स्पष्ट रूप से मैं जैसा बता रहा था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ज्यूडिशियरी और जर्नलिज्म सबके काम बंटे हुए हैं। ये जो आपने 21 पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बनाये थे जिसको आपको वापस लेना पड़ा वो क्या था।..

माननीया अध्यक्षः विषय पे रहिये।

...व्यवधान....

श्री विजेंद्र गुप्ताः जब आपके वो नहीं रहे तो आपने पीटिशन और फिर इसमें अपोजिशन को क्यों नहीं रखा।..

माननीया अध्यक्षः विषय पर रहिये गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः और जो रिकमेंडेशन जितनी आपकी मैं पढ़ूं यहां पर हर रिकमेंडेशन contradictory है self goal है और जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसके बहाने दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा पंगु बनाने की कोशिश करना, उनको ब्लैकमेल करना, उनको मेंटल टॉर्चर करना, उनके कैरियर को खराब करने की धामकियां देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है दिल्ली में सरकार नहीं चल रही कोई गैंग चला रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है।..

माननीया अध्यक्षः चलिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ताः ये गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिये और ये पीटिशन कमेटी समाप्त होनी चाहिये क्योंकि इसकी legality पर भी सवाल खड़े हो गये हैं।

माननीया अध्यक्षः चलिये बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ताः क्वेश्चन मार्क है उसकी परफॉरमेंस पर, उनके एथिक्स पर, इनके एटीट्यूड पर और इनकी सिनसियरिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पूरी कमेटी को कमेटी को पूरा खत्म कर देना चाहिये..

माननीया अध्यक्षः चलिये बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश गुप्ता जी आप कुछ कह रहे थे।

श्री विजेंद्र गुप्ताः और अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि अपोजिशन का इसमें शेयर नहीं रखा गया, धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः एक बात बिल्कुल साफ है न इन्होंने कुछ पढ़ा बेवजह की बात कर दी आपने इन्हें समय दिया। प्लीज जरा विपक्ष के साथी थोड़ा पढ़ लें। रिकमेंडेशन सिर्फ ये 5 लाईन की थी सर जो अभी मैंने पढ़ी हैं। सिर्फ ये 5 जरा खोल के देखो इसको। आप पता नहीं कौन से जमाने का उठा के, वो पुरानी है सर। आप जनवरी की अभी पढ़ोगे।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः राजेश गुप्ता जी,..

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ताः ठीक है, ये 5 लाईनों की..

माननीया अध्यक्षः वन टू वन नहीं आपको चेयर को जो बोलना है बोलें।

श्री राजेश गुप्ताः ये 5 लाईन की रिकमेंडेशन दी है अभी जो मैंने पढ़ी है। पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि कैसे लोगों की इन्होंने नौकरियां खाई हैं वो बच्चा वहां खड़ा है आपकी अनुमति से मैं चाहता हूं वो खड़ा हो जाये वहां पे। खड़े हो जाओ बेटा। ये देखिये।

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ताः बिधूड़ी जी। आपके पीछे कोई खड़ा है जरा देख लो बिधूड़ी जी आपके पीछे देखिये बच्चा खड़ा हुआ है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः कुलदीप जी, बैठिये। बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाइये। वो बोल रहे हैं।

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ता: इस बच्चे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा आपने इसकी नौकरी छीन ली, इसकी नौकरी छीन ली और ऐसे परेशान करा है लोगों को,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: विजेंद्र गुप्ता जी बैठिये।

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ता: वो चल भी नहीं सकता जिसकी नौकरियां खत्म कर दी। अध्यक्षा जी मै चाहता हूं कि जरा इसे दिखाया जाये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: आपका विषय आ गया।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: आपका विषय आ गया।

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ता: हां परमिशन लेके करा है। ये रिकमेंडेशन है पढ़ लो पहले।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: मैंने परमिशन दी है। मैंने परमिशन दी है।

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ता: पढ़ो ये.

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: मैंने परमिशन दी है।

...व्यवधान...

श्री राजेश गुप्ता: कहा तो है इनकी परमिशन है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही दो बजे दोपहर के बाद दोबारा से शुरू करी जायेगी। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराहन् 2.22 बजे पुनः समवेत् हुआ।

माननीया अध्यक्ष (श्रीमती राखी बिरला) पीठासीन हुईं।

माननीया अध्यक्ष: देखिये मैं सभी सदस्यों से एक निवेदन करना चाहती हूं। आज आप लोगों ने बहुत समय खराब करा है, कल की तरह सदन सुचारू रूप से चलने में पक्ष और विपक्ष के साथी कृपया सहयोग करें और अभी जो पीटिशन कमेटी पर डिस्कशन हो रहा था इसमें बहुत सारे लोगों के नाम आये हैं और समय की

सीमा है तो मैं चाहती हूं कि मदन लाल जी अपना वक्तव्य शुरू करें।

श्री मदन लालः अध्यक्ष महोदया 2023 फरवरी में एमसीडी का इलेक्शन होना था उससे जरा सा पहले सरकार के कई विभागों ने जानबूझ कर दिल्ली के विभिन्न विभागों के काम को रोकना शुरू कर दिया। उनका केवल एक परपज़ था कि किसी तरह दिल्ली के डेवलपमेंट को डिरेल किया जाये, ऐसा प्रोसेस प्रैक्टिस में लाया जाये जिसके तहत जानबूझ कर सब डिपार्टमेंट्स में काम को रोका जा सके। उनमें सबसे ज्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट था मोहल्ला क्लिनिक का। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स की अचानक सेलेरी रोक दी गयी, दवाईयां आनी बंद हो गयी और उसके अलावा जब कभी भी शार्ट स्टाफ होता उसके बदले में किसी भी स्टाफ को देने की कोई जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली। ये एक ऐसा समय था..

...व्यवधान...

श्री मदन लालः अब विजेंद्र जी मैं आपसे..

माननीया अध्यक्षः मदन लाल जी आप चेयर से बात करिये। आज आप सुबह से विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी आज आप सुबह से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है। मैंने अभी बैठते ही, मैंने आपसे अभी बैठते ही निवेदन करा ये कोई तौर तरीके अच्छे नहीं हैं। सम्मानित सदस्य हैं आप। हां जी, मदन लाल जी।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्षा जी, मुझे बस यही बोलना है अभी जो कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी उस कमेटी के उपर एक तो विजेंद्र गुप्ता जी ने सवाल उठाये हैं, दूसरा उन्होंने आपके डिसीजन पर सवाल उठाये। तीसरा उन्होंने जो हाउस में कमेटी की रिपोर्ट पास की गयी उसके उपर सवाल उठाये और कमेटी की रिपोर्ट गलत तरीके से हाउस में पेश करी, तो निश्चित रूप से ये मैटर जो है प्रिविलिज का बनता है और इस मसले को प्रिविलिज कमेटी में भेजा जाये और जब तक सदन से इनको हटाया जाये, ये बहुत गंभीर विषय है मतलब किसी भी कमेटी के पास जो संवैधानिक अधिकार है विजेंद्र गुप्ता जी ने सीधा चैलेंज कर दिया है उसको। गलत बता दिया उस कमेटी की रिपोर्ट को।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी आप सुबह से माहौल तो खराब कर रहे हैं न। ये कोई तरीका नहीं है।

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमारः सभी मेरी बात से सहमत होंगे, सभी लोग सहमत हैं न, सभी लोग, पूरा हाउस सहमत है अध्यक्षा जी।.. ये मैटर प्रिविलिज का मैटर है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः ये कोई तरीका नहीं है अगर आप व्यवधान पैदा करेंगे अब अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो मुझे मजबूरी में कोई न कोई फैसला लेना पड़ेगा। बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिये।

...व्यवधान...

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्षा जी, ये मसला प्रिविलिज का मसला है मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि संवैधानिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिये इस मैटर को प्रिविलिज में भेजा जाये। मेरा आपसे निवेदन है।

...व्यवधान...

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं लगातार देख रहा हूं कि विजेंद्र गुप्ता जी हाउस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और ये पुराना है इनका आज का नहीं ये पहले से इनका इस तरह का रवैया रहा है.. और इसी संदर्भ में अध्यक्ष महोदय मैं विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 277(3)(ए)के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं चूंकि ये घटना कोई आज की नहीं है जब जब हाउस को डिस्टर्ब की जाती रही है विजेंद्र गुप्ता जी उसमें आगे रहे हैं। एक पहले से भी प्रिविलिज का मसला इनपर चलता रहा है जिसमें इसी हाउस में इन लोगों ने

अध्यक्ष जी जिसको लीड विजेंद्र गुप्ता जी ने किया था आपको याद होगा गंदे पानी लेकर आया था, लैब रिपोर्ट आया लैब रिपोर्ट में ये कहा गया कि उसमें इंक लगाया गया था और पानी कोई गंदा नहीं था। उसके बाद आज आपने देखा कि आज हाउस ने जो लेकर आया है बिल प्रिविलिज का उसमें इन्होंने disrupt करने की कोशिश करी, मंत्री जी पे एक्यूज करने की कोशिश करी और उसको किसी तरह से ट्विस्ट और टर्न करने की कोशिश करी गई है। तो मुझे लगता है कि इसमें इन पर प्रिविलिज का मसला बनता है क्यूंकि सदन ने लगातार श्री विजेंद्र गुप्ता जी को नियमों के उल्लंघन, अवज्ञापूर्ण रवैये और शरारतपूर्ण आचरण को देखा है इसीलिये ये सदन सहमत है कि उनके आचरण के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये तथा श्री विजेंद्र गुप्ता जी को आज से सदन के विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाये। यही मेरा अनुरोध है।

श्री मदन लाल: मैं इनका अनुमोदन करता हूं। मैं इनको सैकिंड करता हूं जी। He does not deserve to be here. He does not deserve to be here.

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: मैंने कुछ बोला है अभी।

...व्यवधान.....

श्री मदन लालः He does not deserve to be here. He does not deserve to be here.

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मदन लाल जी एक मिनट। एक मिनट।

...व्यवधान.....

श्री मदन लालः ये डिजर्व नहीं करते हैं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः पक्ष और विपक्ष के साथियों से, आप पहले बैठेंगे।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मदन लाल जी दो मिनट आप भी बैठिये। अभी तीन साथियों ने सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी मैं कुछ पढ़ रही हूं रूलिंग देख रही हूं इस बीच में आप सब का खड़े होने का क्या मतलब है। पहली बात। दूसरी बात आज सुबह से ये बात बिल्कुल साफ है, रिकार्डिंग्स में भी आ रही है सब लोग प्रत्यक्ष तौर पर अपनी आंखों से देख भी रहे हें और आपके साथी भी ये देख रहे हैं सुबह से इंटेशनली आप सदन को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मंत्री जी को अपशब्द बोलते हैं, आप टेबल की हुई

रिपोर्ट जिसको अडॉप्ट किया है पूरे सदन के लोगों ने धवनिमत से और आप उसके बारे में गलत उसके शब्द..

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ता: विरोधकर रहे हैं।

माननीया अध्यक्ष: विरोध करना अलग होता है झूठ बोलना अलग होता है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: सदन में झूठ बोलना अलग होता है, आप उसके तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मंत्री जी को आप अपशब्द कह रहे हैं ये कोई तरीका ठीक नहीं है। ये बिल्कुल भी तरीका ठीक नहीं है।

श्री ओ.पी. शर्मा: अरे वापस ले तो लिया और क्या फांसी चढ़ाओगे।

माननीया अध्यक्ष: और ये आपके कौन से बोलने का तरीका है फांसी चढ़ायेंगे।

श्री ओ.पी. शर्मा: वापस ले तो लिया।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: तो चर्चा न करें। बात कर रहे हैं न, तो ये कौन सी तमीज़ है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः नहीं, आपने चेयर का सम्मान करा, मेरे उपर आपने बहुत बड़ा आभार किया है, अहसान कर दिया आपने। लेकिन सदन की मर्यादा होती है या नहीं होती है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः तो सुबह इन्होंने अपशब्दों का यूज किया था अब आप अपशब्दों का यूज कर रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः किस बात का कौन घमंड कर रहा है, मतलब बोले जा रहे हैं आप।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः तो सही शब्दों का प्रयोग करके बोलें न।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः हां तो आप किसी विषय पर बोले न। जनता के विषयों पर बात करें, दिल्लीवासी के विषय पर बात करें, जो सूचीबद्ध कार्य हैं उस पर आप बात करें। अनाप शनाप बात करेंगे फुटेज खाने के लिये। फुटेज खाने के लिये राजनीति करने के लिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप फुटेज खाने के लिये करते हैं सब कुछ। तरीका ठीक नहीं है। आप अपने साथियों को समझायें थोड़ा सा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): माननीय विजेंद्र जी बोल रहे थे इतने महत्वपूर्ण विचार उन्होंने सदन के समक्ष रखे।

माननीया अध्यक्षः तोड़ मरोड़ कर विषय पेश किया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): उससे कुछ सीखना चाहिये। उससे रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को कुछ सीखना चाहिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः अच्छा मतलब मंत्री का अपमान करना उनसे सीखें। उनसे मंत्री जी का अपमान करना सीखें।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): अगर इस कमेटी में अपोजिशन के मेंबर को नहीं रखा है अगर ये सुझाव उनकी तरफ से आया है तो इसमें क्या गलत है?

माननीया अध्यक्षः बात यहां पर सुझाव की नहीं है शायद या तो आप उस वक्त सदन में थे नहीं जब इन्होंने मंत्री जी के लिये अपशब्दों का प्रयोग किया और मैंने तुरंत इनको टोका। ये फिर भी माने नहीं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः ये देखिये अभी भी, अभी भी देख रहे हैं।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूडी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): अब आदरणीय अध्यक्षा जी जो कह रही है आप. हम बैठ रहे हैं। अब आप जो फैंसला देगी हम उसका..

श्री मोहन सिंह बिष्टः उसका सम्मान करते हैं हम।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः और अभी आप अपने दायें और बायें देखें। दायें और बायें देखें। मतलब आप चारों पांचों सातों लोग एक साथ खड़े होंगे। बैठाईये ओपी शर्मा जी को।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष महोदया मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। डिसिजन देना ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। मान लिया पैटिशन कमेटी कोई मुद्दे को ले करके हाउस के अंदर लाईं उसको रखने का एक तरीका होता है। हमने तो बोला नहीं क्योंकि आपने रूलिंग दे दी, वो हमारे लिए सर्वमान्य है।..

माननीया अध्यक्षः जब आपने उस पर प्वाइंट ऑफ आर्डर रखा..

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः अरे हमारी बात तो सुन लो।

माननीया अध्यक्षः एक मिनट। जो आपने बात रखी पहले उसका जवाब सुन लीजिए।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः हमारी बात तो सुन लो। डिसिजन रखने का ये कोई तरीका नहीं है।

माननीया अध्यक्षः ये कोई तरीका नहीं है।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः ये गलत तरीका है। ये हाउस को चलाने का तरीका बिल्कुल गलत है। मैं अपनी अध्यक्षा से बात कर रहा हूं। ये मेरा अधिकार है अपनी अध्यक्षा को अपनी बात रखने का।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः जब आपने उस पर प्वांइट आर्डर दिया..

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः किसी सदस्य को अपनी बात रखने का। ये तरीका बिल्कुल गलत है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः जब आपने प्वांइट आर्डर दिया, उसे माना गया।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः पहले उसको पेश करते फिर उस पर बहस होती। उसके बाद एक या दो दिन के बाद उसको कन्टीन्यू उस बहस को रखते। ये सदन की परिपाटी है। बाकी आप जैसा करेंगे क्योंकि ये लोग मैजोरिटी में हैं। किसी का भी गला दबा देते हैं, किसी को भी बोलने नहीं देते।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः गला किसका दबाया जा रहा है।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः लेकिन आपके ओर से न्याय मिल रहा है। मैडम दो दिन जिस प्रकार का सदन चला, वास्तव में स्पीकर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाईं यदि मैम्बर कोई बात रखता है, मानो या मत मानो, हमने कहा पैटिशन कमेटी की रिपोर्ट आई रिपोर्ट के रूप में उसको प्रस्तुत करेगा।.. अरे क्या पता है तुम्हें ए.बी.सी.डी नहीं पता। तुमने तो ये बना दिया हवा में बना दिया। उडा रहे हो हवा में। मैं स्पीकर साहब से निवेदन कर रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: बिष्ट जी आप गलत, बिल्कुल गलत। आज आपका आचरण बिल्कुल गलत है।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्ट: मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं।

माननीया अध्यक्ष: बिल्कुल गलत आचरण है।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: नहीं-नहीं, सही बोल रहा हूं।

माननीया अध्यक्ष: आज बिल्कुल गलत आचरण आपने रखा है।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: मेरी बहन, ये गलत आचरण नहीं,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: आप बिल्कुल नहीं मानेंगे विजेंद्र गुप्ता जी से.

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्ट: ये संविधान की प्रक्रिया बहुत गलत है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत आचरण है।

...व्यवधान.....

श्री मोहन सिंह बिष्ट: और ये गलत तरीका है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आज आपका आचरण बिल्कुल गलत है।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः आप हमारा गला दबाना चाहते हैं। हम सही बात को कहते हैं, आप बोलने ही नहीं देते।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बेहद शर्मिंदा। बेहत शर्मिंदगीपूर्ण रवैया अपनाया है आज आपने।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः आपने जो ये रिपोर्ट पेश करी,

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः गलत..

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः पहले तो येरिपोर्ट पेश होनी चाहिए फिर उस पर बहस होनी चाहिए।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आपके साथी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। झूठ बोलेंगे। मंत्रियों को अपशब्द कहेंगे..

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्ट: बहन ये इन्ट्रीडयूश होता है। उसके बाद नैक्स्टडे में बिल आता है। ये बात सही है।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्ट: हम कोई गलत नहीं। हम आपका..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: नहीं, आज आप,

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्ट: नहीं, हम गलत नहीं बोल रहें।

माननीया अध्यक्ष: गलत को सही साबित आप नहीं कर सकते।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: नहीं मैडम मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूं। और मैं चेयर को सम्बोधित करते हुए..

माननीया अध्यक्ष: नहीं आप मेरा सम्मान करें या ना करें, सदन को सम्मान करिये। सदन की मर्यादा का सम्मान करिये आप।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: ये तरीका ठीक नहीं है।

माननीया अध्यक्ष: ये गलत है।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: ये तरीका ठीक नहीं है।

माननीया अध्यक्ष: विजेन्द्र गुप्ता जी, सुबह से विजेन्द्र गुप्ता जी..

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्ट: आप हमारी आवाज नहीं दबा सकते। मेरी बहन आवाज नहीं दबा सकते।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्ट: आप कहेंगे हम जरूर बैठेंगे। लेकिन इनको समझाइये..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: आप बैठ जाईये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: बैठिये।

...व्यवधान...

श्री संजीव झा: अध्यक्ष महोदया मेरे हाथ में ये रूल बुक है। ये हमारे हाथ में..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: सही राम जी और संजीव झा जी बैठिये।

...व्यवधान...

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदया मेरे हाथ में ये रूल बुक है..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः सही राम जी बैठिये। संजीव झा जी बैठिये। आपकी बात आ गईं रूल 277 के तहत आपकी बात आ गईं बैठिये। मैं आपको मौका दे दूंगी। समय, आज बहुत चर्चाएं है। वक्ता बहुत ज्यादा हैं मेरे पास। संजीव झा जी बैठिये निवेदन है, प्रार्थना है, संजीव झा जी आप बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः संजीव झा जी बैठिये मैं आपको इस, बैठने के तुरन्त बाद, बैठने के तुरन्त बाद मैं आपको मौका दे दूंगी। संजीव झा जी बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठिये। जब तक आप बैठेंगे नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली। आप बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप बैठिये। आप बैठिये। आज सुबह से लगातार ये सबके संज्ञान में भी है और सबको ये दिख भी रहा है कि जानबूझकर सदन को बाधित करने का काम विजेन्द्र गुप्ता जी के माध्यम से लगातार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आज विपक्ष के साथी उनका सहयोग दे रहे है, क्यूं दे रहे हैं, क्या

करना चाहते हैं। जनहित के मुद्दों पर इनको चर्चा क्यूं नहीं रास आ रही है, ये मेरी समझ से तो बिल्कुल परे हैं। लेकिन ये बेहद दुखद और निंदनीय है कि जो सदन पटल पर रिपोर्ट पेश हुईं सबके समक्ष उसके तथ्यों को तोड मरोड कर पेश करना, झूठ बोलना ये बेहद ही शर्म की बात है और अवमानना की बात है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: ये अवमानना की भी बात है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: आपने तो कोई बात भी नही बोली। ओपी शर्मा जी आपने तो कोई बात भी नहीं बोली, आप क्यूं खड़े हो रहे हो बार-बार।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: मैं इस लिए खड़ा हो रहा हूं कि आप अपने आप में फैसला झूठ और सच का कर रहे हैं।

माननीया अध्यक्ष: मैंने तो अभी कोई फैसला करा भी नहीं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: और क्या कर रहे हैं आप।..

माननीया अध्यक्ष: मैं सिर्फ जो आचरण इनका सुबह से अब दोपहर तक है और दोपहर के भोजन के बाद भी जो इनका आचरण है मैं सिर्फ उसको बता रही हूं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: इसके विरोधा में बोलना झूठ बोलना है क्या?

माननीया अध्यक्षः आपने तथ्यों को तोड मरोड कर पेश नहीं किया है?

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप बैठ जाईये। आदरणीय बिधूडी जी बहुत सम्मान के साथ मैं आपसे निवेदन कर रही हूं। पहले आप विजेन्द्र गुप्ता जी को बैठाईये और फिर खुद बैठिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः जब तक आप नहीं बैठेंगे और जब तक विजेन्द्र गुप्ता जी नहीं बैठेंगे। चेयर से जब तक ना कहा जाए किसी को परमिशन लेकर बोलने के लिए कृपया कोई ना बोले और ये बात तो माननी पड़ेगी कि आज जानबूझकर माहौल खराब करने का पूरा प्रयास विजेन्द्र गुप्ता जी की तरफ से किया जा रहा है। अगर अब आप इसे रिपीट करेंगे, अब आप इसे रिपीट करते हैं तो जो अभी माननीय सदस्य संजीव झा ने प्रस्ताव रखा मुझे मजबूरन उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए आप संयमित होकर अपना आचरण रखें और इस कार्यवाही को आगे बढ़ने दें।

...व्यवधान...

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदया, चाहे मैं हूं ये सदन हो, सदस्य हो या ये चेयर हो सब ये रूल से बधांा हुआ है।

माननीया अध्यक्षः बिल्कुल।

श्री संजीव झाः मैं आपसे बस इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि जो मोशन मैं लेकर आया हूं उसमें सदन की सहमति आप ले लें। सदन से ऊपर कोई नहीं है। अगर सदन की सहमति हो तो कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा इतना निवेदन है।

...व्यवधान...

श्री संजीव झाः केवल अध्यक्ष की अवमानना का ही सवाल नहीं है। कोई पहली घटना नहीं है। लगातार विजेन्द्र गुप्ता जी का ये कन्डेक्ट रहा है। मैं पहले भी अध्यक्ष महोदया आपसे रिक्वेस्ट किया हूं। पहले भी प्रिविलेज का मसला चल रहा है इन पर। कभी कुर्सी पर चढ़ जाते हैं, कभी वेल में बैठ जाते हैं। कभी लेट जाते हैं और हाउस के कन्डेक्ट को हमेशा खराब करते रहे हैं। तो अगर ये लगातार इस तरह से हाउस को अगर डिस्टर्ब करते हैं, हाउस के कन्डैक्ट को डिस्टर्ब करते हैं, चेयर को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को बोलने नहीं देते हैं।.. तो मैं बस इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसी रूल में आप सदन की सहमति ले लें बस।

माननीया अध्यक्षः मदन लाल जी अपनी बात को रखिए। बहुत समय खराब हो गया प्लीज। कल की तरह सहयोग करें।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आपका बोलना बहुत जरूरी है हर बात पर? मजाक बनाकर रख दिया है आप लोगों ने इस सदन का। कोमेडी डांस चल रहा है क्या यहां पर जो आपको इतनी हंसी आ रही है विजेन्द्र गुप्ता जी? बोलिये मदन लाल जी।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे कुछ साथी इस इस हाउस को बार-बार disrupt करना चाहते हैं। अनर्गल बाते करके सदन का समय जाया करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कृपया सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सार्थक वार्तालाप में हिस्सा लें तो ये सदन आपका ऋणी रहेगा। महोदया, 2023 के इलैक्शन से जरा सा पहले.

माननीया अध्यक्षः शार्ट में रखियेगा अपनी बात, आज बहुत सारे विषय हैं।

श्री मदन लालः आप मुझे टाईम बता दें उतने में खत्म कर दूंगा।

माननीया अध्यक्षः चार से पांच मिनट के बीच में कम्पलीट कीजिए।

श्री मदन लालः जी, थैंक यू मैडम। अक्टूबर 2022, जनवरी, 2023 इन लगभग तीन चार महीनों के भीतर बीजेपी ने अपना खेल दिल्ली में खेलना शुरू कर दिया। ये वो समय था जब बीजेपी ना

चाहते हुए भी एमसीडी का इलैक्शन करवाने पर मजबूर हो गई थी। इन्होंने बहुत कोशिश करके एमसीडी के चुनाव टाले थे। तीन बार करारी हार खाने के बाद विधान सभा में ये दूसरी बार एमसीडी का इलैक्शन लड़ रहे थे और ये वो समय था जब लोगों को लगने लगा था कि एमसीडी में अब केवल केजरीवाल जी को लायेंगे तभी दिल्ली का विकास होगा तभी दिल्ली सुन्दर और स्वच्छ बनेगी। हैल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, प्रिंसिपल सैक्रेट्री फाईनांस के सैक्रेट्री सोशल वेलफेयर के सैक्रेट्री ने अपने बड़े आकाओं की मदद से दिल्ली में उस डेवल्पमेंट के प्रोसेस को रोकना शुरू कर दिया। वो चाहे मोहल्ला क्लीनिक का हो, जहां डाक्टर्स की सैलेरी अचानक आनी बंद हो गई हो। मोहल्ला क्लीनिक्स की जो बिजली के कनैक्शन थे उनका ओवर पेमेंट की वजह से, डयू पेमेंट होने की वजह से कनैक्शन कटने लगे थे। स्टाफ की scarcity थी, दवाईयों की उपलब्धता नहीं के बराबर थी। लिहाजा एक-एक करके मोहल्ला क्लीनिक बंद होने लगे। लोगों ने हायतौबा मचाईं अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया। ये बहुत अचरज की बात थी कि सब लोगों को पता चल रहा था कि मोहल्ला क्लीनिक्स में सब कुछ ठीक नहीं है। अखबार लिख रहे थे। परन्तु अफसर आंख और कान बंद कर आराम से बैठे थे। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उस पर कोई एक्शन हुआ तो बीजेपी इलैक्शन नहीं जीत पायेगी। ये ही हाल सोशल वेल्फेयर डिपार्टमेंट का हो गया। बुजुर्गों को विधवाओं को ऐसे लोगों को पेंशन आनी बंद हो गईं बार-बार वो लोग जो

dependent थे केवल पेंशन पर और पेंशन अगर हम दिल्ली के स्वरूप को देखें तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग रोते देखें है जिनकी एक दो महीने की पेंशन ना आये तो रोने लगते हैं कि इससे तो मेरी दवाई का खर्चा चल रहा है। ऐसे लोगों को तीन-तीन, चार-चार महीने अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते है कि वो दोष किसको देंगे। वो नहीं जानते हैं कि जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट है या बीजेपी है या बीजेपी शासित ऐसे बेईमान अफसर उसमें हिस्सेदार है। उनको केवल लगता है कि शायद केजरीवाल जी के दफ्तर से पेंशन नहीं आ रही और कईयों को तो लगता था कि शायद एमएलए के दफ्तर से पेंशन मिलती है, शायद एमएलए साहब दफ्तर से पेंशन रिलीज नहीं कर रहे। ये वो समय था जब टीडीपीएल को सब्सीडी रिलीज करनी थी वो बंद कर दी। डीजेबी, दिल्ली जल बोर्ड के सारे चलते हुए जितने भी प्रोजेक्ट थे रूकने लगे, क्योंकि ठेकेदारों की पेमेंट बंद होने लगी। जहां कहीं सीवर का काम हो रहा था, ठेकेदार को पार्ट पेमेंट मिलनी थी उसके रूकने के कारण वो जल बोर्ड के काम रूके। काम रूके लोगों को असुविधा हुई ये ही बीजेपी चाहती थी। दिल्ली में पानी की समस्या कभी अभी खत्म नहीं हो पायेगी टाइम लगेगा। क्योंकि हमारे पास कितने ही साधान हों, परन्तु इन अफसरों की इच्छा शक्ति के बिना ये सम्भव नहीं है, क्योंकि फाईनांस से जब तक पैसा सही समय पर रिलीज नहीं होगा। जल बोर्ड को जब तक पैसा नहीं

मिलेगा तब तक ये प्रोजेक्ट ना तो शुरू हो पायेंगे, ना कम्पलीट हो पायेंगे। इन पिछले सालों से जब से श्रीमान केजरीवाल जी की सरकार 2013 मान लो 2015 मान लो 2015 से आई है उससे पहले यहां दिल्ली की हालत जो थी हमने कल विस्तार से यहां चर्चा देखी है सुनी है और समझी है। आप 10 साल में दिल्ली का सारा स्वरूप नहीं बदल सकते परन्तु जिस तेजी के साथ केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद दिल्ली की चाहें वो अनॉथराइज कॉलोनी हो, चाहें गांव हों, चाहें कॉलोनी हो, चाहें रिसेट्लमेंट कॉलोनिज़ हों जिस तरीके से सीवर का पानी का काम तेजी से हुआ है उसको अब रोकने की भरपूर कोशिश शुरू हो चुकी थी। यही कारण था कि लोगों ने बार-बार शोर मचाना शुरू कर दिया। अखबारों में लगातार तीन-चार महीने लगातार आती रहीं खबर, हर डिपार्टमेंट के बारे में चाहें वो जल बोर्ड था चाहें मोहल्ला क्लीनिक था। बस के मार्शल्स, आपने बस के मार्शल्स की तनख्वाह देनी बंद कर दी और तो और एक बड़ा बहुत केजरीवाल जी का पता नहीं हमें कई बार लगता है कि शायद केजरीवाल जी ने बहुत ही ज्यादा काम करके अपने लिये मुसीबत ले ली। वो तो अगर पुरानी सरकार की तरह चुप, कुछ ना करते चाहें बीजेपी की सरकार थी कुछ नहीं किया तो सेन्टर से दोस्ती रही, भले ही दोनों सरकारें विपरीत थीं। कांग्रेस सरकार सेन्टर में थी बीजेपी दिल्ली में थी, बीजेपी सेन्टर में थी दिल्ली में कांग्रेस थी कभी झगड़ा नहीं हुआ क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं थे, झगड़ा कहां से होता। वो

कोई नया काम सोचते ही नहीं थे, किसी को परेशानी नहीं थी। सेन्टर को कभी परेशानी नहीं हुई उन्हें लगा ही नहीं कि हमारा ये कॉम्पिटिटर हो रहे हैं। यहां आकर केजरीवाल जी ने कॉम्पिटिटर बनना शुरू कर दिया। उन्होंने विकास के काम जरूरत से ज्यादा करने शुरू कर दिये अगर ये मोहल्ला क्लीनिक ना खोलते तो ठीक थे, कोई दुश्मनी नहीं थी। ये बसों में मार्शल ना लगाते, ये लोगों को मुफ्त बिजली ना देते, पानी ना देते कुछ भी कोई नया काम ना करते, स्कूल ना बनाते। आप देखो मेरी विधानसभा में 9 सरकारी स्कूल हैं 9 के 9 बने हैं, इसका मतलब 9 के 9 को बनने की जरूरत थी। दिल्ली मे सवा पांच सौ स्कूल बने हैं सबको बनने की जरूरत थी तभी बने हैं। मोहल्ला क्लीनिक्स बनें क्योंकि अस्पताल की हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में जिस तरीके से इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा किया गया ये पहले से जरूरत थी पर किसी ने किया नहीं।..

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट कीजिये।

श्री मदन लालः यही लड़ाई का सबसे बड़ा, मुझे लगता है अभी तीन मिनट हुये हैं थैंक्यू, तो आप देखो इसके बाद इन्होंने जो लगातार उस प्रोसेस को derail करने की कोशिश की और बार-बार लोग उसके बारे में चिल्लाते रहे शोर मचाते रहे अंतिम समय में विधानसभा को इस काम को देखना पड़ा क्योंकि सरकार के मुताबिक, जो बड़ी सरकार है वो कहते थे सर्विस आप पर है ही नहीं और अगर आप पर सर्विस नहीं है तो आप सर्विस के किसी

अधिकारी को कुछ नहीं कह सकते। यही कारण था कि वो विधानसभा के कहीं ना कहीं छाया में आते हैं। विधानसभा की पिटीशन कमेटी ने इसमें cognizance लिया। सेक्रेटरी फाइनांस को पिंसीपल सेक्रेटरी हैल्थ को और प्रिंसीपल सेक्रेटरी फाइनांस को कमेटी के सामने बुलाया, उनसे पूछा गया कि आपने वो जो डाटा एन्ट्री लोग थे उनको क्यों हटा दिया है वो कहते जी इनका AR valuation करना है। अरे भई, हटाकर थोड़ी करोगे, आप उनको हटा रहे हो का मतलब लोगों को आप भगवान भरोसे छोड़ रहे हो, उस हॉस्पिटल को आप भगवान भरोसे छोड़ रहे हो। कायदे से जब आप किसी को हटाते हो तो पहले उसका कोई सब्सिट्यूट तैयार करते हो आपने नहीं किया क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते थे। आपने तो आनन-फानन में एक आर्डर किया और सबको हटा दिया जैसे अभी फेलो हटा दिये। आप सोचो फेलो से आपको क्या लग रहा है केवल आपको संतुष्टि हो रही है कि हम दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे, दिल्ली सरकार अब वेलफेयर स्टेट नहीं होगी। दिल्ली सरकार एक वेलफेयर स्टेट है, आज दिल्ली सरकार का नाम पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा वेलफेयर करने वाली सरकार है। आप कहीं किसी से कॉम्प्टीशन करा लीजिये, चाहें वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, दिल्ली की सरकार ने जितने अच्छे काम किये हैं उनमें से एक भी काम आज दिन तक कोई और बीजेपी की या कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई है और तो और हम बाहर के देशों को भूल जायेंगे कि कौन-कौन देखने आता

है, अमरीका की राष्ट्रपति आ रही हैं, यूएन का चीफ सेक्रेटरी former chief secretary आ रहे हैं दुनिया के लोग आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे यहां तो दूसरे चीफ मिनिस्टर आने लगे हैं कि भई देखें आपके स्कूल कैसे डेव्लपमेंट कर रहे हैं, मोहल्ला क्लीनिक कैसे कर रहा है और वो अपने यहां इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पर आपने एक देखा होगा बीजेपी का एक नहीं आ रहा है। वो अपने आका से डरते हैं। वो कहते हैं अगर बेटा चले गये वहां तो नौकरी छूट जायेगी। उन्हें डेव्लपमेंट की चिंता नहीं है, वो अपने यहां मोहल्ला क्लीनिक नहीं खोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि मोहल्ला क्लीनिक खोला तो आपको कहना पड़ेगा मोहल्ला क्लीनिक का कन्सेप्ट अच्छा है। आपने अगर हॉस्पिटल्स को बढ़िया करना शुरू किया, स्कूलों को बढ़िया करना शुरू किया तो आपको established, आपको मानना पड़ेगा कि दिल्ली की सरकार लोगों के भले के लिये सबसे अच्छे काम कर रही है इसलिये बीजेपी की सरकार कहीं भी कोई स्टेट गर्वमेंट हमें फॉलो नहीं कर रही है। ये इसलिये नहीं कर रही कि वो लोगों के लिये काम नहीं करना चाहते, वो काम तो करना चाहते हैं पर ऊपर वाले वो काम नहीं करने देंगे जो केजरीवाल जी कर रहे हैं। यही कारण था कि इस कमेटी ने जब उन सेक्रेटरिज़ को बुलाया चाहे वो सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी हों चाहे वो फाइनांस के हों चाहे वो हैल्थ के हों, उनके पास जवाब नहीं था और वो लीपापोती करते रहे बल्कि कई बार यहां कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें लगा उनका व्यवहार बहुत ही ज्यादा

घटिया था। चीफ सेक्रेटरी को तलब किया, चीफ सेक्रेटरी ने माना कि उन्होंने गलती की है। डाटा ऑपरेटर्स को हटाकर अचानक और उसकी जगह कोई सब्सिट्यूट नहीं किया ये उनकी गलती थी। जब उनको बताया कि क्या आपने अखबारों के, क्या आपको पता था ये हो रहा है दिल्ली में, उन्होंने अनभिज्ञता जताई और ये अनभिज्ञता जानबुझकर जताई गई थी क्योंकि कोई ऐसा उस समय का अखबार नहीं था हिन्दी का अंग्रेजी का किसी और भाषा का जिसमें इस बात का वर्णन ना हो कि दिल्ली में सीवर में, डीजेबी में, मोहल्ला क्लीनिक में, बस मार्शल्स में सब जगह दिक्कत हो रही है और अंत में उन्होंने एक शब्द कहा, जब कमेटी ने बार-बार कहा कि आप मानते हो गलती की तो उन्होंने कहा हां, गलती तो की है इन ऑफिसरों ने और जब कमेटी ने कहा एक्शन लिया, तो उन्होंने एक शब्द कहा जो बड़ा था उन्होंने कहा किस-किस पर एक्शन लूं सारे एक जैसे हैं, ये कमेटी की रिपोर्ट में है। उनका वर्ड था किस-किस पर एक्शन लूं सारे एक जैसे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार का हर ऑफिसर उस समय केवल एक काम कर रहा था, वो काम था दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के किये जा रहे जनता के भले के कामों को किस तरह रोकें। केवल वो उनका काम था, वही उनके लिये आदेश था, उसी पर वो सारे काम कर रहे थे। इससे कमेटी ने जो रिक्मन्डेशन्स दी हैं ये रिक्मन्डेशन राजेश गुप्ता जी ने पढ़ी हैं मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे समय कम दिया आपने, मैं आपका धन्यवाद कर

रहा हूं जितना दे दिया उतना बहुत है। जितने भी ये रिक्मन्डेशन्स हैं मैं इसको सपोर्ट करता हूं और पूरे सदन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर इसको सपोर्ट करें जिससे ऐसे ऑफिसर्स को जिन्होंने दिल्ली के लोगों की भलाई के काम को रोकने के लिये और उनको कष्ट पहुंचाने के लिये जी तोड़ मेहनत कर अपने आकाओं को खुश किया है ऐसे लोगों को सर्विस में रहने का भी अधिकार नहीं है।..

माननीया अध्यक्षः चलिये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मदन लालः इस कमेटी के रिकमन्डेशन के हिसाब से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिये, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद मदन लाल जी। चूंकि इस विषय पर पक्ष और विपक्ष से बहुत सारे साथियों के नाम थे और आज पूरा समय बहस में खत्म किया है अब मैं दूसरे विषय की ओर बढ़ रही हूं श्री दुर्गेश पाठक जी मणिपुर में अशांति और वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचार के विषय के संबंध में चर्चा को प्रारंभ करेंगे, बैठ जाईये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः या तो बहस कर लीजिये या तो आप लोग बहस कर लीजिये या विषयों पर बात कर लीजिये।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदया।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाईये, आराम से बैठ जाईये मुझे बिल्कुल मजबूर ना करें।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः अध्यक्ष महोदया।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः विजेंद्र गुप्ता जी।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः अध्यक्ष महोदया।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः आपने एक बहुत ही, मेरे साथी कह रहे हैं कि मणिपुर कौन सा विषय है..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी तो बहस कौन कर रहा था।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठक: ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ..

माननीया अध्यक्ष: पहले डिसाइड करें कौन बोलेगा।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठक: कि हमारे साथी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि मणिपुर कौन सा सब्जैक्ट है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: जब तक आप लोग नहीं बोल रहे, बैठेंगे और डिसाइड नहीं करेंगे तो..

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठक: ये शर्म की बात है..

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठक: कि भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि मणिपुर कौन सा सब्जैक्ट है ये शर्म की बात है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: बैठाईये बैठाइये, इन्हें।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः ये शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि मणिपुर कौन सा सब्जैक्ट है ये शर्म की बात है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठाईये

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात हैकि भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि मणिपुर कौन सा सब्जैक्ट है ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः ये शर्म की बात है, आप मणिपुर से भाग क्यों रहे हो। आप मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो, आप मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो, आप मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो, आप मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो?

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः आप मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो?

.....व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप लिखकर दे दीजिये, आप लिखकर..

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः आप मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप लिखकर दे दीजिये,

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः आप मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो, आप मणिपुर पर वहां भी चर्चा नहीं कर रहे हो यहां भी चर्चा नहीं कर रहे हो, आप मणिपुर पर वहां भी नहीं चर्चा कर रहे हो यहां भी चर्चा नहीं कर रहे हो। आप मणिपुर पर वहां भी चर्चा नहीं कर रहे हो यहां भी चर्चा नहीं कर रहे हो।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः आप कहां चाह रहे हो चर्चा हो, चर्चा कहां चाहते हो मणिपुर पर हो।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः मणिपुर पर चर्चा कहां हो।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः दुर्गेश जी।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः आप अपने हाउस में तो कर नहीं रहे हो।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मैं खड़ी हूं, मैं खड़ी हूं ना, मैं खड़ी हूं ना बैठिये आप लोग।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः कुछ तो सदन की मर्यादा, बिधुड़ी जी कुछ तो सदन की मर्यादा, कुछ तो सदन की मर्यादा रख लीजिये। इतनी जोश में और होश के साथ जो अभी आपने दिल्ली के विषयों की बात करी सुबह से क्या हो रहा था? सुबह से बार-बार आपके साथी interrupt कर रहे थे।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आपको जो भी..

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): चर्चा हो चुकी है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मणिपुर विषय नहीं है?

श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): नहीं है मणिपुर।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः नहीं है मणिपुर, आपको शर्म आनी चाहिये, आपको शर्म आनी चाहिये कि मणिपुर विषय नहीं है। मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है?

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप बैठिये, लिखकर दे दीजिये, आपको कोई चर्चा चाहिये ना, आप कोई चर्चा देना चाहते हैं, कोई चर्चा कराना चाहते हैं, कोई विषय उठाना चाहते हैं आप लिखकर दे दीजिये। आप ही कहते हैं कि सदन कानून और रूल्स से बंधा हुआ है, बैठिये, आप लिखकर दे दीजिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आज विजेंद्र गुप्ता जी आप बहुत मजबूर कर रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मैं किसी पर, आप लिखकर दे दीजिये ना चर्चा के लिये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः चर्चा के लिये आप लोग लिखकर दे दीजिये। आप लोगों के मुताबिक मणिपुर विषय नहीं है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप मुझे लिखकर दे दीजिये ना।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः ये कोई तरीका नहीं है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप प्लीज़ बैठ जाईये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मणिपुर पर चर्चा ना हो, मणिपुर पर चर्चा ना हो, मणिपुर पर चर्चा ना हो, अभय वर्मा जी बैठ जाईये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः आप बैठ जाईये, मैं पढ़ लेती हूं, देख लेती हूं मैं, देख लूं, देख लूं नियम-55 के तहत आपकी एप्लीकेशन, हां जी बैठिये, बैठ जाईये।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: सहयोग दीजिये, सहयोग दे दीजिये, मणिपुर का कोई लेना-देना नहीं है इस देश से, इस देश से।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: इस देश से मणिपुर का कोई लेना-देना नहीं है।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: आप बहुत वरिष्ठ साथी हैं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: आप बहुत वरिष्ठ साथी हैं।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्ष: आप बहुत वरिष्ठ साथी हैं। मैं सबसे आखिरी बार आप लोगों को बोल रही हूं कि आप लोग बैठ जायें।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठक: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने..

....व्यवधान....

माननीया अध्यक्ष: विजेन्द्र गुप्ता जी, ओपी शर्मा जी, बिष्ट साहब बैठ जाएं।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठक: मणिपुर जैसे बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात रखने का मौका दिया।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्ष: आप मुझे लिखकर दे दीजिए। मुझे लिखकर दे दीजिए। आप मुझे लिखकर दे दीजिए। ओपी शर्मा जी बैठिये। ओपी शर्मा..

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्ष: हां तो दिल्ली के मुद्दों पर ही तो चर्चा हो रही है। सुबह से दिल्ली के मुद्दों पर ही चर्चा हो रही है।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्ष: कहां थे आप जब सुबह से दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी और आप सब लोग खड़े किस खुशी में हैं।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्ष: आप बैठिये। बैठ जाइये महावर जी। महावर जी बैठ जाइये।

...व्यवधान....

(सत्ता पक्ष औरविपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गईं)

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः जितेन्द्र महाजन मार्शल आउट। जितेन्द्र महाजन जी को मार्शल आउट किया जाए। जो नहीं बैठेगा वो मार्शल आउट होगा। वो मार्शल आउट होगा। ये देखिए। जितेन्द्र महाजन जी को मार्शल आउट किया जाए। अभय वर्मा जी मजबूर मत कीजिए।

...व्यवधान....

(माननीया अध्यक्ष महोदया के आदेशानुसार श्री जितेन्द्र महाजन को मार्शल द्वारा सदन से बाहर किया गया।)

...व्यवधान.....

माननीया अध्यक्षः मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत सम्मान करती हूं। नहीं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत सम्मान करती हूं। आप सीट पर चलिए। अभय वर्मा जी सीट पर चले जाएं। अभय वर्मा जी को भी मार्शल आउट करें। अभय वर्मा जी को भी मार्शल आउट करें। मार्शल आउट किया जाए अभय वर्मा जी को। अभय.. आप जाइये।

...व्यवधान.....

(सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई)

...व्यवधान.....

माननीया अध्यक्षः तरीका तो नहीं है। मैं आपको इतना सम्मान करती हूं। अभय वर्मा जी को मार्शल आउट, तुरंत प्रभाव से मार्शल आउट।जाना है तो ऐसे ही चले जाओ, क्यों मार्शलों की भी मेहनत

करा रहे हो। लिखकर दीजिए न, लिखकर दे दीजिए। अभय वर्मा जी, अभय वर्मा जी का मार्शल आउट, बाजपेयी जी जाइये। नहीं जाएंगे। बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, कोई मान मर्यादा नहीं मानेंगे, कोई मान मर्यादा नहीं मानेंगे। ओपी शर्मा जी आप तो बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं। बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। ओपी शर्मा जी और अनिल बाजपेयी जी को भी मार्शल आउट करें। माहौल खराब करेंगे तो मजबूरन, मजबूरन....

(माननीया अध्यक्ष महोदया के आदेशानुसार श्री अभय वर्मा, श्री ओपी शर्मा व श्री अनिल बाजपेयी को मार्शल द्वारा सदन से बाहर किया गया।)

...व्यवधान....

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई)

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः बैठिये सत्ता पक्ष के साथी।

...व्यवधान....

श्री दुर्गेश पाठकः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने..

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः तरीका नहीं है प्लीज बैठ जाइये बहुत वरिष्ठ हैं आप। बहुत वरिष्ठ साथी हैं। बहुत वरिष्ठ साथी हैं, तो जाइये। आप सीट पर..

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः सम्मान करते हैं तो सीट पर जाएं।

...व्यवधान....

श्री मोहन सिंह बिष्टः दिल्ली के विषय पर चर्चा कराओ न।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः अगर कुर्सी का सम्मान करते हैं, अगर..

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः बिष्ट साहब ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर की चर्चा न यूपी के सदन में भी हुई है। यूपी के सदन में भी, यूपी के सदन में भी मणिपुर पर चर्चा हुई है। मणिपुर के विषय पर उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी चर्चा हुई है। सुबह से..

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः अच्छा आप एक बार वहां बैठिये। आपके सवाल का जवाब देती हूं, पहुंचिए।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः आप अपने आसन पर पहुंचे। आप अपने आसन पर पहुंचे बिष्ट साहब।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः अच्छा, पहुंचिए तो, वहां खड़े होकर बोलिए।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः बैठिये, मैं खड़ी हूं न।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः चैयर को सम्मान करते हैं आप लोग तो, आप लोग चैयर का सम्मान करते हैं, आप चैयर का सम्मान करते हैं। आप चैयर का सम्मान करते हैं न और सभी लोग चैयर का सम्मान करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा मणिपुर जैसे गंभीर विषय पर चर्चा कराते हुए विपक्ष को क्या आपत्ति है, पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली के विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। सुबह से, कल से दिल्ली के विषयों पर ही चर्चा हो रही थी। आज जो याचिका समिति की रिपोर्ट पेश हुई है, वो दिल्ली से सम्बंधित ही तो थी। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, षडयंत्र की वजह से, किसी भी कारण की वजह से अस्पताल में से डाटा ऑपरेटर हटाये गये, ये किसी से नहीं छिपा। पानी की समस्या पैदा हुई, ये भी किसी से नहीं छिपा। हजारों हजार लोगों की पेंशन रूकी, ये भी किसी से नहीं छिपा, जब उस वक्त चर्चा हो रही थी, क्या हम लोग सीरियस थे विपक्ष के साथी। कहां थे आप पूछिए, विजेन्द्र गुप्ता जी से।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः कहां सीरियस थे आप?

...व्यवधान....

श्री मोहन सिंह बिष्टः हमारे लिए मणिपुर कोई मायने नहीं रखता।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः नहीं रखता मणिपुर.. मणिपुर कोई मायने नहीं रखता आपके लिए, क्या ही बोल रहे हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं! मणिपुर कोई मायने नहीं रखता। मणिपुर कोई मायने नहीं रखता है।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः प्लीज बैठिए।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः प्लीज बैठ जाइये।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः बैठें। सभी सत्ता पक्ष के साथी बैठें।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः बैठिये बंदना जी।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः मैं बाद में मौका दे दूंगी, प्लीज बैठ जाइये। बंदना कुमारी जी बैठिये।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः बंदना कुमारी जी बैठिये और महावर जी आप भी बैठिये। महावर जी बैठ जाइये। बैठ जाइये।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः बैठ जाइये। आपको बिल्कुल मैं तब तक नहीं बोलने दूंगी जब तक आप बैठेंगे नहीं। दुर्गेश जी के अलावा अब कोई नहीं बोलेगा। न पक्ष से न विपक्ष से, जब आपको बोलने के लिए बोला जाएगा, आप तभी बोलेंगे और...

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः आप मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहते? मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं होने देना...

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः बैठिये बंदना जी।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः दिल्ली का कल भी है सदन। सदन की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही कल 18 तारीख को भी होनी है।

सदन की कार्यवाही कल 18 तारीख को भी होनी है। आपके जो भी विषय है, आप दीजिए मैं टेक-अप करूंगी।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः आप अपने विषयों को दीजिए, मैं टेक-अप करूंगी।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः हां,

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः बिल्कुल।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः बिल्कुल। बैठिये, बैठिये। शुरू करें।

....व्यवधान....

श्री दुर्गेश पाठकः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आज आपने...

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः आप बोलते रहिये।

श्री दुर्गेश पाठकः मणिपुर जैसे बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर इस चर्चा को करने का समय दिया। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि

उत्तर प्रदेश की सदन में मणिपुर पर तो चर्चा हो सकती है लेकिन दिल्ली में नहीं हो सकती..

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः बंदना जी। सत्ता पक्ष के सभी साथी शांति बनाये रखें। लोग देख रहे हैं कि मणिपुर के प्रति इनके मन में कितनी संवेदनाएं हैं।

...व्यवधान....

श्री दुर्गेश पाठकः और जिस तरह से विपक्ष के साथियों ने ये कहा कि मणिपुर उनके लिए मायने नहीं रखता, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि क्या वो मानते हैं कि मणिपुर भारत का हिस्सा है या नहीं है। आज ....

...व्यवधान....

श्री दुर्गेश पाठकः बैठ जाइये बिष्ट जी बैठ जाइये। बैठ जाइये, बहुत धन्यवाद।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः दुर्गेश जी आप अपनी बात रखिये।

...व्यवधान.....

श्री दुर्गेश पाठकः मणिपुर देश का वो राज्य है, जिसे इस देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने उसे हिन्दुस्तान का गहना कहा।

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः ....वैल में आप आए और मैंने आपको मार्शल आउट किया। आप सोच लिजिएगा।

...व्यवधान....

श्री दुर्गेश पाठकः मणिपुर देश का वो राज्य है, जिसने मीरा बाई चानू और मैरी कॉम जैसी ऐसी महिलाएं दी जिससे पूरा भारतवासी गर्व करता है।

...व्यवधान...

श्री दुर्गेश पाठकः 4 मई को पूरे हिन्दुस्तान के एक एक व्यक्ति ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल वाली मणिपुर के अंदर महिलाओं की दुर्दशा हो रही है। 4 मई को पूरे देश के सभी लोगों के व्हाट्सएप पर एक विडियों आया और उस विडियों के अंदर दिखा कि किस तरह से मणिपुर की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जोकि पूरे देश के एक एक व्यक्ति के सिर जो है वो शर्म से झुक गया है ऐसी हालात है ये...

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः आपको थोड़ी सी शर्म आ रही है। आपको इतनी सी लज्जा आ रही है। सारी दुनिया आपको देख रही है। बैठ जाइये। बैठ जाइये।

...व्यवधान....

श्री दुर्गेश पाठकः लगभग 100 दिन हो गए अध्यक्ष महोदया, लगभग 100 दिन हो गये आज मणिपुर में इंटरनेट बंद हुए। लगभग 100 दिन से मणिपुर के अंदर इंटरनेट बंद है। 4 मई को जो ये विडियो आया, 4 मई को जो वो विडियो आया, उस विडियो पर एफआईआर होने में 14 दिन लगे हैं। उस विडियो पर एफआईआर होने में 14 दिन लगे हैं। खुद मणिपुर की सरकार ये कहती है, खुद मणिपुर की ये सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब तक लगभग 55 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं मणिपुर से। 55 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं मणिपुर से।

...व्यवधान....

श्री दुर्गेश पाठकः सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि कुछ दिन पहले तक म्यानमार के अंदर जो लोग हिन्दुस्तान के अंदर आ रहे थे, आज हिन्दुस्तान के लोगों को, मणिुपर के लोगो को म्यानमार के अंदर जाकर पनाह लेनी पड़ रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है। लगभग 200 लोगों की हत्या की जा चुकी है वहां पर, लगभग 200 लोग इस पूरे दंगे के कारण मारे जा चुके हैं और लगभग 6 हजार से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं। घर जलाये गये हैं, लोगों की मंदिर जलाये गये हैं, चर्च जलाये गये हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मणिपुर के अंदर ये काम हो रहा है। जब पूरा का पूरा मणिपुर जल रहा था..

...व्यवधान....

माननीया अध्यक्षः बिष्ट साहब को भी लेकर जाएं।

...व्यवधान....

श्री दुर्गेश पाठकः जब पूरा का पूरा मणिपुर के अंदर इस तरह से 55 हजार लोग विस्थापित हो रहे थे। 200 लोगों की हत्याएं कर दी गयी, 6 हजार से ज्यादा घर जला दिये गये, मंदिर जला दी गयी, चर्च जला दिये गये..

...व्यवधान....

श्री दुर्गेश पाठकः उस समय इस देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, 19 मई को जापान की यात्रा कर रहे थे। 21 मई को पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर थे, 22 मई को आस्ट्रेलिया गये हुए थे, 20 जून को अमेरिका गये हुए थे,

...व्यवधान....

श्री दुर्गेश पाठकः 24 जून को इजिप्ट गये हुए थे। 13 जुलाई को फ्रांस गये थे और 15 जुलाई को यूएई गये थे। जब मणिपुर की बहनों के साथ गलत काम हो रहा था। 55 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, उस समय प्रधानमंत्री विदेश यात्रओं पर थे। इसी विदेश यात्रा में उनके साथ अमेरिका के प्रैसिडेंट भी थे, जो बाइडन साहब। जापान यात्रा पर वो भी थे, ये भी थे साथ में, जापान के बाद उनको भी पापुआ न्यू गिनी जाना था, उनको भी

आस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन अमेरिका में उनको पता चला कि कोई एक डेब्ट क्राइसिस चल रही है, उनकी कोई एक फाइल नहीं पास हो पा रही है सदन से, उन्होंने अपना विदेश दौरा कैंसिल करके वापस अमेरिका चले गए। वो आस्ट्रेलिया नहीं गए, न पापुआ न्यू गिनी गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जब हमारे देश के अंदर 200 से ज्यादा लोगों के मर्डर हो रहे थे, वो आस्ट्रेलिया के अंदर और पापुआ न्यू गिनी के अंदर घूम रहे थे। 78 दिन हुए, 78 दिन तक लगातार मणिपुर जल रहा था, 78 दिनों के बाद प्रधानमंत्री आते हैं और 78 सेकेंड भी नहीं उन्होंने बोला। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि देश के अंदर इस तरह की कहीं भी घटना हो रही है तो वो नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, एक भी कार्रवाई उन्होंने नहीं की। 78 दिन लग गये प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलने में, इससे ज्यादा शर्म की स्थिति नहीं हो सकती। जब सदन के अंदर चर्चा की मांग की गयी कि मणिपुर के ऊपर चर्चा की जाए, तो विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। हमारे राज्यसभा के सांसद श्री संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। राघव चड्डा जी को सस्पेंड कर दिया गया और ना जाने विपक्ष के कितने सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष के सांसद पूरी रात पार्लियामेंट के अंदर सोते रहे और इस मांग को करते रहे कि इसपे चर्चा कराइये, चर्चा कराइये, चर्चा कराइये लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा नहीं किया। मुझे लगता है जो कन्क्लूजन शायद हम लोग कहते आज

भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने मुंह से वो बात कह दी। मोहन सिंह बिष्ट जी ने कहा कि मणिपुर उनके लिए मायने नहीं रखता। अभय वर्मा जी ने कहा मणिपुर क्या मुद्दा है और इसी तरह से बिधूड़ी जी ने कहा और बाकि साथियों ने कहा। आज भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि क्या वो मणिपुर को इस देश का हिस्सा मानते हैं के नहीं मानते। अगर मानते हैं तो उन्होंने क्या किया, उनके मुख्यमंत्री का ये खुद, उनके मुख्यमंत्री का ये बयान है कि ये तो आपने एक विडियो देखा है इस तरह के तो सैकड़ों और हजारों विडियों हमारे पास पड़ी हुई हैं। आज मणिपुर के अंदर महिलायें सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं, युवा सुरक्षित नहीं हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लड़ाने में और अंग्रेजों से भी ज्यादा गंदी नीति इनकी है फूट डालो, राज करो और आज अगर मणिपुर जल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इनकी इसी ?ूट डालों और राज करो नीति का नतीजा है कि पूरा का पूरा मणिपुर आज जल रहा है। जब हम पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे तो सारी मीडिया में ये डिस्कसन था कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब संभाल पायेगी। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है आज पंजाब के लॉ एण्ड ऑर्डर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आज पंजाब के रूल ऑफ लॉ की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आज मणिपुर जो जल रहा है इसकी चर्चा यूनाइटेड नेशन में हो रही है। आप सोचिये कितना बुरा हाल कर दिया प्रधानमंत्री ने। मुझे लगता है कि एक

ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के रूप में है जो ना चर्चा कराती है, चर्चा की मांग कोई करता है तो उसको सस्पेंड कर देती है और अगर दिल्ली जैसे विधान सभा के अंदर चर्चा होती भी है तो उसको वायकॉड कर देते हैं उसमें पार्टीसपेट नहीं करते। आज उनको एक बहुत बड़ा मौका था। आज वो अपनी बात रखते, बताते कि उनकी सरकार ने मणिपुर पे क्या किया लेकिन कोई बातचीत नहीं, कोई चर्चा नहीं और ऐसे-ऐसे रिमार्क्स उन्होंने पास किये। मुझे पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को पता है कि नहीं पता है लेकिन दिल्ली के अंदर हजारों नहीं लाखों मणिपुर के लोग रहते हैं। हर एक विधान सभा के अंदर दो हजार, 5 हजार, 10 हजार लोग मणिपुर के रहते हैं। तो दिल्ली के विधायक होने के नाते, दिल्ली के रिप्रजेन्टेटिव होने के नाते ये हमारा हक बनता है और ये जिम्मेदारी बनती है कि हम मणिपुर के ऊपर चर्चा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अजय दत्त जी। समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री अजय दत्तः जी, जी, जी ज्यादा नहीं लूंगा 10 मिनट से। आदरणीय अध्यक्षा जी सबसे पहले तो मैं आपको पूरे सदन की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ पिछले दो दिन से ये सत्र बहुत ही नियमित रूप से आपने चलाया। आज बीजेपी वालों ने बहुत हंगामा करके इस सत्र को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे भी आपने बहुत शालीनता से हैंडल किया और जैसा कि मणिपुर पे या देश के या दिल्ली के कोई भी ऐसे सैन्सेटिव विषय पर बीजेपी चर्चा

नहीं करना चाहती। ये सदन छोड़कर भाग गए, लेकिन मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे से अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं। मणिपुर का एक बहुत ही सैन्सेटिव मुद्दा है। अभी बीजेपी के कुछ लोग, बीजेपी के विधायक सदन को छोड़ के इसलिए भाग गए क्योंकि वो बीजेपी द्वारा शासित जो राज्यों में इनकी सरकारें राज्यों को संभालने के लिए नाकाम हो चुकी हैं, वहां की व्यवस्थाओं को संभालने में नाकाम हो चुकी है, वहां के लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम हो चुकी है, इस नाकामी को छुपाने के लिए बीजेपी के सारे विधायक यहां से सदन छोड़ के भाग गए हैं और देखिए आज देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां राज्य के लोग अपने आप को बड़े असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मणिपुर की जब ये घटना हुई तो इसके अंदर दो जाति विशेष के लोगों के बीच में आपसी कोई संघर्ष पैदा हुआ तो उस मणिपुर के राज्य की सरकार जहां बीजेपी की सरकार है, उस राज्य का कर्तव्य था कि इन दोनों के बीच में शांति और सद्भावना बनाये, पुलिस डिपलोय करें, डायलॉग करें, संवाद करें और इस जो बहुत बड़ी घटना देश के इतिहास में ये घटी जिसमें करीबन 200 लोग मारे गए, कई हजार करीबन 55000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। साढ़े तीन चार सौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इसमें जो मुझे लगता है दुनिया का सबसे जघन्य अपराध हुआ, महिलाओं को निर्वस्त्र करके उन्हें रोड पे घुमाया गया। उनके साथ अश्लीलता की गईं उनके साथ बलात्कार हुए और उसको विडियो

रिकॉर्ड भी किया गया और इसे पूरे सोशल मीडिया पे चलाया गया। ये एक ऐसी घटना है जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ। अध्यक्षा जी मैं पूरे विश्व में शांतिदूत के तौर पर जाता हूँ। भारत से मुझे शांतिदूत का एक कार्यभार दिया हुआ है। यूनाइट नेशन में भी मैं कई बार गया और मुझे पूरे विश्व से कॉल आईं लोगों ने पूछा ये तुम्हारे देश में क्या हो रहा है? तुम्हारे देश में क्या महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है? क्या तुम्हारे साथ लोगों के साथ कभी भी कोई भी घटना हो जाती है? तुम्हारी सरकारें क्या कर रही हैं? तो मैंने उन्हें बड़ी विनम्रता से बताया कि मैं दिल्ली सरकार को रिप्रजेंट करता हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार को और ये बड़े दुख से मैंने बताया कि ये बीजेपी की सरकार है जो ैडरल गवर्मेंट में है सेन्ट्रल गवर्मेंट में बैठी है। वो बहुत दुखी हुए, उन्होंने कहा कि आप कौन-सी तिथि में रह रहे हो और वहां से कई मेरे साथियों ने महिलायें जो मुझे जानती हैं उन्होंने भी फोन किया और कहा कि भार्गो भारत से हैं, वो एनआरआइज हैं, कुछ लोग वहां काम करने गए हैं, वो सब डरी हुई हैं कि हम भारत कैसे आयें, हम देश में कैसे आये जो महिलाओं के साथ इतना जघन्य अपराध हो रहा है। हम कैसे इस देश पे विश्वास करें और इतनी शर्मनाक घटना हो रही है और इस घटना के दौरान मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ऐसी घटनायें तो मेरे पास हजारों की संख्या में ऐसी विडियो है जहां पर महिलाओं के साथ ऐसा दुराचार हो रहा है और उससे

भी शर्मनाक बात जब इस देश के प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहते हैं कि मैं इस देश को अच्छा बना रहा हूँ, खुशहाल बना रहा हूँ, विकसित बना रहा हूँ। अरे आप क्या बना रहे हो, इस देश की दुर्दशा कर दी आपने। जिस समय मणिपुर जल रहा था, जिस समय ये महिलाओं के साथ घोर अपराध हो रहा था जहां पे एक विशेष जाति के साथ इस तरीके की प्रताड़ना हो रही थी, हजारों लोग यहां पे मर रहे थे, भाग गए थे, आप क्या कर रहे हैं? आपके पास पूरी सेना है। ढाई महीने लगे। ढाई महीने तक आपने कान में अपना, अपना क्या डाला हुआ था और इससे पूरे भारत के लोग डरे हुए हैं। इसके बाद जब उनसे सवाल पूछे गए आम आदमी पार्टी के सांसदों ने सवाल पूछे तीन सांसदों को संजय सिंह जी को, राघव चड्डा जी को, सुशील रिंकू जी को इन्होंने संसद से बर्खास्त कर दिया। ये सुनना ही नहीं चाहते। उसके बाद एक और घटना हुई जो हरियाणा में इन्होंने शुरू करी और वहां भी दो जातियों को साथ इन्होंने लड़ाने का काम शुरू किया। मैं तो हरियाणा की सरकार को एकदम किल सरकार मानता हूँ और वहां इतनी सारी पुलिस और कोई भी इन दंगों को, इन परेशानियों को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा। 6 मासूम लोगों की जान गई अध्यक्षा जी और उसके बाद मैं हरियाणा के लोगों को सैल्यूट करता हूँ। वहां की खाप पंचायतों ने, वहां के बहुत सारे लोगों ने साथ मिल के कहा कि हम ऐसी घटनाओं को होने नहीं देंगे। तो आज ये प्रश्न उठता है कि इस देश के अंदर जब आप पूरी

सरकारें चला रहे हैं, तो आपके पास सारा अमला–जमला है। आप छाती ठोक के कहते हैं हम विश्व गुरू बन गए। आप छाती ठोक के कहते हैं हमारे पास सबसे ज्यादा ताकत है। आप से अपने देश की व्यवस्थायें नहीं सुलझ रही, आपसे देश के अंदर महिलाओं का, नारी का सम्मान नहीं सुलझ पा रहा आप इस देश में क्या करोगे।..

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट कीजिए।

श्री अजय दत्तः मणिपुर के अंदर जो इतना बड़ा अत्याचार हुआ इसका जिम्मेवार कौन? 200 लोगों की जान गई इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेवार सीधे–सीधे बीजेपी है। इसके जिम्मेवार मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उनको उसी समय इस्तीफा देना चाहिए था और अगर मोदी जी आप में दम है तो उससे इस्तीफा लेके के दिखाओ। तब माने कि आप कुछ कर सकते हो।..

माननीया अध्यक्षः चलिए, धन्यवाद।

श्री अजय दत्तः आपने ऐसे मुख्यमंत्री को वहां पे काबिज किया है तो इससे समझ में आता है आप करना क्या चाहते थे। ढाई महीने तक आपने कोई बात नहीं की। ऐसी घटनायें होती जा रही हैं, देश के लोगों को आप डरा रहे हैं, धामका रहे हैं, क्या चल रहा है? ये देश डेमोक्रेसी से चलता है, लोकतंत्र से चलता है,जम्हूरियत चलता है और मैं देश का अगर कोई भी देशवासी मेरी ये बात सुन रहा है, देखिए आज ये मणिपुर में हुआ, उसके बाद ये हरियाणा में हुआ और फिर और किसी राज्य में हो जायेगा, ये

कैसे चलेगा? तो पूरा देश देख रहा है और आज पूरा देश हताश और निराश है कि उन्होंने ऐसा कौन–सा काला समय था जब देश के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। तो आज देश के लोग चाहते हैं कि ये जो सरकारें चल रही हैं जो बिल्कुल इन्सीसीटिव है, जो बिल्कुल एकदम नाकारा हैं। इनको बदल दिया जाए। इनको बदलने की मुहीम पूरे देश में चल चुकी है..

माननीया अध्यक्षः अजय दत्त जी कम्पलीट कीजिए।

श्री अजय दत्तः और मुझे लगता है कि पूरा देश जल्द ही निर्णय लेगा और ये ऐसी नाकारा सरकारों को दूर कर देगा और दूसरी बात आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए पॉलिटीकल लड़ाई किसी की भी हो सकती है लेकिन आप जनता के साथ अगर इस तरीके का जघन्य अपराध करोगे, तो जनता तो माफ नहीं करेगी आपको, वो इश्वर भी माफ नहीं करेगा। मैं ईश्वर से सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबको सन्मति दे और इनको सबसे ज्यादा दे क्योंकि इन लोगों ने जो किया है इनको उसकी माफी मिलेगी नहीं। बस इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूँ, आप बहुत अच्छा सदन चला रहे हैं। जय हिन्द, जय भारत, जय भीम।

माननीया अध्यक्षाः बहुत–बहुत धन्यवाद। बंदना कुमारी जी। समय का ध्यान रखियेगा।

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्षा जी आपने मुझे एक ज्वलन्त मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। शायद इस मुद्दे को हमारे विपक्ष के साथी सुनना नहीं चाहते हैं और इस तरह के मुद्दे पे बार-बार लोकसभा में भी देखा गया कि जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को चर्चा होने देना नहीं चाहते। आज उन्होंने विधान सभा में, दिल्ली विधान सभा में भी अपनी दिखा दी। जो इसपे चर्चा नहीं करना चाहते और सबसे जो मतलब इनकी एक गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, मणिपुर कोई सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ओब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं ये जानें। लेकिन जिस तरह से ये मणिपुर में घटना हुई और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़ी ही शालीनता के साथ विदेश भ्रमण कर रहे थे। अभी हमारे भाई ने बताया जिस तरह से यूएनए हमारे अमेरिका के साथी, चाहे और जगह के साथी जब साथ में थे तो वो अपने-अपने काम छोड़कर और अपनी विधान सभा की, अपनी लोकसभा की, अपने देश की चिन्ता कर रहे थे, लेकिन उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश भ्रमण कर रहे थे और जब ये घटना हुई, जब ये विडियो बनाई गई, घटना के समय ना वहां के विधायक को पता चला, ना वहां के मंत्री को पता चला, ना वहां के मुख्यमंत्री को पता चला। किसी को पता नहीं चला, जब तक ये विडियो वायरल नहीं हुआ। हम सबके विधान सभा में सभी अपने-अपने साथी काम करते हैं। क्या इतनी बड़ी घटना होगी और विधान सभा में मंत्रियों को पता नहीं चलेगा, विधायकों को पता

नहीं चलेगा, वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं चलेगा? जब विडियो वायरल होती है तब सब लोग सीरियस होते हैं जोकि इतनी बड़ी घटना घटी। सैकड़ों लोग मारे गये, सैकड़ों घर तोड़ दिये गये, सैकड़ों लोग वहां से, हजारों लोग वहां से दूसरी जगह चले गए हैं। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री जी को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, यही थी डबल इंजन की सरकार। बार–बार डबल इंजन की बात करी जा रही है, हमें तो लगता है दोनों इंजन फेल है महिलाओं को सुरक्षा देने में। सबसे ज्यादा दुखद तोये लगी जो एक फौज में काम करने वाले साथी, उनकी पत्नी के साथ, उनको नग्न करके घुमाया गया, शायद हमारे जितने भी फौजी साथी आज भी बॉर्डर पर बैठे होंगे तो इस तरह की विडियो देखकर, इस तरह की बातों को देखकर शायद हम सबका दिल सिहर जाता है लेकिन उनकी क्या चिंता होगी जो उनकी बीबी, उनके बच्चे, उनकी बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी। ऐसे आदमी के साथ हमारा पूरा देश है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है जो हमारे ऐसे गृह मंत्री जी हैं जिनको शायद आपने भी कभी कहा था तड़ीपार को हमने गृह मंत्री जी बना रखा है और वो मंत्री जी आज हमारे पूरे देश की बहू–बेटियों को कैसे सुरक्षा दे पायेंगे। सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से देश के गृह मंत्री से मैं इस्तीफा चाहती हूं। सबसे पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप हमारी बहू–बेटियों की और बहन की सुरक्षा नहीं कर पाते तो उनको सुरक्षा.. और खासकर हमारे फौज के, फौज के साथियों जो हमारे बॉर्डर पर पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं और

उनके परिवार की हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनके घर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बेटी की सुरक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। शायद ऐसे गृह मंत्री को खुद शर्मिन्दा होना चाहिए। खुद अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी को मांगने की जरूरत नहीं। आज ये साथी कह रहे थे, हमारे भाजपा के साथी, जो मणिपुर की चर्चा यहां पर क्यों जरूरत है। मणिपुर की चर्चा विदेशों में हो रही है, मणिपुर की चर्चा हर राज्यों में हो रही है। जो कहीं ये मणिपुर जैसा हालात अन्य राज्यों में न उत्पन्न कर दें। हर दिन इनका ये ही है जो आपस में लड़वाओ और फिर राज करो, फूट डालो राज करो। कभी किसी से लड़वाओ, कभी किसी से लड़वाओ। जहां पर भी लड़ाई होती है, जहां पर भी दंगे होते हैं तो यही तड़ीपार जो गृह मंत्री जी हैं उनके संरक्षण में कहीं न कहीं उसकी सुगंधा आती है, उसकी खुशबू आती है, उसकी बदबू आती है। उन्हीं की लगाई हुई आग है जो इस तरह की हरकत हो रही है।..

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट कीजिए।

श्रीमती बंदना कुमारीः तो मैं आज दिल्ली विधान सभा से एक मांग करती हूं, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द, अभी तक तो हटा देना चाहिए, जो मुख्यमंत्री अपने स्टेट को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी बहू-बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और साथ में इस तरह की आवाज जो ऐसा तो होता रहता है, ऐसा तो होता रहता है, ऐसी विधन तो रोज आती रहती है, इस तरह

की जो बात कही गई, ये कितनी शर्मशार करने वाली बात है। तो मैं इस सदन के माध्यम से मैं एक-दो बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ रखना चाहती हूं। एक तो जो वो विडियो रिलीज हुई और विडियो रिलीज हुई तो घटना के कितने दिन बाद हुई, और घटना तक जिस-जिस ने चुप्पी साधी बैठी थी, जिन लोगों ने, चाहे वहां के अधिकारी, चाहे वहां के मंत्रीगण, चाहे उस क्षेत्र के विधायक या वहां के राज्य के मुख्यमंत्री, इन सबकी अपनी जवाबदेही पूछनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, उनसे पूछनी चाहिए, उनसे जवाब लेनी चाहिए क्योंकि जब-जब मणिपुर की बात आती है, आज लोक सभा के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह जी ने जब आवाज उठानी चाही, जब उसकी बात करनी चाही कि मणिपुर पर चर्चा करो तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उसी तरह से बाद में जब राघव चड्ढा जी ने अपनी बात रखने की कोशिश करी..

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट कीजिए मैडम।

श्रीमती बंदना कुमारीः तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हर समय विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश जिस तरह से भाजपा कर रही है, तो लगता है धीरे-धीरे लोकतंत्र में ये तानाशाही, इतनी तानाशाही तो अंग्रेजों ने भी नहीं की थी जिस तरह से तानाशाही चल रही है। तो पूरे देश में एक आवाज उठने लगी है भाजपा हटाओ, देश बचाओ। तो मैं सदन के माध्यम से ये ही कह रही हूं जो पूरे देश में हर कहीं और दूसरा मणिपुर न बने इसके

लिए हमें सभी साथियों को, पूरे देशवासियों को मिलकर एक आवाज उठानी चाहिए और हमारे भाइयों ने कहा, सभी ने कहा, सभी, एक-एक कोने से आवाज आ रही है, जो 'मोदी हटाओ देश बचाओ'। जय हिंद, जय भारत।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रीति तोमर जी, समय का ध्यान रखें।

श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमरः थैंक यू स्पीकर मैम आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसा कि मेरे विपक्ष के भाइयों ने तो बता ही दिया है कि मणिपुर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है बोलने का क्योंकि वहां बीजेपी की गवर्मेंट है और दूसरा इन्होंने बताया कि ये महिला विरोधी पार्टी है। मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए एक महिला होने के नाते और एक महिला के आत्मसम्मान की खातिर कम से कम शब्दों में अपनी बात कहूंगीं। अध्यक्ष जी, मणिपुर मुद्दे पर मैं इन दो लाइनों के द्वारा अपनी बात शुरू करूंगी-

'झूठों के दरबार में अब तक सच्चाई फरियादी है,
76 वर्ष हो गये ये कैसी आजादी है?'

अध्यक्षा जी, अभी हमने आजादी की 77th वर्षगांठ मनाईं मैं आपके माध्यम से सभी लागों से पूछना चाहती हूं क्या ये सच्चे अर्थों में हमारी आजादी है? जहां आज भी मणिपुर जैसी घटना होती है, महिलाओं के साथ ऐसा शर्मनाक व्यवहार होता है उस देश को आजाद कहना सही होगा? यूं तो अध्यक्ष जी हम आज चांद पर

पहुंच गये हैं पर मणिपुर की घटना को देखें तो हम धरती पर रहने के लायक भी नहीं हैं। एक तरफ इस देश में जहां स्त्री को दुर्गा और लक्ष्मी का दर्जा मिला हुआ है वहीं दूसरी तरफ इस तरह के घिनौने अपराधें को अंजाम दिया जाता है और वो भी बड़ी बेशर्मी और बेहयाई के साथ। क्या उस देश को आजाद कहना ठीक होगा? हरगिज नहीं। विश्व के किसी भी हिस्से में कोई भी वॉर हो, महिलाओं को निशाना बनाकर उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो। इस तरह की घटनाओं से एक पुरूष की जो मानसिकता है वो सामने आती है कि किस तरह से बहाना बनाकर महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए। चाहे उस घटना से उस महिला का कोई मतलब हो या न हो लेकिन फायदा उठाना है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं कि हमारा समाज आज भी बीमार है। जैसा कि हमारे आदरणीय सी.एम. सर ने कहा भी है कि मणिपुर की घटना ने पूरे देश के लोगों की आत्मा को झकझोर दिया है। किस सदी में जी रहे हैं हम आज? उस वायरल विडियो में अध्यक्ष जी साफ दिखाई दे रहा है कि 2 युवतियों को निर्वस्त्र कर परेड कराई जा रही है और समूहिक रूप से गलत काम किये गये। आप सोचें उन बहनों की मानसिक स्थिति क्या होगी? दुनिया का कोई भी मुआवजा उनके घावों की भरपाई नहीं कर पायेगा। सरकारें तो आयेंगी और जायेंगी। कोई भी सरकार, कोई भी कानून उनका आत्मसम्मान वापिस नहीं दिला पायेगा। अध्यक्ष जी, जब ये

विडियो आया उससे ढ़ाई महीना पहले की ये घटना है पर मणिपुर गवर्मेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर सही वक्त पर कार्रवाई की होती तो हमारी उन मासूम बहनों के साथ ये अन्याय नहीं होता। वहां तो अध्यक्ष जी बीजेपी की गवर्मेंट है, सी.एम. क्योंकि मैतेई कम्युनिटी के हैं शायद इसीलिए उन्होंने शायद कोई एक्शन नहीं लिया। जब भी कोई गंभीर मुद्दा देश में होता है तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चुप्पी साधा लेते हैं और अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाते हैं, ये एक कमजोर नेता की निशानी है। ऐसे वक्त में हर तरह की राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री जी को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए लेकिन वो ऐसा नहीं करतें। मणिपुर की इस घटना में अध्यक्ष जी एक-दो लोगों की अरेस्टिंग हुई है जबकि विडियों में साफ-साफ बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। State Govt. machinery has brutally failed फिर भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया गया, क्या ये डबल इंजन की सरकार का बहुत बड़ा फेलियर नहीं है? वैसे भी अध्यक्ष जी आजकल 'तुम चुप रहो' इसका फैशन है। बहुत सुन ली मोदी जी आपके मन की बात, अब आपको सुननी होगी मणिपुर के मन की बात। संसद में मोदी जी ने 2 घंटे से ऊपर स्पीच दी लेकिन जब मणिपुर की बात आई तो 2-4 मिनट में अपनी बात कहकर पूरी कर दी। क्या बोला, क्या कहा, मैं अभी तक सोच रही हूं और बात सारी होम मिनिस्टर पर है कहकर डाल दी कि उन्होंने बता दिया है क्या करना है। और उसके बाद मणिपुर में क्या किया, ये विकास किया, वो विकास किया, विकास

की एक लंबी फेहरिस्त। मैं स्पीकर मैम आपके माध्यम से मोदी जी से ये पूछना चाहूंगी कि जो ये शर्मनाक घटना हुई मणिपुर में, क्या ये भी उनके विकास का एक हिस्सा थी? जब लोकतंत्र की बात आती है तो भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं लेकिन हमारे एम.पीज को संसद में किसी गंभीर मुद्दे पर बोलने की आजादी नहीं है। यदि वो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, ये कैसा लोकतंत्र है अध्यक्ष जी और ये कैसी आजादी है?

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मणिपुर में हुई इस हार्ट रिचिंग घटना के बाद के कुछ आंकड़े बता रही हूं। 6500 FIR registered in three months, 4000 houses destroyed, 55000 people displaced and 200 plus people died अध्यक्ष जी, this is not less than civil war. This is a war, war against humanity इतना सब होने के बाद भी बीजेपी के नेता कहते हैं अगर मोदी नहीं तो कौन 2024 में। हम निश्चित तौर पर कहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी ने मणिपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया है India in 2024 will 100% say anyone but Modi. अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर– श्री नरेंद्र मोदी जी से इतना ही कहना चाहती हूं–

‘पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है,

अभी भी जलता शहर बचाया जा सकता है।’

अध्यक्ष जी, ये तो हुई मणिपुर इंसिडेंट की बात। मैं इससे थोड़ा सा हटकर कुछ लाइनों में अपने भी मन की बात कहना चाहती हूं। इस तरह की जो घटनाएं, जो 2 साल की बच्ची से लेकर 90 साल की बुजुर्ग महिला के साथ होती है, हमें इसकी रूट कॉज पर जाना होगा। वो है पेरेंट्स की upbringing या परवरिश। अगर वो बचपन से ही अपने बेटों को अच्छे संस्कार देंगे, बेटी या हर महिला का सम्मान करना सिखायेंगे तो मुझे नहीं लगता कि समाज में इस तरह की घटनाएं जन्म लेंगी, कम से कम परसेंटेज तो बहुत कम होगी। और इतनी ही रिस्पांसिबिलिटी स्कूल और कॉलेजिस की भी है जो अच्छी शिक्षा देने के साथ-साथ उनका मोरल कैरेक्टर भी shape करे हैं क्योंकि कानून, पुलिस, सरकार तो बाद में आती है कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया क्योंकि इसके मूल कारण जो जड़ है बीमारी की जड़ में जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी हमें पता चलेगा और तभी सही अर्थों में हमारा देश आजाद होगा। जय हिंद, जय भारत। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। राजकुमारी जी।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लोंः माननीय अध्यक्षा, आपने मुझे मणिपुर जैसे राज्य पर बोलने का मौका दिया, मेरे से पूर्व काफी वक्ताओं ने, मेरी बहनों ने अपनी जो एक अंदर से ज्वलंत आवाज निकल रही थी उन्होंने विस्तार से बोला। महोदय मणिपुर संप्रदायिक हिंसा, हिंसा के चलते महिलाओं को निर्वस्त्र करके सरेआम घुमाना, गैंग रेप,

सैंकड़ों लोगों का घायल हो जाना, हजारों की संख्या में घरों से पलायन कर जाना, सैंकड़ों लोगों की जान चले जाना ऐसी स्थिति में आज ये देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। आज तक आजादी से पहले और आजादी के बाद नारी पर इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ था जिसके बारे में सोचकर सर शर्म के मारे झुक जाता है। अब तो शर्म शब्द के मायने का भी कोई महत्व नहीं रह गया है। 'बहुत हुआ नारी पर वार अब की बार मोदी सरकार'। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,' नारों के साथ इस देश के प्रधानमंत्री सत्ता में आए और आज नारे लगाने वालों के राज में महिलाओं का अध्यक्षा जी इतना अपमान, अध्यक्षा जी तीन मई 2023 को दो महिलाओं को मणिपुर में निर्वस्त्र कर घुमाया गया और फिर गैंग रेप किया गया एक ट्विटर अकाउंट पर जब एक गैंग रेप की घटना की वीडियो वायरल हो रही थी तब आम आदमी पार्टी ने भाजपा की केन्द्र सरकार को आड़े हाथों लिया। मोदी सरकार ने घटना को दबाने के लिए वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी, इसके बाद भी केन्द्र सरकार इस घटना को सामने आने से रोक नहीं पाईं लेकिन जिस ट्विटर अकाउंट ने यह सच्चाई देश के सामने रखी उस अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया। वीडिओ में चेहरे साफ दिखाई देने के बावजूद मणिपुर पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर करती है। पीएम साहब 77 दिन के बाद जन आक्रोश का इंतजार कर रहे थे। अब समझ नहीं आता कि वे पीड़िता को कैसे न्याय दिलवाएंगे। केन्द्रिय मंत्री रंजन सिंह जो कि

राजकुमार ने अपने घर जलने के बाद कहा कि राज्य की भाजपा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में किल रही है। मणिपुर के दो इलैक्टिड एमपी बता रहे थे कि संसद सत्र में मणिपुर के हालातों पर हमने बोलने की अनुमति मांगी लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली क्योंकि यदि वो मणिपुर के हालातों के बारे में संसद में अपनी आवाज उठाते तो उनका गला दाब दिया जाता और जिस प्रकार हमारे राज्यसभा सांसद, हमारे लोकसभा सांसद को बाहर निकाल दिया, उनकी भी हालत यही होनी थी। प्रधानमंत्री जी ने संसद में ढाई घंटे अपना भाषण दिया लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है सिर्फ मुश्किल से दो या तीन मिनट के लिए मणिपुर जल रहा था उसके बारे में उन्होंने अपनी बातों को रखा। कुछ समय मणिपुर के हालातों पर बोलते तो कुछ तो महिलाओं को लगता कि प्रधानमंत्री जी की संवेदनाएं महिलाओं के साथ हैं। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। महिलाओं के प्रति उनकी क्या संवेदनशीलता है वह दर्शाती है। आप चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री बदल देते हैं लेकिन इतनी शर्मनाक घटना घटने के बाद भी डबल इंजन की सरकार मणिपुर का मुख्यमंत्री नहीं बदला। किसी भी देश और प्रदेश में महिला सशक्तिकरण केवल सुशासन के जरिए लाया जा सकता है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का ऐसा मानना था। मैं महिला व विकास मंत्री सुश्री स्मृति इरानी जी से आज पूछना चाहूंगी कि आप भी एक महिला हैं, देश की मंत्री हैं,आपका कर्तव्य नहीं बनता था कि मणिपुर जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर आउं, उनका दर्द सुनुं।

देश की महिला आयोग की अध्यक्षा का फर्ज नहीं बनता था मणिपुर जाने का। हमारी दिल्ली की महिलाओं की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी परिवार से मिलकर आ सकती हैं लेकिन इनके पास समय नहीं है, खासतौर से मैं पूछना चाहती हूं स्मृति इरानी जी से जो संसद में इतने जोर शोर से अपनी आवाज को उठाती हैं, इतना धमकाती हैं..

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट कीजिए मैडम।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लोंः मैं उनसे पूछना चाहती हूं। बृजभूषण जनता पार्टी ने देश की होनहार खिलाड़ियों को तपती गर्मी में जंतर मंतर पर खूब रूलाया। देश देख रहा है किसी ने ना सुनी बृजभूषण जनता पार्टी ने पिछले नौ सालों में केवल यह बताया है कि महिलाओं को कैसे और किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कब तक घर आ जाना चाहिए। हाथरस में हुए बलात्कार को अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया। भाजपा के आईटी सैल के लोग लगातार भद्दी गालियां दे रहे हैं। भाजपा तालिबान को आर्थिक मदद दे रही है। सत्ता के लालच में ये लोग दिल्ली को अपना गुलाम बनाने के लिए एक चुनी हुई सरकार को मजबूर करने के लिए संसद में बिल तो ले आते हैं लेकिन मणिपुर और हरियाणा जैसी घटनाओं पर मौन साधो रहते हैं। जब महिलाओं का चीर हरण होता है तो उनकी राज्य की सरकार चुप, केन्द्र में बैठे राजा की इतनी भी हिम्मत नहीं कि उस अपराधी सरकार को बर्खास्त करें, अरे उस सरकार के हाथ सैकड़ों लोगों के खून से रंगे गए मौतों का

जिम्मेवार कौन है, हजारों लोग बेघर होने का जिम्मेदार कौन है? इस सरकार में अब इतनी भी नैतिकता नहीं है कि कम से कम इतना मान सके कि हां केन्द्र और मणिपुर की राज्य सरकार वहां हिंसा रोकने में किल रही है। इस देश में पहली बार ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि जब एक पुलिस वाला अपनी ही सेना के जवान पर हाथ उठाने को तैयार है। इतना सब कुछ होने पर भी आप कहते हैं कि मणिपुर में शांति है। मणिपुर के लोग खतरे में हैं, राज्य में अपने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए हर टाइप के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

माननीया अध्यक्ष: मैडम कंपलीट कीजिए।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों: बिल्कुल। आगामी चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में वे ही आएंगे और भारत का विश्व के टॉप तीन में लेकर आएंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि कैसे? क्या ऐसे अलग अलग राज्यों में जातीय हिंसा से दो धार्मो को आपस में बांट कर, विपक्ष को कमजोर करकर, विपक्ष को इडी, सीबीआई का डर दिखाकर, देश में मंहगाई की मार कर कर, बेराजगारी कर कर, देश में घोटालों को दबा कर, विपक्ष यदि संसद् में देश को सच्चाई बताए तो उनको बाहर कर के, क्या ऐसे देश विश्व में टॉप थ्री की लिस्ट में आएगा? महोदया भविष्य किसी ने नहीं देखा लेकिन सोचना बुरी बात नहीं है। परंतु आज क्या हो रहा है, ध्यान ना देना कहां की समझदारी है। उपरोक्त सभी तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि

मणिपुर ही नहीं अन्य राज्यों में भी हालत खराब हैं। मान्यवर एक कहावत है कि कबूतर के आंख बंद करने से खतरा टल नहीं जाता। आज हमारी केन्द्र और मणिपुर की राज्य की सरकारें इनका भी यही हाल है। मैं हर दिल अजीज, पढ़े लिखे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहती हूं कि वे धार्मवाद, जातिवाद के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखें हम सब देशवासी आपके साथ हैं। जय हिंद जय भारत।

माननीया अध्यक्षः राजकुमार आनंद जी।

श्री राजकुमार आनंदः अध्यक्ष महोदया, परसों हमने आजादी की 77 वीं सालगिरह मनाई और उस आजादी को पाने के लिए हमारे लाखों वीर सपूतों ने, मां भारती के लाखों वीर सपूतों ने अपनी जानें गवाईं। जब वो अपनी जानें गवां रहे थे तो उन्होंने कभी ये सोचकर अपनी जानें गवाई थीं कि हमारी शहाद्त एक ऐसा देश बनाएगी जिसमें भाईचारा होगा, अमन होगा, शांति होगी, मां बहनों का सम्मान होगा लेकिन अध्यक्ष महोदया, पिछले दिनों मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वह मानवता को शर्मसार करने वाला था। वह शहीदों के भरोसे को तोड़ने वाला था। अध्यक्ष महोदया, आज मणिपुर की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं उसे देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति सामान्य नहीं रह सकता। मणिपुर की सड़कों पर औरतों को नंगा करके परेड कराई जाती है। उनके साथ बलात्कार किए गए हैं। भारी संख्या में लोगों के कत्लेआम हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे तक मारे गए हैं। अध्यक्ष महोदया, मणिपुर में

इंसानियत कराह रही है। मानवता तार तार हो रही है। मुझे तो लगता है कि वहां जो हिंसा चल रही है वो सब भाजपा प्रायोजित है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी खामोश रहे। प्रधानमंत्री जी की ये खामोशी देश और देशवासियों के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाती है, क्रूरता को दर्शाती है। अध्यक्ष महोदया, मणिपुर के मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि आप राज्य में हो रही हिंसा पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो मणिपुर के निकम्मे सीएम का जवाब था कि सैंकड़ो जगह पर हिंसा हो रही है मैं कैसे और किस किस पर कार्रवाई करूं। इस बयान से दो बातों का पता चलता है अध्यक्ष महोदया। पहला, मणिपुर के सीएम किस कदर अमानवीय और संवेदनहीन व्यक्ति हैं और दूसरा मणिपुर की हिंसा कितनी भयावह थी। सौ दिन की चुप्पी के बाद, तीन महीने की चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्रोधा है, पीड़ा है। अध्यक्ष महोदया, मैं बताता हूं कि जब मणिपुर जल रहा था तब केन्द्र में बैठी मोदी सरकार क्या कर रही थी। तब मोदी सरकार एक दिल्ली वालों के खिलाफ एक बिल बना रही थी एक ऐसा बिल जो दिल्ली के लोगों के वोट का अपमान करता है और जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को पंगु बनाता है। अध्यक्ष महोदया, जब मणिपुर जल रहा था तब मोदी सरकार राज्यों की गैर भाजपा सरकारों और पार्टियों को तोड़ने में लगी थी और विदेशों में राजनीतिक तफरियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री विदेशों में राजनीतिक तफरियां कर रहे थे। अध्यक्ष महोदया, ये वही मोदी जी हैं जिनकी छाती का साइज 56 इंची बताया जाता है।

कहां थी वो 56 इंच की छाती जब मणिपुर के बच्चों, बूढ़ों और औरतों के उपर अत्याचार, हिंसा और बलात्कार किए जा रहे थे। मोदी जी आपके 56 इंची की छाती की ताकत सिर्फ विपक्षी पार्टियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ ही काम करती है और अगर कहीं काम करती है तो आपके 56 इंच की छाती की ताकत आपके पूंजीपति दोस्तों की मदद करने का काम करती है। अध्यक्ष महोदया, भाजपा अपने काम के आधार पर सत्ता में नहीं आना चाहती बल्कि नफरत और लड़ाई झगड़े के जरिए सत्ता पर काबिज होना चाहती है इसलिए वे कभी हिंदु मुस्लिम के नाम पर झगड़े कराते हैं, कभी सिख हिंदू के नाम पर झगड़े कराते हैं और जब धार्मों का झगड़ा खत्म हो जाता है तो दो जातियों के बीच नफरत पैदा कराते हैं। वे जाट और गैर जाटों को लड़वाते हैं। वे कूकी, मैतई आदिवासी समुदायों के बीच में झगड़े करवाते हैं। अध्यक्ष महोदया, भाजपा का मकसद नफरत और हिंसा फेलाकर इस देश की सत्ता को एक बार फिर से हासिल करना है ताकि देश वासियों का ध्यान विकास के कामों की तरफ ना जाए। इसलिए मेरी इस सदन के माध्यम से देश के लोगों से गुजारिश है, अपील है कि भाजपा की असलियत को पहचानिए। जब तक ये सत्ता में रहेंगे, इस देश का ना तो विकास हो सकता है, ना ही सौहार्द स्थापित हो सकता है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सकता, मंहगाई से छुटकारा नहीं मिल सकता, किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल सकता, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती,

हर आम-ओ-खास को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल सकती और सबसे बड़ी बात, भाजपा के सत्ता में रहते यह देश बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से नहीं चल सकता। दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा।

'तुमसे पहले वो एक शख्स यहां तख्त नशीं था,

उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था'

बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।

माननीया अध्यक्षः माननीय मंत्री गोपाल राय जी।

श्री गोपाल रायः माननीय अध्यक्ष महोदया, सदन मणिपुर के अंदर जो असहनीय पीड़ा देने वाली अमानवीय घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के चर्चा कर रहा है। लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि आज इस सदन के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये कहते हुए सार्वजनिक तौर पर सुना कि मणिपुर कोई मायने नहीं रखता। ये कौन लोग हैं? राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव की फसल काटने वाले। आज मणिपुर जल रहा है, दर्द से कराह रहा है। अध्यक्ष महोदया, पिछले सौ दिनों से मणिपुर के अंदर किसी को नहीं पता कि किसके बेटे को कौन मार देगा, किसी को नहीं पता चाहे वो मैत्रैयी समाज के लोग हों, चाहे कुकी समाज के लोग हों, किसी को नहीं पता कि किसकी बहन कब किसी के हवस की शिकार हो जाएगी, किसी को नहीं पता की उसका कब आशियां

जला दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे लिए मायने नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं और वो खुद नहीं कह रहे, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह से सदन के अंदर, संसद के अंदर मणिपुर के चर्चा के दौरान सदन में प्रवेश करने से डरते रहे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें डर लग रहा है, मणिपुर पर मुँह खुलेगा तो क्या हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से डायरेक्शन आया, भाजपा के विधायकों को कि सदन के अंदर मणिपुर पर चर्चा हो तो बाहर चले जाओ। भाजपा का प्रधानमंत्री संसद के अंदर मणिपुर पर चर्चा करने से, आने से डरता है और सदन के अंदर विधायकों को भाग जाने के लिए कहता है। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि पूरा मणिपुर सौ दिनों से जल रहा है। कौन सी घटना नहीं हुई दरिंदगी की मणिपुर के अंदर, जो भारतीय समाज में हुई हो। अध्यक्ष महोदया अंग्रेजों की भी ये हिम्मत नहीं थी कि जो मणिपुर के अंदर घटित हुआ, भारत के किसी हिस्से में कर दे। ये कह रहे हैं कि मणिपुर का मुद्दा तो बाहरी है, दिल्ली के सदन को, दिल्ली के लोगों को उससे क्या लेना-देना है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली का दिल हर उस बात पर धड़कता है, ये आपका चेयर इस बात का गवाह है, अगर कश्मीर के अंदर भी कुछ होता है, हम इसी चेयर से उसकी भी निंदा करते हैं। अगर देश के लिए कोई कुछ करता है तो उनको सलाम करते हैं। आज कह रहे हैं कि मणिपुर का मुद्दा बाहरी मुद्दा हो गया। अध्यक्षा

महोदय, मैं आपको इस सदन के माध्यम से सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई के दौरान 1905 में जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मॉडल ऑफ मणिपुर तैयार किया है, कैसे डबल इंजन की सरकार, सारी तामझाम, सारे सरकारी महकमें को लेकर के किसी समाज को, किसी राज्य को धूं-धूं जला सकती है। कैसे तबाह कर सकती है, इसका एक मॉडल भाजपा ने मणिपुर के अंदर तैयार किया। अंग्रेजो ने भी एक मॉडल खड़ा किया था अध्यक्ष महोदय। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया इसी तरह से। जिस तरह से बुनियाद रखी गई है मणिपुर के अंदर, मैत्रेयी और कुकी समाज के बीच में आपसी कलह पैदा करके, आपसी आग लगाकर के बंटवारे की, उसी तरह से अंग्रेजों ने 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन किया, हिन्दु और मुस्लिम का झगड़ा पैदा किया और उस झगड़े के आधार पर हिन्दु बंगाल और मुस्लिम बंगाल 1905 में विभाजित कर दिया। अध्यक्ष महोदय मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं राष्ट्रवाद की बात करना अलग बात है और राष्ट्र को सीने में लेकर के जीना अलग बात है। तुम्हारी जुबॉ पर राष्ट्र रहता है, भारत के लोगों के दिलों में राष्ट्र रहता है, इसलिए कल भी भारत जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। अध्यक्ष महोदया, अंग्रेजों ने बंगाल में आग लगाई थी, बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ लड़ा कौन, आवाज उठी बाल-लाल-पाल की। आवाज उठी

लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय बंगाल के नहीं थे, लाहौर के थे। बाल गंगाधार तिलक बंगाल के नहीं थे, महाराष्ट्र के थे, विपिन चंद पाल बंगाल के थे, लाल–पाल की जोड़ी ने पूरे देश के अंदर एक जागृती पैदा की। अंग्रेजों के उस विभाजन, उस नफरत को धवस्त किया और इतना बड़ा ये आंदोलन देश के अंदर, इतनी बड़ी आवाज देश के अंदर खड़ी हुई, अंग्रेजों को उसी बंगाल विभाजन के बाद कलकत्ते से राजधानी लेकर के दिल्ली भाग कर के आना पड़ा था। अध्यक्ष महोदया मणिपुर का दर्द, मणिपुर का दर्द नहीं है, मणिपुर की बहनों का दर्द, मणिपुर का नहीं है पूरे भारत की बहनों का दर्द है। मणिपुर के अंदर जो आग लगाई जा रही है पूरे भारत के अंदर आग लगाई जा रही है लोगों के दिलों में। मणिपुर के अंदर अगर आज घर जलाए जा रहे हैं, आज एक वो बानगी है, एक मॉडल खड़ा किया जा रहा है। आज उसका कारण क्या है? आज पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आर्थिक तौर पर पूरी तरह से किल हो चुकी है। राजनैतिक तौर पर किल हो चुकी है, वो इस बात को सोचते थे कि इस देश के अंदर ईडी और सीबीआई के दम पर विपक्ष की आवाज को कुचल देंगे, एक–एक नेताओं को हम जेल में बंद कर देंगे। लोगों की आवाज को बंद कर देंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, दमन जितना ही बढ़ता है, आवाज उतनी ही मजबूत होती है। र्ब्फ की सिल्लियों पर लिटाकर के, कोड़े बिठाने से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं चुप हुई, तो आज तुम्हारे सीबीआई, ईडी से

कैसे चुप हो जाएगी। ज्यों-ज्यों दमन बढ़ा है, देश खड़ा हो रहा है। पूरे देश के अंदर, उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम से आवाज उठ रही है। बदलाव की ऊंची आवाज उठ रही है और वो आवाज आंधी बन जाए इसके लिए तैयारी हो रही है। अध्यक्ष महोदया, आज भारतीय जनता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से डरते हैं, मैं इस सदन को आगाह करना चाहता हूं, मणिपुर में जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, आज अगर मणिपुर जल रहा है, नरेंद्र मोदी उस आग को ठंड़ा करने के काबिल नहीं है। तो कल देश अगर इस हालात में पहुंचता है, ये प्रधानमंत्री देश को बचा नहीं सकता। इसलिए देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि जो लोग इस मुल्क से मुहोब्बत करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री की विदाई की तैयारी करें। अगर उसके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है तो अब देश की कुर्सी पर ऐसे प्रधानमंत्री के लिए रहने का भी समय नहीं है। इसलिए अगर मणिपुर के साथ हो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अगर मणिपुर के दर्द के साथ हो तो ऐसे निर्दयी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना पड़ेगा, अगर आप मणिपुर की महिलाओं के साथ हो तो महिलाओं के दर्द को, अपमान को, इस तरह से निर्लजता के साथ, टुकुर-टुकुर देखने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर इस देश के लोगों के दर्द को नहीं बर्दाश्त करता, तो अब ये देश प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसी आवाज के साथ हमें आवाज उठानी होगी, थैंक्यू बहुत-बहुत शुक्रिया।

माननीया अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी।

माननीय मुख्यमंत्रीः आदरणीय अध्यक्षा महोदया, आज हम सब लोग यहां पर मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं। एक तो मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घटी वो बेहद दर्दनाक हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज जो कह कर यहां से सदन छोड़कर बाहर चले गए और बाहर जाकर चैनलों पर बाइट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना-देना नहीं है। मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। मैं ये सोच रहा था, ये सारे चैनलों पर भी चल रहा है, सारे चैनलों पर चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो विधान सभा छोड़ कर ये कहकर चले गए कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना-देना नहीं है, मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। पूरे देश में इस टाइम टीवी चैनलों पर ये चल रहा है और मणिपुर के लोग भी ये देख रहे होंगे। और जब मणिपुर के लोग ये देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए विधायक, दिल्ली के विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक साफ-साफ ये कह रहे हैं कि मणिपुर से उनको कोई लेना-देना नहीं है, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। अध्यक्षा महोदया, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक नहीं कह रहे, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी इनकी सारी सरकारें और उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि मणिपुर से उनका कोई लेना-देना नहीं है। जब से मणिपुर की घटना घटी है प्रधानमंत्री

जी चुप हैं। मणिपुर के अंदर 65 सौ एफआईआर हो गई, 90 दिन के अंदर, 3 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में 65 सौ एफआईआर हो गईं प्रधानमंत्री जी चुप रहे। मणिपुर में 4 हजार लोगों के घर जला दिये गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 60 हजार लोग बेघर हो गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। साढ़े तीन सौ धार्मिक स्थल जला दिए गए प्रधानमंत्री जी चुप रहे। केंद्रीय ंोर्सिज, आसाम राइफल्ज और मणिपुर पुलिस के बीच में खुलेआम झगड़ा हो गया और गोलाबारी हो गई जो आज तक भारत में कभी नहीं हुई कि सैंट्रल फोर्सिज और लोकल पुलिस के बीच में झगड़ा हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर भारत की थू-थू हो रही है, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर इस पर चर्चा हुईं अमेरिका के अंदर इसपर चर्चा हुई वहां के नेताओं ने इसकी थू-थू की। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चुप रहे कुछ नहीं बोले और एक दिन जब एक विडियो चारो तरफ सर्कुलेट हुआ, जिसमें हमारी दो या तीन बहनों को निर्वस्त्र करके, सड़क के ऊपर घुमाया गया और उनके साथ खुलेआम सरेआम कई लोगों ने मिलकर गलत काम किया, तब भी प्रधानमंत्री जी चुप रहे। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये कोई आइसोलेटिड इन्सीडेंट नहीं है यहां तो ये रोज ही हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री एक पिता के समान होता है सबके लिए। वो जो बेटियॉं जिनके साथ ये गलत काम किया जा रहा था, या जितनी इतनी बेटियों के साथ उनके मुख्यमंत्री का बिरेन सिंह का कहना है कि ये तो रोज

हो रहा है यहां पर। लोग प्रधानमंत्री को रोज याद नहीं करते, आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी, घर में पानी नहीं आ रहा है तो लोग प्रधानमंत्री को याद नहीं करते, प्रधानमंत्री को याद तब करते हैं जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब आदमी याद करता है यार मेरा प्रधानमंत्री मेरे को बचाएगा। उन महिलाओं के लिए तो सब कुछ फेल हो गया था जिनको निर्वस्त्र करके वहां पर खुलेआम सड़कों पर घुमाया गया और खुलेआम उनके साथ गलत काम किया गया।

वो तो बेटियां हैं हमारे देश की, वो तो प्रधानमंत्री जी की उम्र के हिसाब से वो तो उनके पिता समान हैं। पोजीशन के हिसाब से भी उम्र के हिसाब से भी प्रधानमंत्री तो उनके पिता समान हैं और जिस दिन अगर बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही है और बाप कहे कि मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है तो बेटियां कहां जाएंगी। बाप अगर ऐसे मौके पर मुंह मोड़ ले तो बेटियां कहां जाएंगी। मैं देख रहा था एक रिटायर्ड आर्मी आफिसर जो मणिपुर का रहने वाला है उसका एक वीडियो सर्कूलेट हो रहा था। वो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त होता था, अंधा भक्त होता था, उसका पिछला ट्वीटर अकाउंट उठाके देखो उसने मोदी जी के लिए अंधीभक्ति में पिछले कई सालों से खूब ट्वीट किये हुए हैं। वो रो रहा था उस वीडियों में और रोते हुए कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी मैंने नहीं सोचा था कि आप हमें इस तरह से धोखा देंगे। मैंने नहीं सोचा था कि आप हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे, आप हमें हमारे हाल पर इस तरह से छोड़ देंगे। ये सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं

कि ये अकेला प्रधानमंत्री आज जो पिछले 9 साल में 50 बार नॉर्थ-ईस्ट गया था। अध्यक्षा महोदया, हमारा कोई रिश्तेदार हमारी खुशी के मौके पर तो रोज जाए लेकिन जिस दिन मुसीबत हो उस दिन मुंह मोड़ ले, तो आदमी का असली दोस्त तो वही होता है न जो मुसीबत में काम आता है, असली साथी वो थोड़ी होता है जो कि शादी ब्याह में। तो जब हमारे घर में मुसीबत आई, जब मणिपुर के अंदर मुसीबत आई, जब मणिपुर जल रहा था, लोग मर रहे थे, लोगों के घर जलाये जा रहे थे, महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा था तब आपको सुध नहीं आई, तब आप अपने कमरे के अंदर कुंडी मारकर बैठ गये। पूरा देश इस टाइम स्तब्धा है और पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है। प्रधानमंत्री न कुछ कर रहे हैं और न कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है ये पूरे देश के अंदर इस वक्त चर्चा का विषय है और यह पहली बार नहीं है, पिछले 9 साल के अंदर जब-जब इस देश के ऊपर आपदा आई, जब-जब इस देश के अंदर कोई आपदा आई, ये प्रधानमंत्री चुप हो गये, अपने कमरे में जाकर अंदर कुंडी मारकर बैठ गये। ये प्रधानमंत्री मैदान छोड़कर भाग गये, ये प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं दिये, लोग चिल्लाते रहे। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को याद है जंतर-मंतर के ऊपर हमारी महिला पहलवान जंतर-मंतर के ऊपर बैठी थीं उनके आरोप थे कि उनके साथ कुश्ती फेडरेशन के प्रेसीडेंट ब्रजभूषण सिंह ने उनके साथ छेड़खानी की है और उनके साथ गलत हरकतें की

हैं। यही महिला पहलवान जब मैडल जीतकर आई थी ओलंपिक के अंदर तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले फोटो खिंचवाने पहुंच गये थे और वो वीडियो भी देखा मैंने जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों को कहा बेटा तुम मेरी बेटियों के समान हो, कल को कोई दिक्कत हो तुम मेरे पास आ जाना। जब उन महिला पहलवानों ने कहा कि पिताजी हमारे साथ गड़बड़ हो गई, हमारे साथ बदसलूकी हो गई, तो प्रधानमंत्री जी चुप हो गये। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साधा ली। कम से कम इतना तो कह देते प्रधानमंत्री जी अगर इतना ही कह देते की बेटा चिंता न करो मैं हूं, मैं जांच कराउंगा, दोषियों को सजा दिलवाउंगा, कम से कम लोगों को संतुष्टि तो मिल जाती कि प्रधानमंत्री है। मणिपुर के केस में कम से कम इतना ही कह देते मणिपुर के लोगों को, एक शांति की अपील ही कर देते प्रधानमंत्री कि मैं मणिपुर के लोगों से शांति की अपील करता हूं कि कृपया हिंसा मत कीजिए। शांति की अपील तक नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री, कमरे में कुंडी मारकर बैठ जाते हैं। जब ये महिला पहलवान थी महिला पहलवानों को एक अपील कर देते, वो तो बेचारी केवल प्रधानमंत्री से दो शब्द सुनने के लिए बेताब थी। अगर वो कह देते कि बेटा चिंता न करो जिसने भी तुम्हारे साथ गड़बड़ की है मैं उनको बख्शुंगा नहीं। उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इन बेचारी महिला पहलवानों को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे। जब चाइना पिछले 9 साल से चाइना हमें आंख दिखा

रहा है, जब देखो चाइना हमें आंख दिखा रहा है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह बंद हैं, प्रधानमंत्री जी के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकलता इस प्रधानमंत्री के मुंह से। मेरे को याद है अक्टूबर 2019 में चाइना के राष्ट्रपति इंडिया आए और इंडिया के अंदर तमिलनाडू में महाबलेश्वर में दोनों हाथ में हाथ मिलाकर चाइना के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री हाथ में हाथ मिलाकर महाबलिपुरम के मंदिर में घूम रहे थे, उसके फोटो खींचे गये अक्टूबर 2019 और 15 जून 2020 को चाइना की फौजों ने गलवान घाटी पर हमारे ऊपर हमला करके हमारे 20 सैनिकों को मौत के घाट पहुंचा दिया। 2 हजार स्क्वेयर किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया 2 हजार स्क्वेयर किलोमीटर मतलब दिल्ली 14 सौ स्क्वेयर किलोमीटर है दिल्ली से डेढ़ गुना इलाका चाइना की फोर्सेज ने कब्जा कर लिया, हमारा प्रधानमंत्री जी चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अफवाहें हैं, लेह के कई लोगों का दावा है, अफवाहें हैं की 2 हजार स्क्वेयर किलोमीटर जो इन्होंने हमारा कब्जा किया है अंडरहैंड डीलिंग करके कोई चुपके से डील हुई है और शायद इन्होंने ये उनको दे दिया है, उनसे संधि। अध्यक्षा महोदय, सबसे शर्मनाक बयान अभी फरवरी के महीने में हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का आया। उन्होंने कहा they are the bigger economy चाइना हमसे बड़ी इकॉनमी है what I am going to do ? मैं क्या करूं? हद है यार! हमारे देश का विदेश मंत्री कहता है मैं क्या करूं as a smaller economy I am going to pick up a fight with the

bigger economy. It is not a question of being reactionary, it is a question of common sense.ये हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी के अफसरों ने लिखा एक मेजर जनरल शैल झा हैं उन्होंने ट्वीट किया Mr. Jai Shankar should know that it is not India but China which is picking up the fight. Economy or no economy if we bow down to a bully, we are abandoning our self resepct. Is it acceptable? what a shame, it is cowardish! अध्यक्षा महोदया, ये लोग पानी पी–पीकर जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते हैं, कम से कम उस जवाहरलाल नेहरू ने चायना की आंखों में आंखें डालकर उनके साथ युद्ध तो किया था, इन्होंने तो देश को सरेंडर कर दिया चायना के सामने और उन्होंने हमारे उपर हमला किया, हमारे 2 हजार स्क्वेयर किलोमीटर एरिया को ले लिया, इन्होंने बदले में चायना को ईनाम दिया। 2018–19 में चायना के साथ हमारा ट्रेड हमारा व्यापार 87 बिलियन डालर्स का था उसको डेढ़ गुना करके 22–23 में ये 114 बिलियन डालर का व्यापार हो गया। मैं आज देश के लोगों से पूछना चाहता हूं आपको धंधा करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, आपको बिजनेसमैन प्रधानमंत्री चाहिए या देश की रक्षा और देश का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री देश को चाहिए। सब लोग यह जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। अगर हम एक ही काम कर देते इसमें डरने की क्या बात थी हम चायना से इतना माल इंपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ इंपोर्ट करना बंद कर देते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं आंख

दिखाने की हिम्मत तो दिखाओ, हाथ में हाथ डालकर मंदिर में घुमने से इश्क होता है कूटनीति नहीं होती, डिप्लोमेसी नहीं होती। डिप्लोमेसी करने के लिए तो आपको आंखें दिखानी पड़ती है। अडानी का घोटाला हुआ, एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई जनवरी के महीने में जिसने पूरे देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी, दुनिया का सबसे तीसरे नंबर पर अमीर आदमी था तीसरे नंबर पर सबसे अमीर आदमी अचानक जो है उसकी और पूरा बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज तहस-नहस हो गया, लाखों लोग इनवेस्टर्स लाखों इनवेस्टर्स का पैसा डूब गया, एलआईसी का पैसा डूब गया, बैंकों का पैसा डूब गया, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अरे एक बार बाहर आकर इतना ही कह देते मैं जांच कराउंगा, दोषियों को सजा दूंगा, ये तो कह देते। एक ट्वीट ही कर देते कि मैं दोषियों को सजा दूंगा, जांच कराउंगा, जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, जिन लोगों ने फ्रॉड किया उनको मैं बख्शुंगा नहीं, इतना ही कह देते। प्रध ानमंत्री जी चुप रहे तो अब लोगों को लगने लगा यार अडानी का पैसा तो सारा मोदी का पैसा है, मोदी चुप क्यों है, मोदी बोलता क्यों नहीं है, मोदी बचा क्यों रहा है उसको। तो लोगों को लगने लगा यार ये सारा पैसा जो है ये मोदी का पैसा है, जनता जानना चाहती है असलियत क्या है। अगर प्रधानमंत्री चुप हो जाएगा और कुछ बोलेगा नही ंतो अफवाहों का बाजार गर्म होता है, चारों तरफ अफवाहें ही अफवाहें फेलती है और देश के लिए अच्छी बात नहीं हैं अगर चारों तरफ अफवाहें फेलें, इस तरह से तो। इनके समय में

पिछले 9 साल में 13 लाख करोड़ रुपये के बैंकों के कर्जे कुछ चंद अमीर लोगों के माफ कर दिये गये। इन्होंने नीरव मोदी को भगा दिया, इन्होंने मेहुल चौकसी को भगा दिया, ललित मोदी को भगा दिया, विजय माल्या को भगा दिया, वो क्या कहते हैं जो क्या नोटिस होता है जो बाहर जाने से रोकने के लिए.. वो मनीष के खिलाफ करा इन्होंने।..

माननीया अध्यक्षः लुक आउट।

माननीय मुख्य मंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): लुक आउट नोटिस, नहीं लुक आउट भी नहीं होता कुछ नोटिस होता है। भई तुमने मनीष के खिलाफ वो नोटिस कर दिया यार थोड़ा नीरव मोदी के खिलाफ भी वो नोटिस कर देते वो यूं ही भाग गया वो एयरपोर्ट से बैठकर। वो कोई वेश बदल कर तो गया नहीं। नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया। ये यूं ही भाग गये, ये भगाये गये, भगाये गये। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी आपका इनसे क्या रिश्ता है, क्या डील है आपकी इनसे, ऐसे ही थोड़े भाग गये सारे के सारे। अभी-अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई है 16 हजार बिल्कुल डिफाल्टर, विल्फुल डिफाल्टर का मतलब होता है जिनके पास पैसे हैं जानबूझकर नहीं दे रहे। एक तो है भई कोई बैंकरप्ट हो गया उसके पास पैसे ही नहीं हैं, धंधा चौपट हो गया, एक है विल्फुल डिफाल्टर, विल्फुल डिफाल्टर वो होते हैं जिनके पास पैसे हैं नीयत नहीं है, वो दे नहीं रहे। आरबीआई कह रही है 16 हजार विल्फुल डिफाल्टर हैं जो नहीं दे

रहे। तो क्यों नहीं दे रहे? उनको जेल में नहीं डालते, उन पर ईडी-ईडी नहीं करते उन पर सीबीआई नहीं करते। तो प्रधानमंत्री जी से पूछना तो चाहते हैं लोग कि भई आपका क्या है, उनके साथ क्या डील हो रही है ये। जनता पूछना तो चाहती है ये क्या अंदरखाने चल क्या रहा है, ये 16 हजार विल्फुल डिफाल्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? बोलें तो सही, कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री जी। आपके केन्द्रीय मंत्री के जब किसान आंदोलन चल रहा था केन्द्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी में जीप चढ़ा दी, वीडियो है सबके सामने, उसका सबूत है सबके सामने, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। हमारे किसान भी प्रधानमंत्री जी के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं सरेआम जीप ने उनको कुचल दिया, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 14 सितंबर 2020 को हाथरस में एक दलित बेटी के साथ 19 साल की दलित बेटी के साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप किया, प्रधानमंत्री जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले और अभी हरियाणा के अंदर पहले नूंह में और उसके बाद सोहना में और फिर गुड़गांवां के अंदर सरेआम दो समुदायों के बीच में हिंसा हुई, पूरी दुनिया के अंदर थू-थू हुई, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने फलांने-फलांने उन्होंने दो-तीन नेताओं का नाम लिया फलांने नेताओं ने 17 हजार करोड़ रुपये का घोटाला कर दिया, 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो जनता जानना चाहती है जी 3 दिन के अंदर उस घोटाले का क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी चुप

रहे। अभी किसी ने सीएजी की रिपोर्ट आई है कि 18 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर की सड़क को 250 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर की सड़क पर बना दिया, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तो अब देश के अंदर चारों तरफ चर्चा हो रही है क्या मोदी जी एक कमजोर, अहंकारी और भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। आज ये सदन प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता है कि बाकी बातें बाद में हो जाएंगी मणिपुर को संभाल लीजिए, कुछ तो कहिये, कुछ तो करिये।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद, अब सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 18 अगस्त, 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 18 अगस्त, 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।